(सभापतीस्थानी माननीय उपसभापती)

पृ.शी.: राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था

मु.शी.: राज्यातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था या विषयावर सर्वश्री पांडुरंग फुंडकर, दिवाकर रावते, विनोद तावडे, रामदास कदम, संजय केळकर, डॉ. दीपक सावंत, श्री. केशवराव मानकर, डॉ. नीलम गोऱ्हे, सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, परशुराम उपरकर, पाशा पटेल, किरण पावसकर, अनिल परब यांचा प्रस्ताव

(चर्चा पुढे सुरु)

श्री. सय्यद जमा (महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा निर्वाचित) : सभापति महोदय, माननीय विरोधी पक्ष नेता श्री. फुंडकर जी ने महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 260 के अन्तर्गत राज्य की कायदा व व्यवस्था के बारे में जो प्रस्ताव लाया है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं. हमारे विरोधी पक्ष के साथियों को महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स को क्रिटीसाइज करने के लिए बहुत सारे कारण मिल सकते हैं. हमारा पुलिस फोर्स बहुत बड़ा है और मुंबई शहर हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए बहुत से असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों का ध्यान यहां रहता है. इसलिए उनको क्रिटिसाइज करने के बहुत सारे मुद्दे मिल सकते हैं. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस फोर्स हमारे समाज का एक अंग है और हमारे समाज में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उनका फैलाव पुलिस फोर्स में भी हो रहा है.

सभापति महोदय, पुलिस के मनोबल को बढ़ाना बहुत आवश्यक है. हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ जनता के मन में पुलिस के बारे में विश्वास का स्तर बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है. लेकिन अगर हम छोटी-मोटी बातों को लेकर पुलिस की क्रिटिसाइज करनेंगे, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस में त्रुटियां नहीं है, लेकिन वे जिन विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते हैं, जितनी कठिनाई का कार्य करते हैं, जितने घंटे कार्य करते हैं, उनको जो आर्म्स मिलते हैं और उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, इन सारी बातों को

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

01-04-2010 (असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही) A 2

DGS/ KGS/ KTG/ 11:00

. . . . श्री. सय्यद जमा

ध्यान में रखते हुए हमारे पुलिस फोर्स ने महाराष्ट्र और मुंबई में कठिन समय में जबाबदारी से कार्य निभाया है. कभी-कभी, यहां-वहां ऐसी घटनाएं हो जाती है, जिनसे हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को क्रिटिसाइज करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें तो पुलिस का परफोरमेंस शानदार रहा है. केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पिछले कुछ सालों में जब से आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, पुलिस के आधुनिकीकरण करने के बारे में बहुत सारे कदम उठाए हैं और बहुत सुधार हुआ है. इस साल के बजट में पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान किया गया है. मुंबई पर हुए 26/11 के हमले के बाद सरकार ने 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक हब मुंबई में बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य में हर साल 11 हजार पुलिस बल में भर्ती की जा रही है और एक कमांडो फोर्स बनाया गया है. गडचिरोली जिले में एक पुलिस स्टेशन के 2 भाग किए गए हैं. वहां पर पुलिस की भर्ती की जा रही है और नक्सलवादियों से लड़ने के लिए उनको आधुनिक हथियारों के साथ साथ हेलीकॉप्टर की सेवा भी दी गई है. हमारी सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उनसे आम जनता के मन में पुलिस के बारे में विश्वास बढ़ा है और निश्चित रुप से उनमें सेन्स ऑफ सिक्योरिटी आई है. आज हम देखते हैं कि ओवर पॉपूलेटेड और इकॉनॉमिक हब के रुप में प्रसिद्ध मुंबई शहर में आम जनता के मन में सेन्स ऑफ सिक्योरिटी है. यही कारण है कि हम और आप सुरक्षित महसूस करते हैं. जब हमारे राजनैतिक नेताओं की सुरक्षा की बात आती है तो हम उनके ऊपर ही भरोसा करते है, चाहे भले ही उन्हें सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूमना पड़ता हो.

. . . . भाषण जारी, नंतर तालेवार.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री सय्यद ज़मा ....

जनता की सुरक्षा करते समय हमारे कई पुलिस अधिकारी एवम् पुलिस के जवान शहीद हो गए. 26/11 की घटना में भी हमारे कई पुलिस अधिकारियों एवम् जवानों ने जनता की सुरक्षा करते समय अपने प्राण न्योछावर कर दिए और मुंबई शहर को भी बचाया. जनता में सेंस ऑफ सिक्योरिटी है. इसलिए हम सभी मिलकर पुलिस का मनोबल बढ़ाए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं. मैं महाराष्ट्र की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन, सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले दिनों में सभी लोगों ने मिलकर राज्य में कानून एवम् व्यवस्था बनाए रखी, सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने दिया. इस प्रकार से राज्य में शांति बनाए रखी. सभी लोगों ने जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार किया. इसी लिए हमारे राज्य में सामाजिक तनाव पैदा नहीं हुआ. साम्प्रदायिक तनाव पैदा नहीं हुआ. इस सिलसिले में मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं.

सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली हमारी पुलिस फोर्स में काम करने वाले अधिकारियों एवम् जवानों के काम के घंटे तथा सुविधाओं का भी विचार किया जाना चाहिए. माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि पुलिस जवानों का जो पेमेंट रुका था, वह अब उन्हें मिलेगा. वित्त विभाग से 20-25 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, इसलिए अब पुलिस कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. मेरा यह सुझाव है और सरकार से अनुरोध है कि पुलिस विभाग को सक्षम बनाना है तो उसके लिए आकस्मिक कोष (कॉन्टिन्जन्सि फंड) बनाया जाना चाहिए. 100 से 400 करोड़ रुपये का यह आकस्मिक कोष हो. इस प्रकार का आकस्मिक कोष होगा तो किसी भी इमर्जेंसी की स्थिति में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हम यह जानते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि पुलिस को लगातार कई घंटों तक डयूटी करनी पड़ती है, अपना घर-परिवार छोड़कर डयूटी करनी पड़ती है. इसलिए पुलिस कर्मचारियों को सुविधाएं देने के लिए सरकार के पास आकस्मिक कोष (कॉन्टिन्जन्सि फंड) होना बेहद जरुरी है. यह आकस्मिक कोष होगा तो इस कोष का आपात्कालीन स्थिति में उपयोग हो सकेगा और पुलिस फोर्स भी अपना काम अच्छी प्रकार से कर सकेगी. मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में, राज्य में जब तक शांति और व्यवस्था नहीं रहेगी, तब तक विकास कार्य नहीं हो सकता है. मेरा यह भी सुझाव है कि , जिस प्रकार से कई विभागों में विशेष फंड की व्यवस्था

..........2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री सय्यद ज़मा ....

होती है, जैसे आदिवासी विभाग के अन्तर्गत आदिवासी उप योजना है, स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान है, उसी प्रकार से पुलिस विभाग के लिए अलग से बजट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बजट होना चाहिए. प्लान, नान-प्लान में 5 प्रतिशत कटौती करके पुलिस विभाग के लिए अलग से बजट बनाया जा सकता हो तो इस पर भी विचार किया जाए. अगर पुलिस फोर्स आधुनिक होगी, प्रशिक्षित होगी, आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होगी और सारी आवश्यक सुविधाओं से युक्त होगी तो मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स में विश्वास बढ़ेगा और जनता का भी पुलिस फोर्स के प्रति विश्वास बढ़ेगा. पुलिस विभाग के पास आकस्मिक कोष होगा तो पुलिस के सामने कठिन समस्या पैदा होने की स्थिति में कोष से मदद की जा सकेगी. राज्य को भी अच्छी तरह से सुरक्षित रख सकेंगें. पुलिस ज्यादा सक्षम हो सकेगी. इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी पक्षों के सामने यह बात रखते हुए पुलिस विभाग के लिए आकस्मिक फंड बनाया जाए, अलग से बजट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा फंड दिया जाए ताकि पुलिस फोर्स को अधिक सक्षम किया जा सके.

सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं शांति बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग ने जो सक्षमता दिखाई है, उसके लिए मैं पुलिस विभाग को मुबारकबाद देना चाहता हूं.गृह मंत्री श्री आर.आर. पाटील के बारे में सभी लोग कहते हैं कि वे अच्छे है. सब को उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर गर्व है. सभी को उनके प्रति यह विश्वास है कि महाराष्ट्र में पुलिस फोर्स की रेपिड तरीके से तरक्की होगी. जिस प्रकार से रेपिड एक्शन फोर्स कार्यवाही करता है, उसी प्रकार से वे पुलिस फोर्स की रेपिड तरीके से तरक्की करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है, इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं. धन्यवाद.

....

यानंतर श्रीमती गोऱ्हे यांचे भाषण.

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

डॉ. नीलम गोऱ्हे (महाराष्ट्र विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, काल सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकरजी रावते आणि सन्माननीय सदस्य श्री. रामदासजी कदम यांनी या सभागृहात अनेक मुद्दे मांडलेले आहेत. पण सांगलीच्या संदर्भात मला येथे सांगावयास पाहिजे की, सांगलीमधील अनेक नगरसेवक हे वेगवेगळया घोटाळयामध्ये अडकलेले आहेत. त्याच्यामध्ये महिला बचतगटाचे पैसे गायब करण्याच्या संदर्भात इचलकरंजी, सांगली, सातारा कऱ्हाड याठिकाणी जे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत त्या सोनपरी डॉल घोटाळयामध्ये श्रीमती सुवर्णा पाटील अडकलेल्या आहेत त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झाले पाहिजे. मोटार चोरी मध्ये श्री. सुनील पाटील हे दोषी आढळून आलेले आहेत. ते देखील नगरसेवक आहेत. श्री. दादा सावंत यांच्यावर खून आणि खंडणीचे गुन्हे आहेत. सभापती महोदय, या आधीचेही गृहमंत्री सांगली जिल्हयाचे होते आणि आताचे गृहमंत्रीही सांगली जिल्हयाचे आहेत. एवढे गुन्हेगार नगरसेवक सांगलीत आहेत. म्हणून माझी पहिली मागणी अशी आहे की, या नगरसेवकांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यसाठी आपण स्वत: महाराष्ट्राचे नेते म्हणून पुढाकार घेतला पाहिजे. (अडथळा) सभापती महोदय, प्रत्येक वेळेला सन्माननीय सदस्य अशा प्रकारे अडथळे आणीत असतात. हा विषय महत्वाचा असल्यामुळे सन्माननीय सदस्य श्री. जयंत प्र.पाटील आपल्याकडून ही अपेक्षा नाही. त्यांचेही नाव जयंत पाटील आहे म्हणून तुम्हाला पुळका येण्याचे कारण नाही.

सभापती महोदय, याठिकाणी स्पष्टपणे असे दिसते की,जेव्हा दंगल झाली त्यावेळी सांगलीचेच गृहमंत्री होते. चार दिवस स्वत: गृहमंत्री सांगलीला आलेच नाहीत. त्यासगळया वादात न जाता सुध्दा मला याठिकाणी अशी मागणी करावयाची आहे की, ज्या निष्पाप लोकांवर केसेस दाखल झालेल्या आहेत त्याबद्दल आपण पुनर्विचार केला पाहिजे. पाच वर्षापूर्वीच्या पुणे शहरातील गणेशोत्वाच्या मिरवणुकीमध्ये ज्या कार्यकर्त्यांवर केसेस झाल्या होत्या त्या मागे घेऊ असे माननीय गृहमंत्री श्री. आर.आर.पाटील यांनी सन्माननीय सदसय श्री गिरीष बापट आणि इतर सगळयां सदस्यांच्या बैठकीत वारंवर सांगितले होते. आजही त्या कार्यकर्त्यांना पुन्ह पुन्हा कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. पुण्याचे सरकारी वकील असे सांगतात की, आमच्याकडे गृह विभागाकडून ही केस आम्ही मागे घेत आहोत असे लेखी येत नाही तोपर्यंत त्यांना कोर्टात ती केस चालवायला लागणार आणि सरकारचे वकील जोपर्यंत येतात तोपर्यात आरोपी म्हणून या कार्यकर्त्यांना यावेच

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

डॉ. नीलम गोऱ्हे....

लागणार. सभापती महोदय, सांगलीलाही एक मोठा गणेश आहे त्यांच्याही दर्शनाला आम्ही जात असतो तेव्हा या गणेशोत्सवाच्या आगोदर या कार्यकर्त्यांवरील खटले पाठिमागे घ्यावेत. पुण्याच्या संदर्भात आणि सांगलीच्या संदर्भात प्रत्येक केस तपासून योग्य ती कारवाई ताबडतोब करण्यात यावी.

सभापती महोदय, नगरसेवकांची खूप मोठी यादी आहे. उदगीर येथील एक नगरसेविका श्रीमती मालनबी मदारी या जवळ जवळ गेले तीन वर्षे फरार आहेत आणि तीन मुलींना फसवणुकीच्या संदर्भात त्यांच्यावर लातुरच्या पोलिसांनी गुन्हे दाखल केलेले आहेत. पण अजूनही त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झालेले नाही. सभापती महोदय, लातूरच्या पोलीस अधीक्षकांना मी वारंवार भेटले आहे. त्यांच्या काय अडचणी आहेत याबाबत या सभागृहात सांगणे म्हणजे राजकरण केल्या सारखे होईल. तेव्हा श्रीमती मालनबी मदारी यांचे नगरसेवक पद रद्द झाले पाहिजे आणि त्यांना मोका लावला पाहिजे. कारण अशा पध्दतीच्या अनेक गुन्हयांमध्ये त्यांचे नांव गुंतले गेलेले आहे.

सभापती महोदय, सांगलीच्या दंगलीच्या संदर्भात कोणाची नार्को टेस्ट करायची आणि कोणाची पॉलीमार्क टेट करायची यासंदर्भात निकष लावले पाहिजेत. कदाचित हे सगळे हाल असह्य झाल्यामुळेच महाराष्टाचा पोलीस कस्टडीतील मृत्युच्यासंदर्भातील नंबर उत्तरप्रदेश, गुजराथ आणि बिहार याच्यापेक्षा जात आहे. सभापती महोदय, आर्थिक गुन्हयांची ंसख्या खूप वाढलेली आहे. अलीकडे नायजेरीयन फ्रॉड म्हणून जो प्रकार आलेला आहे त्यामध्ये बऱ्याचशा लोकांना मेल येतात, फोन येतात, एसएमएस येतात आणि तुम्हाला काही लाख पाऊण्ड मिळालेले आहेत आणि ते लाख पाऊण्ड तुम्हाला मिळण्यासाठी तुम्ही आम्हाला मेल करा आणि तुमचा क्रेडीटकार्ड नंबर कळवा म्हणजे आम्ही तुम्हाला पैसे देतो अशा पध्दतीने लक्षावधी डॉलर्सचा गैरव्यवहार करणारी टोळी सगळीकडे पसरलेली आहे. म्हणून हे सायबर क्राईम कसे हाताळावयाचे यासाठी ठिकठिकाणी कक्ष मजबूत केले पाहिजेत याकडे मला शासनाने लक्ष वेधावेसे वाटते.

...3..

डॉ. नीलम गोऱ्हे....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती महोदय, यूटयुबवर सन्माननीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याबद्दल आणि इतर अनेक मान्यवरांबद्दल सातत्याने घा
णेरडया फिल्म्स लोड केल्या जातात. त्या काढणे आणि त्यावर लक्ष ठेवणे हे काम सातत्याने करत रहावे लागते म्हणून सायबर क्राईमच्या संदर्भात जास्त लक्ष घालून पावले उचलण्यात यावीत याकडे मला लक्ष वेधावेसे वाटते.

सभापती महोदय, याखेरीज काही मुद्दे धार्मिक कायद्याशी संबंधित आहेत. धार्मिक कायद्यांच्या बाबतीत सामाजिक प्रश्न मोठयाप्रमाणात वाढत आहेत. विशेषत: त्याच्यामध्ये अल्पवयीन मुलींच्या बलात्कारा बरोबरच एकतर्फी प्रेमातून ॲसिड फेकण्याचे गुन्हे होत आहेत. रेल्वेट्रेनमध्ये महिलांच्या छेडछाडीचे गुन्हे होत आहेत.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

डॉ. नीलम गोऱ्हे .....

जळितामुळे महिलांचे मृत्यू होत आहेत. जळितांच्या जबानीसाठी स्पेशल ऑनररी मॅजिस्ट्रेट महिला नेमण्याच्या संदर्भात आपण पावले उचलावीत. यापूर्वी शासनाने निर्णय घेतले होते पण आपण सगळ्या जिल्ह्याचा आढावा घेतला तर मृत्यूपूर्व जबानीसाठी जे अधिकारी नेमले जातात त्याच्यामध्ये फार थोड्या महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नंतर कोर्टामध्ये बऱ्याच वेळा यावरुन विसंवाद निर्माण होतो आणि आरोपी सुटतात, ही वस्तुस्थिती आहे. पोलिसांमध्ये महिलांना आरक्षण आहे. आपण महिलांच्या आरक्षणाच्या बाजूने आहात पण प्रत्यक्षात महिला पोलीसआठ टक्केच आहेत. मराठवाड्यामध्ये मी शिवजागरण यात्रा काढली तेव्हा मला सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये असे चित्र दिसले की, बलात्काराच्या घटनेमध्ये चौकशी करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यामध्ये महिला सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर सुध्दा नाहीत. त्या ठिकाणी मग रेंजचा प्रश्न येतो. उस्मानाबादमध्ये जर महिला पोलीस इन्स्पेक्टर असेल तर ती बीडला जाऊ शकत नाही. जालन्यामध्ये जर गुन्हा घडला असेल तर नांदेडची व्यक्ती जाऊ शकत नाही. म्हणून जी परिक्षेत्रे आपण नेमलेली आहेत त्या प्रत्येक परिक्षेत्रामध्ये निदान डीवाय.एस.पी.स्तरावर एक तरी महिला अधिकारी असली पाहिजे यादृष्टीने आपण प्रयत्न करावा. ज्या सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर उपलब्ध आहेत त्यांना तसे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. नाही तर बहुतेक वेळा दबाव आणण्यासाठी त्यांचा उपयोग केला जातो. आज अहमदपूरची घटना घडली. त्या ठिकाणी 11 लोकांनी एका महिलेवर बलात्कार केला. अगदी अशीच घटना नोव्हेंबर महिन्यामध्ये कौशल्या गोपले यांच्या बाबतीत घडली. त्यांचे नाव माध्यमातील लोक गुप्त ठेवतील अशी मी अपेक्षा करते. तिच्यावर बलात्कार झाला आणि त्याची दखल घेतली गेली नाही. 26 नोव्हेंबर, 2009 ला हा गुन्हा घडला होता. त्यानंतर 1 डिसेंबरला तिचा गुन्हा दाखल केला गेला नाही. नंतर त्या महिलेच्या नवऱ्याने आत्महत्या केली. कौशल्या गोपले या महिलेला मी स्वत: भेटले. त्यांनी आठ दिवसांपूर्वी सांगितले की, त्यांना परत मोटारसायकलवरुन धमक्या देणारे लोक इकडे फिरत आहेत. लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथील इंदिरानगरमध्ये राहणाऱ्या 21 वर्षीय विवाहितेवर 11 जणांनी अशाच पध्दतीने बलात्कार केला होता. कालच्या घटनेच्या संदर्भात मी माहिती घेतली होती. ही मुलगी मागासवर्गीय आहे.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ KGS/ KTG/

डॉ. नीलम गोऱ्हे .....

सभापती महोदय, बालकामगार, घरकामगार, अल्पवयीन मुली, लग्नामधील फसवणूक, असे जे सामाजिक प्रश्न आहेत या प्रश्नांसाठी सामाजिक सेवा शाखा अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे. लोक बऱ्याच वेळा 'तो मी नव्हेच' या भूमिकेमध्ये असतात. ते लग्नाचे आश्वासन देतात आणि नंतर असे लक्षात येते की, त्याला दोन, तीन, चार पत्नी असतात. दुर्दैवाने जशी सानिया मिर्झाच्या संदर्भात आज सर्व वृत्रपत्रांमध्ये चर्चा आहे त्या पध्दतीने महाराष्ट्रामध्ये शेकडो गुन्हे अशा प्रकारचे आहेत की, ज्यामध्ये लग्नाच्या बाबतीत फसवणूक करणे किंवा वेगवेगळ्या सी.डी. काढून फसविले जाणे असे गुन्हे घडतात. यासाठी सामाजिक सेवा शाखा मजबूत करावी अशी माझी विनंती आहे.

सभापती महोदय, पुण्यातील जर्मन बेकरीला लवकरात लवकर नाहरकत प्रमाणपत्र मिळावे. त्यांना ती बेकरी परत सुरु करण्याची इच्छा आहे. त्याना नाहरकत प्रमाणपत्र अजूनही मिळालेले नाही. पुणे शहराचे आयुक्त श्री. सत्यपाल सिंह यांच्याबद्दल मला वैयक्तिक बोलावयाचे नसले तरी पत्रकार परिषद घेत असताना ते अजिबात गांभीर्याने घेत नाहीत. सारखे नको त्या ठिकाणी हसतात. मध्येच फोन घेतात आणि सगळ्यात कहर म्हणजे त्यांचा सातत्याने असा आग्रह असतो की, पुण्यामधील दुचाकीस्वार महिलांनी स्कार्फ बांधता कामा नये. त्यांच्या संदर्भात महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. आपल्याला सुरक्षेच्या दृष्टीने ते खरेच किती उपयुक्त आहे आणि किती उपयुक्त नाही याचा कोठे तरी विचार करावा. नाही तर कोणी दिसले नाही की महिलांना थांबविणे बरेच वाटते. प्रत्येक ठिकाणी संघर्ष सुरु होतो. म्हणून अशा अगदी वरकरणी गोष्टींवर पोलीस आयुक्तांनी लक्ष वेधण्यापेक्षा आम्ही दीपक मानकरच्या केसमध्ये पाहिले की, त्यातील जे जबाबदार पोलीस अधिकारी आहेत त्यांच्यावर हायकोर्टाने सांगितल्यावर आता कारवाई झाली. अजूनही दीपक मानकरच्या केसमध्ये ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी केस नोंदवून घेतली नाही त्यांच्यावर आजही कारवाई झालेली नाही. ही पुणे शहरामधील परिस्थिती आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये उपायुक्तांचे कार्यालय असावे ही मागणी गेली तीन वर्षे होत आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये उपायुक्तांचे कार्यालय तसेच तेथील पोलीस फोर्स वाढविण्याच्या संदर्भामध्ये आपण पावले उचलावीत याकडे मला शासनाचे लक्ष वेधावेसे वाटते. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपविते.

...3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ KGS/ KTG/

श्री. संजय केळकर (कोकण विभाग पदवीधर) : सभापती महोदय, नियम 260 अन्वये सभागृहासमोर चर्चेला असलेल्या प्रस्तावर बोलत असताना मी काही विषय या ठिकाणी मांडू इच्छितो. सदनातील अनेक सदस्यांनी निरनिराळ्या विषयांवर मग सुरक्षेच्या संबंधातील विषय असेल, अतिरेकी हल्ल्याच्या संदर्भातील विषय असेल, पोलीस खात्याच्या संदर्भातील विषय असेल असे अनेक विषय मांडलेले आहेत. या ठिकाणी खरे म्हणजे राज्याचे जे पोलीस खाते आहे ते सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून आपण काम करते.

यानंतर श्री. खंदारे

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.संजय केळकर....

सर्व क्षेत्रामध्ये आपण जे काम करतो ते सामान्य माणसाला डोळयासमोर ठेवून काम करीत असतो. पण आज सामान्य माणूस ना घर का ना घाट का अशी त्याची स्थिती झाली आहे. त्याला सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही. सांगायचे असेल तर कोणाला सांगायचे, सहन होत नसले तरी ते सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहे अशी स्थिती दिसत आहे. सभापती महोदय, अनेक ठिकाणी पोलीस अधिकारी चांगले काम करीत आहेत. ज्या ज्यावेळी ते चांगले काम करतात त्यावेळी लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांचे कौतुक करीत असतो. चांगले काम केल्याबद्दल त्यांना शाबासकी दिली पाहिजे, प्रोत्साहन दिले पाहिजे. परंतु अनेक ठिकाणी हेच पोलीस रक्षक नसून भक्षक आहेत की काय असे सर्व दूर चित्र पहावयास मिळते. तालुक्याच्या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक असतात ते त्याठिकाणचे सुभेदार असल्याचे समजतात. ते म्हणतील ती पूर्व दिशा, ते म्हणतील ते धोरण, ते लावतील ते तोरण अशा प्रकारच्या भावनेतून ते फिरत असतात. अशी अनेक उदाहरण समोर आल्यानंतर अधिवेशनामध्ये बोलत असतो, पत्र व्यवहार करीत असतो.

सभापती महोदय, वसईमध्ये घटनेला घटनेबाबत अनेक सन्माननीय सदस्यांनी आपली मते मांडली आहेत. त्या महानगरपालिकेतून 53 गावांना वगळण्याबाबत तेथील लोकप्रतिनिधींनी उपोषण केले होते. परंतु ते उपोषण दडपून टाकण्यासाठी पोलिसांनी उपोषणकर्त्यांवर व सामान्य लोकांवर ज्यांचा त्याच्याशी काही संबंध नसताना अत्याचार केले. या वाघोली गावामध्ये मी दुस-या दिवशी जाऊन प्रत्येक घरातील लोकांना भेटलो आहे. 35 लोकांचे जबाब मी घेतले आहेत, त्याची फाईल माझ्याकडे आहे. या लोकांवर पोलिसांनी कशा पध्दतीने हल्ला झाला, अत्याचार झाला त्याचे सर्व जबाब आहेत. हा अन्याय व अत्याचार पाहिल्यावर ब्रिटिशांनी देखील एवढा अत्याचार केला नाही इतका अमानुषपणे अत्याचार त्या लोकांवर झाला आहे. मी विरोधक म्हणून बोलत नाही, मी तेथील वस्तुस्थिती पाहून आलो आहे. 18 वर्षाच्या मुलापासून ते 86 वर्षाच्या वृध्द माणसापर्यंत कोणालाही पोलिसांनी सोडले नाही. त्याबाबतची अनेक नावे घेता येतील. एक माणूस आपल्या मुलीला परीक्षेला सोडून घरी येत असताना त्याला पोलिसांनी पकडून मारहाण केली आहे. मेन रस्त्यापासून आतमध्ये अर्धा कि.मी.पर्यंत जाऊन तेथील 30-35 घरांच्या काचा

2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

NTK/ KGS/ KTG/

श्री.संजय केळकर....

फोडल्या आहेत, तोडफोड केली आहे. स्वयंपाक घरात शिरले, स्वयंपाक घरातील कपाटे तोडली. वरच्या मजल्यावरील घरामध्ये शिरुन लोकांना मारहाण केली आहे. मी त्या 86 वर्षाच्या व्यक्तीला भेटण्यासाठी गेलो होतो. त्यांनी औषधपाणी सोडले होते, ते अन्नपाणी घेत नव्हते अशी त्यांची अवस्था होती. त्यांना पोलिसांनी सोडले नाही. त्यांच्या पायावर जखमा होत्या. श्री.गणपत पाटील, रा.वाघोली अशी अनेक उदाहरणे या वसईच्या घटनेबाबत सांगता येतील. तेथील लोक भयभीत झ ााले होते. आमचा वाली कोण, आम्हाला कोण धीर देणार आहे, आम्हाला कोण धैर्य देणार आहे असे त्यांना वाटत आहे. या लोकांपैकी कोणाच्या पायाला फ्रॅक्चर झाले होते, कोणाच्या पाठीवर वळ उठले होते. तेथे सर्व जाती धर्माचे लोक होते. अपलान संस्करण ही सिटी स्कॅन करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये मुलगी चालली होती. ती वाटेतून येत असताना पोलिसांनी तिला विचारले आणि मारहाण केली आहे. हरिश्चंद्र कुशवाहक, हा माणूस किराणा स्टोअर्समध्ये काम करतो. श्री.अशोक म्हात्रे हा माणूस त्याच्या मुलीला दहावीच्या परीक्षेला सोडून आला. त्याच्या वाटेवर असलेल्या मावशीने जेवायला बोलविले होते. जेवण करीत असताना त्याला उचलून मारहाण केली, त्यामुळे त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला असून अजूनही त्याच्या पायाला प्लॅस्टर आहे. सांतान फर्नांडीस ही 70 वर्षाची महिला तिलाही मारहाण केली. अशी 35 उदाहरणे वाघोली गावाची देता येतील. एवढा क्रूर अत्याचार पोलिसांनी केला आहे. ब्रिटिश काळात आपण आहोत की काय असे आपल्याला वाटेल. तेथे केवळ एसआरपी नव्हते तर नालासोपारा पोलीस ठाण्याचे पी.आय.आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व सुरु होते, हे घर, ते घर असे दाखविले जात होते. माझी यानिमित्ताने विनंती आहे की, हा सामान्य माणूस आहे, तो दंगलखोर नाही, तो बस जाळण्यासाठी गेला नव्हता, आपापल्या कामामध्ये होता. त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार झालेले आहेत. ते बघवत नाही अशी त्याची स्थिती होती. त्यादिवशी आम्ही एस.पीं.ना, पी.आय.ला वारंवार सांगत होतो की, तेथे अत्याचार चालले आहेत. श्री.विवेक पंडित यांचे उपोषण सुटण्यासाठी त्या सव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आमचा प्रयत्न चालू होता.

यानंतर श्री.शिगम.....

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

(श्री. संजय केळकर....

परंतु पांडेसाहेबांना सांगून सुध्दा त्यांनी यासंदर्भात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सभापती महोदय, तेथील आदिवासींना आणि आजूबाजूच्या परिसरातील लोकांना प्रचंड प्रमाणावर मारहाण झाली. पण आज पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई संबंधितांवर झालेली नाही. मग लोकांनी काय समजायचे ? सरकार सामान्य लोकांच्या पाठीशी आहे की नाही ? त्यांना कोणी वाली आहे काय ? अशा प्रकारचे वर्तन आणि सुभेदारी पोलिसस्टेशन मधील पोलीस आणि अधिकारी करीत असतील तर त्यांना शिक्षा ही व्हायलाच पाहिजे. जे पोलीस चांगले काम करतात त्यांना जरुर प्रोत्साहन दिले पाहिजे. परंतु या प्रकरणी आजपर्यन्त कारवाई झालेली नाही. ही कारवाई झाली तरच लोकांना काही तरी दिलासा मिळू शकेल. सभापती महोदय, म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ साकावतोय आणि याचा परिणाम आपल्याला पुढच्या काळामध्ये भोगावा लागू शकतो.

सभापती महोदय, सामान्य माणूस जर पोलीस स्टेशनमध्ये गेला तर त्याला कोणीच वाली नाही अशी त्याची अवस्था होते. मी शहापूर मधील एक घटना सांगतो. मी कोणत्या ऐकीव बातमीवर बोलत नाही किंवा वर्तमानपत्रातील बातमीवर बोलत नाही. मी स्वत: पाहिलेली आणि स्वत: पाठपुरावा केलेली घटना सांगतो. शहापूरच्या पोलीस स्टेशनमध्ये रमेश रिकामा नावाचा आदिवासी मुलगा गेला. त्यांचे जे काही घरगुती भांडण झाले होते ते मिटले होते आणि ते सांगण्यासाठी तो पोलीस स्टेशनला गेला असता तेथील पोलीस इन्स्पेक्टरने त्याला बेदम मारहाण केली. त्यावेळी तो तेथून पळत सुटला. तो पळत असताना तेथील कॉन्स्टेबलने पाठलागकरुन त्याला पकडले आणि शहापूरच्या मार्केटमध्ये लाथाबुक्क्यांनी त्याला मारहाण केली, त्याच्या प्रचंड अत्याचार केला, इतकी मारहाण केली की शेवटी त्याला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले. हा आदिवासी मुलगा दोन दिवस बेशुध्द अवस्थेत होता. याबाबतीत शहापूर पोलीस स्टेशनमधील कोणत्याही कॉन्स्टेबलवर किंवा इन्स्पेक्टरवर कारवाई झाली नाही. ही घटना नोव्हेंबर मधील आहे. मी स्वत: एसपीना भेटून ही घटना सांगितली आणि चौकशीची मागणी केली. चौकशीसाठी तुम्हास वेळ देतो असेही मी एसपीना सांगितले. तरीही आजपर्यन्त कोणावरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सामान्य माणूस त्याच्यावर होणा-या अन्यायाच्या बाबतीत कोणाकडे दाद मागणार ? कोणाला जाब विचारणार ? अशी राज्यामध्ये

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

MSS/ KGS/ KTG/ पूर्वी श्री. खंदारे 11:25

श्री. संजय केळकर...

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संदर्भात स्थिती आहे. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे आहेत. सभापती महोदय, लोकप्रतिनिधींना देखील सोडलेले नाही हे उल्हासनगरचे उदाहरण मी डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये सांगितले होते. उल्हासनगर येथील डीसीपीं श्री. संजय ऐनपुरे, हे आहेत. निवडणुकीच्या काळाताध्ये पप्पू कलाणीची एवढी मोठी दहशत होती की,पप्पु कलाणीचे गुंड बुथवर जात होते, कार्यकर्त्यांना मारहाण करीत होते. त्या ठिकाणी कुमार आयलानी यांचे निवडणूक प्रतिनिधी नरेंद्र राजानी यांनी त्याचा जाब विचारला तर त्यांनाच पोलिसांनी व्हॅनमध्ये कोबून त्यांना मारहाण केली. त्यांना दिवसभर गाडीतून फिरविले आणि त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवले. या संजय ऐनपुरेचे काय केले, कोणती कारवाई त्याच्यावर केली ? निवडणुकीचा जो प्रतिनिधी आहे त्याला ज्यांनी मतदानापासून वंचित ठेवले त्याच्यावर कोणतीही कारववाई करण्यात आलेली नाही.

सभापती महोदय, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते श्री. एकनाथराव गणपतराव खडसे(पाटील) यांना धमकीचा एसएमएस आला.अनेक व्यापा-यांची चौकशी करण्यात आली. त्याबाबत जितु मखिजा याला अटक झाली. असंख्य व्यापा-यांना पकडण्यात आले. त्याची चौकशी केली. पण नंतर त्याच्याकडून पैसे घेतले, त्याला भीती दाखवली आणि त्याला सोडले. माझ्या माहितीप्रमाणे त्या मखिजाने सांगितले की, माझे बनावट कागदपत्र दिले होते, खोटे कार्ड बनवले होते, मुद्दाम खोटा फोटो छापला होता. ही धमकी दुस-याच लोकांनी दिलेली आहे. याची देखील शहानिशा झाली पाहिजे. कारण या राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांना हा एसएमएस आलेला होता. अशा प्रकारची सुभेदारी आणि वर्तन पोलिसांकडून होत असेल तर सामान्य माणसाने न्याय मागण्यासाठी कुठे जायचे, हा प्रश्न आहे. सभापती महोदय, मी प्रत्येक अधिवेशनामध्ये भिवंडीच्या पोलीस स्टेशनबाबत मुद्दा उपस्थित करीत असतो. या भिवंडीच्या पोलीस स्टेशनच्या बाबतीत कोणता निर्णय घेतलेला आहे त्यासंबंधीचा खुलासा माननीय मंत्री महोदयांनी करावा. या भिवंडी पोलीस स्टेशनकरिता निधी दिलेला आहे.

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री. रमेश शेंडगे)

...नंतर श्री. भोगले...

अप्रकाशित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

SGB/ KGS/ KTG/ 11:30

श्री.संजय केळकर.....

हे भिवंडी पोलीस स्टेशन तेथील लोकांची गरज आहे. परंतु भिवंडी पोलीस स्टेशन निर्माण होत नाही. ही कोणती व्होट बँक आहे? तेथील लोकांच्या हितासाठी पोलीस स्टेशनची मागणी आहे. या पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून, पोलीस खात्याच्या माध्यमातून एक प्रकारची विश्वासार्हता निर्माण व्हावयास पाहिजे, न्याय आणि धीर जनतेला मिळाला पाहिजे. हे होत नसल्यामुळे जनता हवालदिल झालेली आहे. या सर्व विषयामध्ये या चर्चेच्या निमित्ताने सभागृहाचे आणि माननीय मंत्रीमहोदयांचे लक्ष वेधून माझे भाषण संपवितो.

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

अॅड. उषा दराडे (विधानसभेने निवडलेल्या) : सभापती महोदय, या प्रस्तावाच्या संदर्भात माझे मत व्यक्त करताना एक बाब स्पष्टपणे सांगावयाची आहे की, माझ्या समाजातील समाजमनावरची मनुवादी प्रवृत्ती अद्याप संपलेली नाही. याचे उदाहरण काल आपल्याला सभागृहात बघायला मिळाले. जेंडर बायस अशा प्रकारची स्टेटमेंट आदरणीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील आणि माननीय सदस्य श्री.भाई जगताप यांच्या संदर्भात केली गेली. आयपीसी कलम 154 नुसार खोटी तक्रार करु शकतो अशा प्रकारचे स्टेटमेंट झाले. या संदर्भात सांगावयाचे आहे की, कोणी कोणत्या कायद्याचा किती वापर करायचा आणि किती गैरवापर करायचा त्याप्रमाणे समाजामध्ये केले जाते का? सभापती महोदय, आपल्याला माहिती आहे, कलम 324 अन्वये गुन्हा दाखल झाला की कलम 307 दाखल करण्याची मागणी केली जाते. डोक्याला गंभीर जखम झाली, अॅट्रॉसिटी अॅक्टचा वापर झाला किंवा गैरवापर झाला अशा तक्रारी झाल्या. परंतु स्त्री सक्षमीकरणाला धक्का पोहोचेल अशा प्रकारची आक्षेपार्ह स्टेटमेंट केली जातात या संदर्भात मला आक्षेप नोंदवायचा आहे. कोणतीही घटना घडली आणि पोलीस स्टेशनमध्ये सांगितले जाते त्यावेळी सीआरपीसीच्या कलम 154 अन्वये गुन्हा नोंद केली पाहिजे. टेलिफोनीक इन्फॉर्मेशन असली तरी ती फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आहे. परंतु दुर्दैवाने असे होत नाही. इन्क्वॉयरी केली जाते. नंतर आवश्यक वाटले तर गुन्हा रजिस्टर होतो आणि मग चौकशी होते. कलम 354 सारख्या गुन्हयामध्ये खोटी तक्रार केली गेली असे घडत नाही. उलट भगिनींची प्रवृत्ती अशी असते की, माझ्या चारित्र्याविषयी समाजामध्ये चर्चा न झालेली बरी. म्हणून अनेक घटना घडतात मग विनयभंगाची घटना असेल, बलात्कार होऊन देखील महिला समोर येत नाहीत. समोर येण्यास धजत नाहीत. प्रत्यक्ष गुन्हा नोंदविणा-या महिलापेक्षा गुन्हा न नोंदविण्याऱ्या महिला जास्त असतात. महिलांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात सांगावयाचे झाले तर कायदे वेगळे आहेत. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा असे अनेक कायदे आहेत. शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने टाकलेली पावले चांगली आहेत. अजूनही चांगली पावले टाकली पाहिजेत. अजूनही समाजामध्ये हुंडा घेतला जातो. अशा प्रकरणात किती गुन्हे दाखल झाले? महिलांवरील किती अत्याचार समोर आले? बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या संदर्भात मला सांगितले पाहिजे की, 15-16 वर्षाच्या मुलीच्या विवाहाला सामाजिक आदर देण्याच्या दृष्टीने

..3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ॲड.उषा दराडे............

राजकीय पुढारी सुध्दा हजर असतात. अनेक वेळेला अशा प्रवृत्ती खतपाणी घालत असतात. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी आणि द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी किती प्रमाणात होते? सेक्शन 94, आयपीसीच्या संदर्भात विनंती करावयाची आहे की, कायद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. हे गुन्हे दखलपात्र नाहीत. अदखलपात्र आहेत. दुसरी बायको केली तर नॉन कॉग्निझेबल गुन्हा म्हणून एन.सी.रजिस्टर केली जाते. त्या महिलेला स्वत:च्या खिशातून पैसे घालून दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतात. या अर्थाने राज्य महिला अत्याचाराच्या संदर्भात सध्या समाजामध्ये जे प्रमाण आहे त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्ती राज्य महिला आयोगाला दिली गेली आहे. त्यांच्याकडे प्रकरणे मोठया प्रमाणात येतात. परंतु त्यांच्याकडे पुरेसा स्टाफ नाही. अडचण अशी आहे की, त्यांना फक्त नोटीस देण्याचा अधिकार आहे. समन्स काढण्याचा अधिकार आहे. त्यांना वॉरंट काढण्याचा अधिकार नाही. फाईंडिंग देण्याचा अधिकार आहे. त्या फाईंडिंगची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार राज्य महिला आयोगाला नाही. राज्य महिला आयोगाचे अधिकार आहेत त्यामध्ये सुध्दा बदल करणे गरजेचे आहे. महिला पोलीस स्टेशन्सची निर्मिती करणे, जलद गती न्यायालये निर्माण करणे गरजेचे आहे. किती जिल्हयात कुटुंब न्यायालये आहेत? सर्व जिल्हयांमध्ये कुटुंब न्यायालयाची स्थापना करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. गुन्हेगार जन्माने गुन्हेगार नसतो. समाज व्यवस्थेमुळे तो गुन्हेगार होतो. कारागृहामध्ये ज्या सुविधा आहेत त्याबाबत पाहिले पाहिजे की, स्त्री अत्याचाराबद्दल दोन महिन्यांची शिक्षा होऊन तो गुन्हेगार बाहेर आला की,....

(एच.1....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ॲड. उषा दराडे ....

दोन महिन्यानंतर समाजात त्या व्यक्तिची परिस्थिती काय होते हे आपणा सर्वांनाच माहीत आहे. समाज त्या व्यक्तीचा त्याग करतो, बहिष्कृत म्हणून जगण्याची वेळ त्या महिलेवर येते आणि माहेर व सासरचे लोक सुध्दा तिला स्वीकारत नाहीत. अशा परिस्थितीत ज्यावेळी त्या व्यक्तिला आपण शिक्षा करतो तेव्हा तिला जन्मठेप करण्याचा अधिकार पोहचत नाही. म्हणून कारागृहातून बाहेर गेलेल्या महिलांचे पुनर्वसन व त्यांना रोजगाराची संधी मिळवून देणे, व्यवसाय करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. एकीकडे जगाची उत्पत्ती कशी झाली हे संशोधन करण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत तर दुसरीकडे मात्र कारागृहातील महिलांच्या पुनर्वसनाचा शासनाने विचार करावा. मी एक उदाहरण म्हणून सांगणार आहे की, एका साखर नावाची महिला मर्डरच्या केसमधून उच्च न्यायालयात निर्दोष सुटली. त्यानंतर तिला अवहेलना सहन करावी लागली म्हणून ती बीडमध्ये गेली आणि तिने वेश्या व्यवसाय सुरु केला. शेवटी तिचा मृत्यू झाला तेव्हा समजले की, तिची बहीण आणि तिने दारु पिऊन आत्महत्त्या केली. अशा एका घटनेमुळे तिचे संपूर्ण आयुष्य बरबाद झाले असे होता कामा नये म्हणून कारागृहामध्ये ज्या महिला असतात त्यांच्यासाठी शासनाने आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करणे आवश्यक आहे व त्यांचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे.

महोदय, मागील आठवड्यात एका प्रकरणाचा मी सभागृहात उल्लेख केला होता. ते म्हणजे बीड जिल्ह्यातील एकुरका या गावामध्ये महिलेची नग्न धिंड काढण्यात आली आणि तिला मारहाण करुन आरोपी पळून गेले. अशा गुन्हेगारांवर 37, 38 आणि 39 सीआरपीसी नुसार गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. परंतु आपल्या कायद्यातच असे म्हटले आहे की, 99 गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये अशा प्रकारचे कायद्यातील सेक्शन्स आहेत. त्यात परिवर्तन करण्याच्या दृष्टीने राज्यशासनाने केंद्राकडे संपर्क साधला पाहिजे. अशा प्रकारे गंभीर आरोप असताना सुध्दा आरोपी सुटून जातात हे कायद्यातील पळवाटांमुळे होते.

या सभागृहात चर्चेत भाग घेताना सन्माननीय सदस्य पोलीस यंत्रणेवर चांगले बोलले तर काही पोलिसांच्या विरोधात बोलले. परंतु महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, पोलिसांवर कामाचा प्रचंड ताण असतो त्यामुळे त्यांना 24-24, 25-25 तास डयुटी करावी लागते आणि हे निश्चितच चुकीचे आहे. माजलगांवच्या एका बातमीचा उल्लेख येथे केला होता तो म्हणजे तेथे एपीआय आणि

....2....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ॲड. उषा दराडे ....

पीआय यांच्यामध्ये हप्ते वाटून घेण्यावरुन भांडण झाले त्यासंबंधीची कोणतीही तक्रार नोंदविलेली नाही. दोन कॉन्स्टेबलनी एका महिलेची छेड काढण्याचा प्रयत्न केला असता लोकांनीच त्यांना पकडून मारले परंतु त्यासंबंधीचा कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. त्याचबरोबर पोलीस दलात काही चांगले अधिकारी सुध्दा आहेत. त्यात रंजन मुखर्जी नावाचे एस.पी. होते. त्यांची बदली झ ाल्यावर बीड जिल्ह्यातील जनतेने संपूर्ण जिल्हा बंद पाडला होता आणि हीच व्यक्ती आम्हाला एस.पी. म्हणून पाहिजे अशी मागणी केली होती. म्हणून कोणीही असो, जो काम चांगले करतो त्याला लोकांची साथ असते. मग त्यात पोलीस असतील किंवा कुठलीही यंत्रणा असेल. आजही गृह विभागात चांगले काम करणाऱ्यांची फळी आहे म्हणूनच कायदा व सुव्यवस्था कायम आहे. आपण 26/11 च्या प्रकरणात धैर्याने तोंड दिले, मालेगाव मधील घटनेच्या प्रसंगी धैर्याने तोंड दिलेले आहे. कारण गुन्हेगाराला कोणताही धर्म आणि जात नसते, गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. अशा परिस्थितीत सुध्दा या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था टिकविण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कारण आपल्या राज्यातील नागरिकांचे मनोबल, राज्याचे मनोबल मोठे आहे म्हणून अशा कठीण प्रसंगतातूनही पुन्हा हिंमतीने उभे राहण्याची शक्ती आपल्याला मिळते. अशाच प्रकारे पुढची वाटचाल देखाली शासन करील असा आशवाद मी व्यक्त करते आणि मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल पुन्हा आपले आभार व्यक्त करुन माझे भाषण संपविते.

....3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. जयंत प्र.पाटील (विधानसभेने निवडलेले) : महोदय, कायदा व सुव्यवस्थेच्या संदर्भात मी फक्त एकच मुद्दा सांगणार आहे. तो म्हणजे एके काळी स्कॉटलँड पोलिसांबरोबर मुंबई पोलिसांची तुलना होत होती. पोलिसांचा दर्जा जागतिक पातळीवर होता आणि आता तो इतका घसरलेला आहे की, या विधिमंडळात येताना सुध्दा आमची तपासणी करावी लागते. आपण जनतेपासून दूर जात आहोत की काय असेच त्यामुळे वाटायला लागले आहे. विधिमंडळामध्ये अतिरेक्यांची भीती वाटते म्हणून सर्वसामान्य माणूस येऊन सभागृहाचे कामकाज सुध्दा पाहून शकत नाही हे शासनाला गांभीर्याने पहावे लागेल. आम्ही येथे येऊन काय बोलतो, कोणते प्रश्न मांडतो हे येऊन जनता पाहत होती ते सुध्दा आता सिक्युरिटीच्या नावाखाली बंद झालेले आहे. कदाचित भविष्यात एक वेळ अशी येईल की, आम्हाला सुध्दा विधिमंडळात येण्याची बंदी येईल आणि घरीच बसून संगणकावरुन, व्हिडीयो कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून किंवा सी.सी.टी.व्ही. च्या माध्यमातूनच आपली भाषणे करावी लागतील.

यानंतर श्री. जुन्नरे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(सभापतीस्थानी माननीय उपसभापती)

श्री. जयंत प्र.पाटील.....

सभापती महोदय, मी ऑस्ट्रेलियात गेलो होतो त्यावेळेस मला त्या ठिकाणच्या पार्लमेंटमध्ये जाण्याचा योग आला. मला वाटले पार्लमेंटमध्ये जावयाचे असे्ल तर आपल्या सारखा पास वगैरे काढावा लागेल, परंतु आपल्या सारखा मला त्या ठिकाणी पास काढावा लागला नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या पार्लमेंटमधील प्रेक्षक गॅलरीत मी 10 मिनिटात पोहचलो. त्या ठिकाणी मी प्राईम मिनिस्टरला भेटलो त्यांनी जागेवरुन उठून मला वेलकम केले. परंतु भारतामध्ये आज आपल्याकडे काय चालले आहे ते आपण पाहतोच आहोत. या ठिकाणी माननीय गृहमंत्री श्री. पाटील उपस्थित असल्यामुळेच मी माझे विचार मांडण्यासाठी उभा आहे. माननीय पाटील साहेब आपण तळागाळातील चळवळीमध्ये काम करुन राज्याचे गृहमंत्री झालेला आहात. असे असतांनाही आम्हाला या ठिकाणी या परिस्थितीत यावे लागते हे काही बरोबर नाही. विधानभवनात येतांना सुध्दा आमदारांची चौकशी केली जाते, हे काही बरोबर नाही. त्यामुळे हा प्रकार कोठे तरी थांबला पाहिजे. खरे म्हणजे आपले पोलीसदल अकार्यक्षम झालेले आहे. मला या ठिकाणी एकच मुद्दा मांडावयाचा आहे की, आपण पोलिसांना मीडिया समोर जाण्यास बंदी घातली पाहिजे. केंद्रामध्ये आयएएस अधिकारीच मीडिया समोर जात असतात परंतु आपल्याकडे साधा इन्स्पेक्टर मीडियासमोर आपल्या पेक्षा जास्त जोरात बोलत असतो. त्यामुळे आपल्या अधिका-यांना मीडिया समोर जाण्याची बंदी केली पाहिजे. पुण्याच्या जर्मन बेकरीच्या प्रकरणात तेथील दोन अधिका-यांनी वेगवेगळी स्टेटमेंट दिली होती. म्हणून हा प्रकार कोठे तरी थांबला पाहिजे. सरकारच्या वतीने ठराविक अधिका-यांनाच मीडिया समोर पाठविले पाहिजे. खरे म्हणजे यामुळे गुन्हेगारी वाढते, असे मला वाटते.

सभापती महोदय, मुंबईमध्ये अनेक संघटना आणि अनेक पक्ष अधिवेशनाच्या वेळेस मोर्चे काढीत असतात. या मोर्च्यांमुळे मुंबईतील ट्रॅफिक जाम होत असते. मुंबईतील ट्रॅफिक जाम होऊ नये यासाठी आता आझाद मैदानावरच मोर्चे अडविले जातात व तेथेच त्यांची सभा होते आणि भाषणही होत असतात. काल आम्ही आझाद मैदानावर मोर्चा काढला होता. आझाद मैदानावरील 25 टक्के जागा आपण अगोदरच बंद केली आहे. आझाद मैदानावर सावलीची कोणतीही सोय

...2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. जयंत प्र.पाटील.....

नसल्यामुळे मोर्च्यातील लोक झाडाच्या आडोशाला उभे राहतात व त्यामुळे त्या ठिकाणी ट्रॅफिक जाम होत असते. आझाद मैदानावर कायमस्वरुपी सावलीची सोय केली तर त्या ठिकाणी ट्रॅफिक जाम होणार नाही. तरी आझाद मैदानावर कायमस्वरुपी सावलीची सोय करावी, अशी मी मागणी करतो. या ठिकाणी आपण मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपले आभार मानून मी माझे दोन शब्द पूर्ण करतो.

...3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. किरण पासवकर (विधानसभेने निवडलेले) :सभापती महोदय, कायदा व सुव्यस्थेवर चर्चा व्हावी म्हणून आम्ही दोन दिवस नाही तर अधिवेशन सुरु झाल्यापासून मागणी करीत आहोत. आपण मला कायदा व सुव्यस्थेवर विचार मांडण्याची संधी दिल्याबद्दल प्रथम मी आपल्याला धन्यवाद देतो.

सभापती महोदय, राज्याचा विकास किंवा राज्याचे अर्थशास्त्र हे गृहविभागावरच अवलंबून असते. जे राज्य विकासामध्ये पुढे आहे, ज्या राज्याचा गृह विभाग चांगला आहे, त्या ठिकाणी लॉ अँड ऑर्डरची स्थिती चांगली असते, तेच राज्य ख-या अर्थाने विकास करु शकते. जम्मू-काश्मिरला आपण औद्योगिक धोरण ठरविलेले आहे. परंतु त्या ठिकाणी एकही उद्योग जात नाही. हिमाचल प्रदेश येथे उद्योग काढले तर त्या उद्योगांना इन्कमटॅक्समध्ये तसेच सेल्स टॅक्समध्ये सरकारने सूट दिलेली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे त्या ठिकाणी एकही इंडस्ट्री जात नाही, हे त्या मागचे मुख्य कारण आहे. ज्या राज्याची कायदा व सुव्यवस्था चांगली नसते त्या राज्याचा विकास होऊ शकत नाही.

सभापती महोदय, मुंबईला उद्योग नगरी म्हटले जाते. मागील पाच वर्षामध्ये मुंबईमध्ये कुशल, अकुशल कामगार मिळत होते परंतु आता मुंबईत फक्त मॅनेजर आणि सिक्युरीटी गार्डस् मिळतात. मुंबईत मॅनेजर आणि सिक्युरीटीचा वर्षाचा टर्नओव्हर जवळ जवळ 1000 कोटीच्या वर गेलेला आहे. अगोदर आपल्याला केवळ सोनाराच्या दुकानावरच सिक्युरीटी गार्ड दिसत होते.

यानंतर श्री. गायकवाड...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.किरण पावसकर...

आता प्रत्येक सोसायटी, दुकानासमोर गार्ड दिसत आहेत. त्यामुळे आपण मुंबईमध्ये आहोत की,नैरोबीमध्ये आहोत असा प्रश्न पडतो. नैरोबीच्या प्रत्येक रस्त्यावर आपल्याला गार्ड दिसतात. तीच परिस्थिती आज मुंबई शहरामध्ये आहे. पोलिसांना सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत यात दुमत नाही. पोलिसांना घर मिळाले पाहिजे. एवढेच नव्हे तर आज त्यांच्या कामाची पद्धत बदलली पाहिजे. पोलीस दलाला भ्रष्टाचार मुक्त केले पाहिजे. त्यांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी शासनाने सर्व सहकार्य केले पाहिजे. तसेच, पोलिसांकडून चांगले काम करून घेतले पाहिजे. या सर्व बाबींकडे शासन म्हणून आपण लक्ष देणे गरजेचे आहे. पोलीस दलामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाणे 10 ते 15 टक्के असेल. यासाठी संपूर्ण पोलीस दल बदनाम होणे योग्य नाही. भ्रष्टाचार प्रकरणी लाचलुचपत विभागाने ज्या अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना पकडून चौकशी केल्यानंतर त्याच अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना चांगली पोलीस ठाणी देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. ते प्रथम बंद केले पाहिजे. कालच सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते म्हणाले की, आबा आपण फार संवेदनशील आहात. "आबा " या शब्दाचा अर्थ वडिलधारी माणूस. आपल्या घरातील ज्येष्ठ व्यक्तीला आपण "आबा " या नावाने हाक मारतो.

उप सभापती : मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना देखील आबासाहेब म्हणायचे.

श्री.किरण पावसकर : सभापती महोदय, सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्य माननीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटील असा उल्लेख न करता आबा असा करतात. आबा असा उल्लेख केल्यामुळे आपल्यावरचा हक्क ते दाखवितात. आपण डान्सबार बंद केल्यामुळे महाराष्ट्रातील विशेष करून मुंबईतील जनतेने आपल्याला धन्यवाद दिले. आपण तंटामुक्त गाव केले. पण सर्व गावातील तंटे शहरात आणून टाकले की काय ? असे आता वाटायला लागले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे शाहरूख खान यांच्या सिनेमाविरोधात तसेच श्री.राहुल गांधी यांच्या मुंबई भेटीच्या वेळी शिवसेनेचे केलेले आंदोलन. लोकशाहीमध्ये मोर्चे काढायचे नाहीत काय ? धरणे धरायची नाहीत काय ? आंदोलन करायचे नाही काय ? श्री.राहुल गांधी यांना काळे झेंडे दाखवायचे नाहीत काय ? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान असताना काळे झेंडे दाखविण्यात आले

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.किरण पावसकर....

होते. त्यावेळी त्या स्वत: आंदोलनकर्त्यांना भेटायला गेल्या. पण ज्यावेळी श्री.राहुल गांधी यांना काळे झेंडे दाखविण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला त्यावेळी पोलीस दलाचा जो वापर करण्यात आला तो निश्चितच चुकीचा होता. हा लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रकार होता. यावेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जे निवेदन केले ते भयानक होते. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी असा प्रकार घडत असेल तर श्री.उद्धव ठाकरे यांची सुरक्षा काढून घेण्यात येईल असे निवेदन केले. आंदोलन करतात म्हणून सुरक्षा काढून घेणे चुकीचे आहे. डेव्हीड हेडली यांच्याकडे 24 जणांची माहिती होती. त्यात उद्धव ठाकरे यांच्या घरासंबंधातील माहिती होती असे कळले आहे. असे असताना श्री.उद्धव ठाकरे यांची सुरक्षा काढून घेणे याचा अर्थ काय ? माननीय मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख असल्याने त्यांच्यावर संपूर्ण राज्याची जबाबदारी असते हे विसरून चालणार नाही. श्री.राहुल गांधी हे एका पक्षाचे प्रमुख आहेत त्याच प्रमाणे दुसऱ्या पक्षाचे देखील काम चालत असते. श्री.राहुल गांधी व श्री.शाहरुख खान यांच्या विरोधात केलेले आंदोलन चिरडण्यासाठी जो प्रकार केला तसा पुन्हा करू नये. आपण लोकशाही पद्धती स्वीकारली आहे, याचा विचार शासनाने करावा, एवढेच या निमित्ताने मला सांगावयाचे आहे.

सभापती महोदय, मी आणखी दोन मुद्दे मांडणार आहे. सन 2009 मध्ये श्री.जयंत पाटील गृह मंत्री असताना लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. सांताक्रूझ विमानतळ येथे 100 किलो चांदी आणि सोन्याची चोरी 11.00 वाजता झाली.

यानंतर श्री.सरफरे......

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. किरण पावसकर....

आजही त्याचा उलगडा झालेला नाही. मी त्यावेळी आणखी चार प्रसंग याठिकाणी सांगितले होते. त्या विमानतळाला आपण मोठया प्रमाणात सिक्युरिटी पुरविलेली असतांना आणि त्या सिक्युरिटीमध्ये असलेल्या विमानतळावर चोऱ्या होत आहेत. आपणही नेहमी हेलिकॉप्टरने फिरत असता. मी याठिकाणी आपणास चार घातपाताचे प्रकार सांगितले. त्यानंतर मला या सदनामध्ये आश्वासन देण्यात आले की, तेथील अे.सी.पी. यांच्यावर कारवाई केली जाईल. त्या असीपी यांनी स्वत: एविकॉन एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची एक कंपनी काढली आहे. अशी कंपनी काढून ते लोकांना त्रास देत आहेत. तरीसुध्दा त्यांच्यावर शासनाकडून सन 2009 नंतर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी या सदनामध्ये मागणी केल्यानंतरही कारवाई करण्यात आली नाही. मी पुन्हा त्यासंबंधीची कागदपत्रे आपणाकडे पाठवीत आहे. मागील आठवडयात दि. 27 रोजी एअरपोर्टवर एका उद्योगपतीला गुजरातहून सी.बी.आय. पकडून आणीत असतांना त्या उद्योगपतीला हायकोर्टाकडून अंतरिम जामीन मिळाल्याची ऑर्डर एअरपोर्टच्या बाहेर आणून द्यावयाची असतांना या महाशयांनी ती ऑर्डर एअरपोर्टच्या आतमध्ये जाऊन दिली. सभापती महोदय, त्या एअरपोर्टच्या रनवेवर राज्याचे गृहमंत्री म्हणून आपणसुध्दा जाऊ शकत नाही. परंतु या महाशयांनी स्वत: हायकोर्टाची ऑर्डर नेऊन सी.बी.आय. च्या कामामध्ये अडथळा आणला यासंबंधी त्यांच्याविरुध्द तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सभापती महोदय, यासंबंधी मी पाच वेळा तक्रारी केल्यातरी आपणाकडून सी.आय.डी. चौकशी केली जाईल असे एकच उत्तर देण्यात आले आहे. परंतु कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही. आपण या महाशयांना अे.सी.पी.वरुन डी.सी.पी. च्या पदावर बढती देऊन त्यांची चांगल्या ठिकाणी पोस्टींग कराल. ज्याप्रमाणे कल्याण आणि डोंबिवलीमध्ये जोशी दिसले, त्याप्रमाणे हे महाशय दुसऱ्या कोणत्या तरी प्रकरणामध्ये गुंतल्याचे आपल्याला दिसतील. त्यांचे नाव अे.सी.पी. श्री. जांभूळकर आहे. यासंबधी उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना आपण चौकशी करुन न्याय देतो असे सांगितले. त्यांची सी.आय.डी.मार्फत चौकशी करतो असे सांगितले. परंतु मागील आठवडयात त्यांच्याकडून हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा घडला आहे. अशाप्रकारचा कुठलातरी घातपाताचा प्रकार या अधिकाऱ्याकडून होऊ शकेल. हा अधिकारी आपल्याबरोबर चार कर्मचाऱ्यांना त्या एअरपोर्टच्या रनवेवर घेऊन जातो आणि सी.बी.आय. च्या अधिकाऱ्यांना जामीन आदेशाची प्रत देतो. त्यामुळे

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/ KGS/ KTG/

श्री. किरण पावसकर....

सी.बी.आय. ला आपल्या गृह खात्याकडे या संदर्भात तक्रार करावी लागणे ही गांभीर्याने घ्यावयाची बाब आहे.

सभापती महोदय, त्याचप्रमाणे मी मुनीरखानचे एक प्रकरण याठिकाणी मांडणार आहे. अंधेरी येथील एक बॉडी रिव्हायवलचा कार्यक्रम टी.व्ही. वर दाखविण्यात येत होता. यामध्ये मोठ मोठ्या रोगांवर उपचार केले जातात असे सांगून अनेक लोकांकडून लाखो, करोडो रुपये लुटण्यात आले आहेत. याविरुध्द वर्सोवा पोलीस स्टेशनमध्ये 1 हजारावर तक्रारी करण्यात आल्या असतील. असे असतांना आपले पोलीस मुनीरखान फरार असल्याचे सांगत आहेत. मुनीरखानविरुध्द हजारो तक्रारी असलेल्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 27 मार्चला इस्कॉनच्या हरे राम हरे कृष्ण मंदिराच्या हॉलमध्ये एक कार्यक्रम करण्यात आला. त्यामध्ये मुनीरखान याला आमदार श्री. बलदेव खोसा यांच्या हस्ते ॲवॉर्ड देण्यात आला . तो ॲवॉर्ड असा होता "Excellent contribution in the Social Work" हा ॲवॉर्ड या अधिवेशन काळामध्ये त्याला देण्यात आला आहे. सभापती महोदय, तो कार्यक्रम पराज प्रतिभा प्रतिष्ठान या संस्थेने ठेवला होता, त्यांचे हिंदी विकली मॅगझिन प्रसिध्द होते. त्या कार्यक्रमाच्या पत्रिकेवरील नावे आपण पाहिलीतर आपल्याला आश्चर्य वाटेल. कायदा व सुवयवस्थेच्या विषयावर हे अधिवेशन संपेपर्यंत आपण बोलू शकू एवढी नावे त्यावर आहेत. सभापती महोदय, त्यामध्ये त्या कार्यक्रमाला कोण कोण मान्यवर व्यक्ती येणार आहेत हे दाखविले आहे? खासदार गुरुदास कामतजी, केंद्रीय मंत्री, संजय निरुपमजी, आणि अमिताभ गुप्ता अतिरिक्त पोलीस आयुक्त यांची नावे असतांना त्यांच्यापैकी कुणीही आले नाही. परंतु माननीय आमदार श्री. बलदेव खोसा त्या कार्यक्रमाला उपस्थित झाल्यानंतर त्यांच्या हस्ते मुनीरखान यांना पारितोषिक देण्यात आले. यासंबधीचा फोटो टाईम्स ऑफ इंडिया या वर्तमानपत्रामध्ये छापून आलेला आहे. मला आपल्याला विचारावयाचे आहे की, या मुनीरखानसाठी कोणत्या राजकीय पक्षाचे नेते पुढे येत आहेत. ज्यांनी हजारो लोकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळला आहे, ज्यांनी करोडो रुपयांना फसविले आहे, त्या माणसाला पाठिशी घालण्याचे कारण काय? आपण त्याला फरार म्हणून घोषित केले असतांना त्याला लवकरात लवकर पकडणार काय? सभापती महोदय, माझ्याकडे बोलण्यासारखे भरपूर मुद्दे आहेत. माननीय गृहमंत्र्यांकडून आमच्या भरपूर अपेक्षा आहेत. आपण या दोन्ही प्रकरणामध्ये लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/ KGS/ KTG/

श्री. किरण पावसकर....

सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याकरिता भरपूर वेळ दिल्याबद्दल आपले आभार मानून माझे भाषण संपवितो.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.कपिल पाटील (मुंबई विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, याठिकाणी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाबाबत सदनामध्ये चर्चा सुरु आहे. मी केवळ दोनच मुद्यांना स्पर्श करुन माझ ो भाषण संपविणार आहे.

सभापती महोदय, हे राज्य कायद्याचे आहे असे आपण म्हणत असलो तरी या राज्यातील लोकशाही हक्काची रोज पायमल्ली होत आहे याबद्दल प्रश्न निर्माण होतो. वसई मधील आंदोलन चिरडण्यासाठी, जे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने, सनदशीर मार्गाने सुरु होते ते मोडून काढण्यासाठी ज्या पध्दतीने पोलिसांनी अत्याचार केले, त्याला इतिहासामध्ये तोड नाही. मला अशी माहिती मिळालेली आहे की, या संबंधीचे आदेश माननीय गृह मंत्र्यांनी, माननीय मंत्री महोदयांनी किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले नव्हते. परंतु तेथील एस.पी.आणि डी.वाय.एस.पी.यांनी कोणाची तरी सुपारी घेऊन स्वत:हून ज्यापध्दतीने ते आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याला कुठेतरी पायबंद घातला पाहिजे. सभापती महोदय, उपास संपवावयाचा होता, मी समजू शकतो. पण तेथून 15 कि.मी.वर असलेल्या वाघोली गावात घराघरामध्ये घुसून ज्यापध्दतीने अत्याचार केले, ते पाहिल्यानंतर डोळयामध्ये पाणी येते. त्याठिकाणी 85 वर्षाच्या म्हातारा जो अंथरुणावर आहे, ज्यांना उठता येत नाही, त्यांनाही मारहाण केली. त्यांनी महिलांना सुध्दा सोडले नाही, त्यांची वस्त्रे फेडण्यात आली. तसेच छोटी-छोटी मुले परीक्षेसाठी चालली होती, त्यांच्या पाठिवर देखील रट्टे बसले अशा प्रकारे निघृण मारहाण झालेली आहे, एवढी मारहाण झालेली आहे की, अजूनही लोक त्यामधून बाहेर येऊ शकलेली नाहीत. जेव्हा लोक लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतात, तेव्हा त्याचा आदर सरकार करणार की नाही हा प्रश्न आहे. तुम्हाला तुमचा जो काही राजकीय निर्णय घ्यावयाचा असेल तो घ्यावा. पण जेव्हा जनमत एका बाजूला आहे आणि त्यांच्याकडून सांगितले जात आहे की, 53 गावे वगळली पाहिजेत, तेव्हा त्या लोकांशी चर्चा केली पाहिजे, संवाद साधला पाहिजे परंतु त्याऐवजी त्या लोकांना मारहाण केली जाते. या चर्चेच्या निमित्ताने माझी अशी मागणी आहे की, ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही मारहाण केली, जे अत्याचार केले त्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित केले पाहिजे. माननीय गृह मंत्री महोदयांनी चौकशी लावलेली आहे. पण जोवर ते अधिकारी तेथेच असतील, तोपर्यंत या चौकशीला काही अर्थ रहाणार नाही. म्हणून किमान त्यांना त्या जिल्ह्याच्या बाहेर तरी पाठविण्यात यावे, अन्यथा या चौकशीला काही अर्थ नाही.

सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.किरण पावसकर यांनी लोकशाही हक्कांच्या होत

. . . .एल-2

असुधारीत प्रत/प्रसिध्दीसाठी नाही

श्री.कपिल पाटील . . . .

असलेल्या पायमल्लीबाबत उल्लेख केला की, जेव्हा-जेव्हा जन आंदोलने होतात, त्या-त्या वेळेला पोलीस हे आपल्या समोर जणुकाही चोर-दरोडेखोर उभे आहेत अशा पध्दतीने वागतात. चोरांना सोडून देतात, फसविणाऱ्यांना सोडून देतात. पण जे लोक शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करतात, त्यांना गोळया खाव्या लागतात. या राज्याचे गृहमंत्री हे आदरणीय श्री.आर.आर.पाटीलसाहेब आहेत म्हणून मला त्यांच्या कडून अपेक्षा आहे की, त्यांनी यापुढे लोकांच्या प्रश्नाच्या संबंधात जी आंदोलने सुरु आहेत, जी सनदशीर मार्गाने सुरु आहेत त्या आंदोलकांवर लाठी किंवा गोळया चालविल्या जाणार नाही याची या सदनामध्ये हमी दिली पाहिजे. आपण अशा प्रकारची हमी दिली नाही तर लोकांना मार खावा लागेल आणि खरे चोर, अतिरेकी पळून जातील.

सभापती महोदय, या राज्यातील नक्षलवाद्यांच्या संबंधात राजकीय मतभेद असू शकतात. पण नक्षलवादी म्हणजे कोणी चोर किंवा दरोडेखोर नाहीत किंवा कोणी अतिरेकी नाहीत. या राज्यातील जी शोषित जनता आहे, त्यांच्या मुक्तीसाठी ते लढत असतात. त्यांचे मार्ग भले चुकीचे असतील, मी त्याच्याशी सहमत नाही. त्यांनी संसदीय प्रवाहामध्ये आले पाहिजे या मताचा मी आहे. पण त्यांना तुम्ही अतिरेकी समजून जर गोळया घालत असाल तर ते योग्य नाही. मी अनेक उदाहरणे दिली की, जे नक्षलवादी नाहीत, पण केवळ क्रांतीची पुस्तके हातामध्ये आहेत, ज्यांची परंपरा नक्षलवादाची नाही, ज्यांच्यावर पूर्वी कोणताही हिंसेचा आरोप नाही, हिंसक कारवाईमध्ये भाग घेतल्याचा आरोप नाही अशा छोट्या मुलांना, कॉलेजमधील तरुणांना तुम्ही वर्षानुवर्षे तुरुंगामध्ये टाकता. मागच्या वेळी मी नागपूरच्या मुलांच्या संबंधात मागणी केल्यानंतर अगोदर थोडेसे ताणून धरले, पण त्या तीन मुलांची सुटका केली. पण ज्यांच्यावर कोणतेही हिंसक आरोप नाहीत आणि ज्यांनी या कामामध्ये कोणताही भाग घेतलेला नाही. केवळ क्रांतीची पुस्तके हातात आहेत, भगतसिंग यांचे पुस्तक हातामध्ये आहे म्हणून जर तुम्ही त्यांना तुरुंगामध्ये टाकणार असाल तर त्यासारखी शरमेची बाब नाही. त्या सर्व मुलांची सुटका झाली पाहिजे अशी माझी या निमित्ताने माननीय गृहमंत्री महोदयांना विनंती आहे.

सभापती महोदय, मी भिवंडीच्या बाबतीत एकच उल्लेख करुन माझे भाषण संपविणार आहे. भिवंडी येथे गुलाम नबी अन्सारी जे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, पत्रकार आहेत. त्यावेळच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी आपले ऐकत नाहीत आणि पोलीस स्टेशनच्या संबंधात जो विवाद ...

. . . .एल-3

श्री.कपिल पाटील . . . .

निर्माण झाला त्याचा राग मानून, सूडबुध्दीच्या भावनेने श्री.गुलाम नबी अन्सारी यांना गेल्या दोन वर्षापासून तुरुंगामध्ये टाकण्यात आलेले आहे. अशा प्रकारे जर पोलीस अधिकारी व्यक्तीगत सूड भावनेने पेटून अशा प्रकारे कारवाई करणार असेल तर या राज्यामध्ये कोणाकडे न्याय मागावयाचा असा प्रश्न आहे. सभापती महोदय, आपल्याला ती घटना माहिती आहे. श्री.गुलाम नबी अन्सारी यांच्यावर कोणताही पूर्व गुन्हा नाही, कोणतीही गुन्हेगारी पाश्वभूमी नाही अशा माणसाला 302 या कलमाखाली तुरुंगामध्ये टाकलेले आहे. मी गेल्या दोन वर्षापासून अनेक वेळा विनंती करुन, मागणी करुन त्याची दाद लागत नाही. मी यानिमित्ताने मागणी करतो की, श्री.गुलाम अन्सारी प्रकरणाबाबत सी.आय.डी.चौकशी करावी आणि सध्या त्यांच्याकडे असलेले प्रकरण काढून घेण्यात यावे आणि श्री.गुलाम नबी अन्सारी यांची मुक्तता करावी अशी मागणी करुन मी माझे भाषण संपवितो. सभापती महोदय, आपण मला भाषणासाठी वेळ दिला आहे त्याबद्दल धन्यवाद.

यानंतर कु.थोरात . . ..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. हेमंत टकले (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय,मी सर्वप्रथम आपण मला याठिकाणी बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल आपले आभार मानतो. अतिशय थोडक्यात थोडयाशा व्यापक प्रश्नांना स्पर्श करण्याचा मी प्रयत्न करतो.

सभापती महोदय, पोलीसांसाठी एक आदर्श आचारसंहिता कोड ऑफ कंडक्ट असण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचे पालन करण्यासाठी एक यंत्रणा पोलीस खात्यामध्ये आणणे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आवश्यक झालेले आहे. आपण नेहमी म्हणतो की पोलिसांची केंद्र एकमेकांना जोडलेली आहेत ती नुसती एकमेकांना जोडून चालणार नाहीत तर याठिकाणी जे प्रमुख आहेत त्यांचे आपापसातील नेटवर्किंग होत आहे की नाही याकडें अधिक बारकाईने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. अनेक ठकाणी असे दिसून येते की, समाजहितविरोधी प्रवृत्तींना संरक्षण देण्याकडे पोलीस खात्याचा कल असतो आणि हा समज जर समाजामध्ये पसरला तर अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळून सामान्य माणसांना असुरक्षित वाटायला लागते. अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पोलीस खात्यामार्फत काही तरी योजना ताबडतोब राबविणे गरजेचे आहे. सरकारी वकीलांच्या गृहखात्याकडून ठिकठिकाणी नेमणुका केल्या जातात. त्यासाठी बारकौन्सिलचे सहकार्य घेणे महत्वाचे आहे कारण योग्य पध्दतीचे वकील पोलीस खात्याला मिळाले तर गुन्हेगारांना शिक्ष होण्याचे प्रमाण निश्चितपणे वाढेल. आपण नेहमी म्हणतो की, पोलिसांची रिस्पॉन्स टीम तयार असते. पण रिस्पॉन्स टीम ऐवजी ॲन्टीसिपेट करणारी एखादी टीम तयार करता येईल काय? याचा पोलीस खात्याने विचार करावा. एकूणच पोलीस खात्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा हयुमन रिसोर्सेस म्हणून विचार केला तर या हयुमन रिसोर्सेसची मॅनेजमेंट करण्याची आधुनिक साधने आहेत किंवा शास्त्र आहेत त्याचा अभ्यास आपल्या खात्यात कुठे हेातो काय? तसेच त्यातील एखादा तज्ञ आपल्या सगळया हयुमन रिसोर्सेशी संबंधीत आहे याकडे पोलीस खात्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

सभापती महोदय, आपल्याकडे नेहमी असे हटले जाते की, आयपीएस कॅडर विरुध्द महाराष्ट्र कॅडर अशा प्रकारचा विसंवाद वारंवार वर्तमानपत्रातून वाचायला मिळतो. त्याच्यासाठी काय करता येईल याचाही विचार पोलीस खात्याने निश्चितपणे करणे आवश्यक आहे. जसजशी पोलिसांची सेवा वाढत जाते तसतशी त्यांच्या आरोग्याबद्दल त्यांच्या फिटनेसबद्दल अनेक प्रश्न

..2..

श्री. हेमंत टकले.....

निर्माण होतात त्यामुळे फिटनेस टेस्ट आणि पोलिसांचे आरोग्य यामध्ये जर ते पास होऊ शकले नाहीत तर त्यांना तेथून दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे किंवा त्यांना योग्य तो वेळ देऊन ते पुन्हा फिट होण्याच्या दृष्टिकोनातून यंत्रणा असण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस खात्यातील कर्मचारी किंवा बाकीच्या सगळया लोकांची जीवनपध्दती कशा प्रकारची आहे याबाबतीत बारकाईने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सभापती महोदय, मला गेल्या कित्येक वर्षात सायकलवरुन फिरणारा पोलीस बघायला मिळालेला नाही. आता पोलिसांना सायकल आठवते काय? याबद्दलच मला शंका वाटते. न्यायदानाचे काम करणाऱ्या न्यायाधिशांना सामाजिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी होताना काही पथ्य पाळायला लागतात. पोलिसांची समाजाचे रक्षण करण्याची भूमिका तर आहेच पण स्वात:साठी एक प्रकारची अलिप्तता या पोलीस खात्यातील अधिकाऱ्यांनी बाळगणे आवश्यक आहे.

सभापती महोदय, पोलिसांच्या अनेक वसाहती आहेत. अनेक ठिकाणी त्यांना घेरे देण्यात येतात अनेक सुख-सोयी देण्यात येतात. पण पोलिसांचे कुटुबिय आणि त्यांची तरुण, वयात आलेली मुले ज्यांची कदाचित इतर घरामध्ये होते तशी अवस्था होत असेल की, आपणही पोलीस खात्यात जावे पण पोलीस खात्यात जाता येत नसेल तर गैरमार्गाला लागण्याचे प्रमाण पोलिसांच्या कुटुंबियांमध्ये किती आहे? याचाही एकदा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या राज्याला अनेक महत्वाचे अधिकारी आणि कर्मचारी पोलीस खात्याने दिलेले आहेत. त्यांच्याजवळ माहितीचा भरपूर साठा आहे. या माहितीचे संकलन करुन प्रत्येक जिल्हयाची आणि प्रत्येक ठिकाणाची जी माहिती आहे त्याची डेटा बँक करता आली आणि ती उपलब्ध झाली तर नव्याने येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्याठिकाणी काम करणे सोयीस्कर होईल्. पोलीस खात्याची अशा प्रकारची पुर्नरचना होणे मला अत्यावश्यक वाटते. त्यादृष्टीने पावले टाकावीत. गृहमंत्री माननीय श्री. आर.आर.पाटील यांच्याकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत. सभागृहाच्याही त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत त्या अपेक्षांची पूर्तता ते करतील असा विश्वास मला वाटतो. सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद देतो आणि मी येथेच थांबतो.

यानंतर श्री. बरवड...

अमुद्रित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. परशुराम उपरकर (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, या ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलत असताना मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि कोकणातील कायदा व सुव्यवस्थेवर बोलणार आहे. 26/11 चा प्रकार घडल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चार गस्ती नौका देण्यात आल्या. कृष्णाई, अस्मिता, सावित्री, अल्वासनी अशा चार गस्ती नौका देण्यात आल्या. या गस्ती नौका अजूनही समुद्राच्या किनाऱ्याला लागलेल्या आहेत. कारण या गस्ती नौकांना प्रशिक्षित स्टाफ दिलेला नाही. पाच वर्षापूर्वी एक गस्ती नौका दिली होती तिला इंधन तसेच प्रशिक्षित स्टाफ न दिल्यामुळे ती सडली आणि देवगड बंदरामध्ये आता ती नौका लिलावात काढली. आता ज्या गस्ती नौका दिलेल्या आहेत त्याही तशाच पडून आहेत. या नौका भाड्याने घेतलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी हाय अलर्ट सांगूनही मालवणमधील गस्ती नौका किल्ल्याच्या पाठीमागे जाते, नांगर घालते आणि गस्ती नौकेवर असलेले सर्व पोलीस झोपतात आणि सकाळी उठून परत येतात. अशा प्रकारची त्यांची गस्त आहे. नौकेवरील जी व्यवस्था आहे ती कार्यरत केली जात नाही. अशा पध्दतीने या गस्ती नौकेच्या बाबतीत असलेले कमीशन खाण्याचे काम पोलिसांकडून होत आहे. कारण ती नोका कमी वेळ फिरल्याने कमी डिझेल लागल्यामुळे त्यांना टेंडरनुसार दिवसाच्या मिळणाऱ्या अनुदानाची रक्कम पोलीस विभागाकडे घेऊन पोलीस विभाग आणि बोटमालक यांच्याकडून संगनमताने पैसे खाण्याचे काम चालू आहे. याची चौकशी व्हावी. अनेक हल्ले समुद्र मार्गाने झालेले असताना आणि अनेक वेळा हाय अलर्ट सांगितले असताना सुध्दा अशा प्रकारे या गस्ती नौकांचा दुरुपयोग होऊन या गस्ती नौका गस्त न घालता पैशासाठी वेगळया पध्दतीचे काम चालले आहे त्याकडे लक्ष देण्यात यावे अशी मी मागणी करतो.

सभापती महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जुने एस.पी. गेल्यानंतर नवीन एस.पी. आले. या एस.पी. च्या काळात दारु, मटका, जुगार एवढ्या जोरात चालू आहे की, लोकांना बोलवून दारु, मटके चालू करा असे सांगितले जाते. त्या ठिकाणी बांद्यामध्ये गोवा राज्यातील दारु आणताना कर्नाटकमधील नागराज यांना पकडले. त्या नागराजला सोडविण्यासाठी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पैसे खाल्ले आणि वरच्या अधिकाऱ्याला मिळाले नाही म्हणून वरच्या अधिकाऱ्याशी भांडण झाले आणि मग गोव्याच्या हॉटेलमध्ये जाऊन दोघांनी तोडबाजी केली. कर्नाटकमधील नागराज नावाच्या दारु

...2...

RDB/ MMP/ SBT/

श्री. परशुराम उपरकर .....

तस्करीमधील मोठ्या व्यापाऱ्याला सोडविण्यासाठी, त्याला वाचविण्यासाठी या पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मदत झालेली आहे. एवढेच नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नवीन निवडून आलेले आमदार श्री. जठार यांना गुन्ह्यामध्ये गुंतवू नये म्हणून तिकडचे डी.वाय.एस.पी श्री. परकाळे यांनी साडेचार लाख रुपये मागितले. ते दिले नाही म्हणून त्यांनी गुन्हा नोंदवला आणि मग त्यांनी हायकोर्टातून जामीन घेतला. हायकोर्टाने गुन्हा कसा काय नोंदविला अशा प्रकारचे ताशेरे ओढले आणि हायकोर्टाने त्यांना जामीन दिला. म्हणजे पोलीस अधिकारी एखाद्या आमदाराला सुध्दा जर तू पैसे दिले नाहीस तर मी तुझ्यावर गुन्हा नोंदवीन असे सांगतात आणि खुनासारख्या गुन्ह्यामध्ये आमदाराला गुंतविण्याचे धाडस अधिकारी करीत आहेत. त्या अधिकाऱ्यांची खऱ्या अर्थाने चौकशी झाली पाहिजे आणि अशा अधिकाऱ्यांवर योग्य पध्दतीने कारवाई झाली पाहिजे.

सभापती महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोलीस भरतीमध्ये अनेक घोळ झालेले आहेत. माननीय गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांना काही एसएमएस आले आणि त्यांनी त्या ठिकाणी डीआयजींना पाठविले. डीआयजींनी आणि आम्ही चौकशी केल्यानंतर पहिली यादी दुसऱ्या दिवशी नव्हती आणि दुसरी यादी तिसऱ्या दिवशी नव्हती आणि ेगवेगळ्या याद्यांमुळे मुलांमध्ये आणि पालकांमध्ये फार नैराश्य निर्माण झालेले आहे. पालकांना विचारले तर ते सांगतात की आमच्याकडे देण्यासाठी 1 लाख रुपये नाहीत, 2 लाख रुपये नाहीत. अशा प्रकारच्या तक्रारी पालकांकडून होत आहेत. त्यामुळे या भरतीच्या संदर्भात सुरुवातीपासून जे काही घडले आहे त्याची पूर्णपणे वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशी होण्याची गरज आहे. या ठिकाणी पोलीस कल्याण निधीच्या नावाखाली आता प्रत्येक पोलीस स्टेशनला 9 लाख रुपयांचा टार्गेट दिलेला आहे. मग येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहन चालकांकडून पावत्या फाडणे, नाटकाची तिकिटे फाडणे, त्या नाटकाच्या तिकिटावर कोणत्याही प्रकारचा रजिस्ट्रेशन नंबर नाही आणि अशा पध्दतीने पैसे गोळा करण्याचे काम चालू आहे. कोणती तरी नाटके आणून लावावयाची असा प्रकार सुरु आहे. हे पैसे खऱ्या अर्थाने पोलीस कॉन्स्टेबलला मिळतात काय, पोलिसांच्या कल्याणासाठी हे पैसे खर्च होतात काय, याबाबत माहिती घेतली असता पोलिसांच्या कल्याणासाठी हे पैसे खर्च न होता जे पोलीस अधिकारी येतात त्यांचे चोचले पुरविणे,

...3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ MMP/ SBT/

श्री. परशुराम उपरकर .....

त्यांची ऊसबस करणे यावर खर्च केला जातो अशी माहिती पोलीस कॉन्स्टेबलकडून मिळालेली आहे.

सभापती महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटल्यानंतर रमेश गोवेकर यांचे नाव येणार. त्या ठिकाणी पोट निवडणुकीपासून रमेश गोवेकर गायब झाला आहे. सी.आय.डी.कडे चौकशी दिली होती. कोर्टाने त्याबाबतची चौकशी सी.बी.आय. कडे वर्ग केली. हायकोर्टाने सी.बी.आय.ला सांगितले की, चार महिन्यात त्यांच्या कुटुंबियांना कळवा. त्याची आई गेल्या महिन्यामध्ये मृत्युमुखी पडली. चार महिन्यात कळविले नाही. आज चार वर्षे झाली. ती केस बंद केली. हायकोर्टाला कळविले पण त्याच्या कुटुंबियांना कळविले नाही. रमेश गोवेकर कोठे आहे, काय आहे, कोठे बेपत्ता झाला आहे हे कळत नाही.

यानंतर श्री. खंदारे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.परशुराम उपरकर....

दुसरे श्री.अंकुश राणे हे एका जबाबदार मंत्र्यांचे भाऊ आहेत. त्यांचा अद्याप तपास लागलेला नाही. हे प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग केले आहे. परंतु त्या खूनाचा तपास लागत नाही. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कोणत्याही केसचा तपास नाहीत अशी परिस्थिती आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये आमचे श्री.वैभव नाईक यांच्यावर माणगावमध्ये लोकांनी रिव्हॉल्व्हर रोखले. ते लोक स्वाभिमानी संघटनेचे कार्यकर्ते होते असे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याचा तपास गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे देण्यात आला. पण गुन्हा अन्वेषण विभागाने तो तपास थांबविला आहे. त्यातील कोण गुन्हेगार आहेत ते समजले नसल्यामुळे गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत हा तपास पुन्हा सुरु करण्यात यावा. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील श्री.प्रमोद जठार यांच्या निवडणुकीनंतर श्री.बाळा वळंजू यांची पोटनिवडणूक लागली आहे. ते जळून मृत्युमुखी पडले अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या. त्यांचा जळून मृत्यू झाला की कसा झाला ते माहीत नाही. एका जबाबदार मंत्र्यांनी वृत्तपत्र वाहिन्यांमध्ये सांगितले की, मोबाईलचा स्फोट झाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्याचा मृत्यू कसा झाला त्याची माहितीच मिळत नसल्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मी मागणी करतो. त्याचप्रमाणे सुदिन बांदिवडेकर नावाचे कणकवलीचे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यावर दिवसा ढवळया तलवारी घेऊन हल्ला झाला. हे हल्लेखोर कोण आहेत, त्यातील दोन हल्लेखोर बेपत्ता आहेत. अशाप्रकारचे हल्लेखोर कोण आहेत ते समोर आले पाहिजे. याच निवडणुकीतील श्री.रजनीश निर्मल नावाचे कर्तव्यदक्ष अधिकारी होते. पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्यासाठी येणा-या माणसांना मारहाण केली म्हणून या निर्मलने पोलीस स्टेशनमध्ये आपली तक्रार नोंदविली. तक्रार नोंदविल्यानंतर एस.पीं.च्या माध्यमातून रातोरात 12.30 वा. त्यांची बदली करण्यात आली. तेथील सर्वपक्षीय लोकांनी मोर्चा काढला होता. त्यासंबंधी निवडणूक आयोगाने अहवाल मागविल्यानंतर ती बदली रद्द करण्यात आली. चुकीच्या पध्दतीने व निवडणूक आयोगाला न विचारता ती बदली केली होती ती कोणी व कशी केली, कशाच्या आधारे केली त्याचा तपास होण्याची आवश्यकता आहे. सावंतवाडीचे श्री.केतकर नावाचे पोलीस निरीक्षक सेवानिवृत्त झाले. सकाळ वृत्तपत्रामध्ये जाहिराती आल्या.

2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.परशुराम उपरक....

मायनिंगचे तस्करी करणारे यांनी त्या जाहिराती दिल्या. त्या जाहिरातीमध्ये शुभेच्छा देणारे जुगार, मटका चालविणारे यांचा समावेश आहे. म्हणजे त्या केतकरांनी त्यांच्या काळात जुगार, मटका, मायनिंगची तस्करी करण्यासाठी सपोर्ट केला त्यामुळे निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जाहिरातीमध्ये शुभेच्छा देण्यात आल्या. या सर्व प्रकरणांची सीबीआय व सीआयडीकडून चौकशी करावी. श्री.जठार यांना श्री.परकाळे यांनी गुन्हयामध्ये गुंतविण्यासाठी पैसे मागितले त्यांची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी. ते लोकप्रतिनिधींना गुंतविण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी विनंती करतो. मला वेळ दिल्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो आणि माझे भाषण संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.

3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

NTK/ MMP/ SBT/

श्री.भगवानराव साळुंखे (पुणे विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदय, श्री.आर.आर.पाटील हे दुस-यांदा गृहमंत्री झाले. परंतु पहिल्यांदा गृहमंत्री झाले होते त्यावेळी त्यांनी राज्याला 4 अभिवचने दिली होती. हिवाळी अधिवेशनात गुटखा बंदीचे अभिवचन दिले होते. पण गुटखा बंद झालेला आहे. या गुटख्याचा तरुण पिढीवर दुष्परिणाम होत आहे, ही पिढी त्याच्या आहारी गेल्यामुळे नानाविध आजाराच्या विळख्यात अडकत आहे. त्यासाठी जरुर काही तरी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्यातील मटका बंद करु असे सांगितले होते. परंतु मटका बंद तर झ ााला नाहीच उलट आणखी फोफावला आहे. ऑन लाईन लॉटरीच्या माध्यमातून सबंध महाराष्ट्रात दिसत आहे. एकॉमिक्स ऑफ मटका हे काढले तर महाराष्ट्राच्या बजेटच्या काही टक्का ते होईल इतके या मटक्याचे अर्थशास्त्र आहे. त्याच्यावर मर्यादा आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांची घरेच्या घरे उद्ध्वस्त होत आहेत.

यानंतर श्री.शिगम.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(श्री. भगवान साळुंखे...

सामान्य माणसी घरेदारे उद्ध्वस्त होत आहेत. माननीय गृहमंत्र्यांनी बेकादेशीर सावकारकी बंद केली जाईल असा शब्द सभागृहामध्ये दिला होता. परंतु अजूनही राज्यातून ही बेकायदेशीर सावकारकी नाहीशी झालेली नाही. या बेकादेशीर सावकारकीच्या माध्यमातून अनेक गावातून गरीब शेतक-यांकडून जमीन जुमला, घरदार लिहून घेऊन त्यांना उद्ध्वस्त केले जात आहे, त्यांचे प्रचंड आर्थिक शोषण केले जात आहे. ही बेकादशीर सावकारकी बंद करणे आवश्यक आहे.

सभापती महोदय, शहरातील डान्स बार बंद करण्यात आलेले असले तरी ते चालू असल्याचे काही सन्माननीय सदस्यांनी माननीय मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून दिलेले आहे. डान्सबार बंद केल्यामुळे या बारबाला विस्थापित झालेल्या आहेत. त्यांचे पुनर्वसन कसे होईल यादृष्टीने शासनस्तरावर निर्णय व्हायला पाहिजे. हे डान्स बार बंद झाल्यानंतर या बारबाला खेडयामध्ये येऊन यात्रामधून नाचगाणी करुन तरुण पिढीला आकर्षित करुन एड्स सारख्या रोगाला बळी पाडत आहेत. तेव्हा या बारबालांच्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात शासनाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

सभापती महोदय, आणखीन एका महत्वाच्या मुद्याकडे मला माननीय मंत्री महोदयांचे लक्ष वेधावयाचे आहे. पोलिसांच्या कारभारामध्ये राजकीय मंडळींचा खूप हस्तक्षेप होतो. या राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांना नीटपणे काम करता येत नाही. त्यांच्या गुणवत्तेवर आणि निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर त्यामुळे मर्यादा पडतात. तेव्हा पोलिसांच्या कारभारामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये यासाठी काही कोड ऑफ कॉंडक्ट करता येईल का हे पाहिले पाहिजे. या सगळयाचा परिणाम असा होतो की महाराष्ट्रामध्ये जी तरुण पिढी आहे ती ताणतणावामुळे मृत्यूला बळी पडत आहे. वयाच्या पस्तीशीच्या आज मृत्यू पावण्याचे प्रमाण 10 टक्क्याच्या आसपास आहे. खरे म्हणजे ही तरुण पिढी दीर्घायुषी व्हायला पाहिजे. परंतु ती सहा षड्रिपुंनी ग्रासलेली आहे. त्यातील पहिला रिपू एडस् आहे. दुसरा लिव्हर सोरायसेस, मध्यपानामुळे होणारे विकार, तिसरा रिपू तंबाखुच्या व्यवसामुळे होणारा कॅन्सर, चौथा रिपू वाढता हिंसाचार, पाचवा रिपू अपघात, नशापाणी करुन भरधाववेगाने गाडी चालविल्यामुळे हे तरुण स्वत: मरतात आणि दुस-यालाही मारतात आणि सहावा रिपू म्हणजे मानसिक ताणतणाव. मेण्टल हॅरॅसमेण्ट मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे. कार्यालयामध्ये एखादा चांगला काम करणारा तरुण असेल तर त्याच्यावर मानसिक दबाव आणला

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

जातो आणि त्यामुळे तो वयाच्या पंचवीशीमध्ये तिशीमध्ये मरतो. या षड्रिपुवर इलाज करण्यासाठी आपल्याला उपाययोजना केली पाहिजे. एवढे बोलून मी आपली रजा घेतो.

--

...3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

उपसभापती : या प्रस्तावावर बोलण्यासाठी ज्या ज्या सदस्यांनी नावे दिलेली होती त्यांची भाषणे झालेली आहेत. मी या प्रस्तावावर बोलणार नाही. परंतु या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने एक सूचना या ठिकाणी नक्कीच मांडू शकतो आणि ती माननीय मंत्री महोदयांनी गांभीर्याने घ्यावी. ठाणे येथील वर्तकनगर भागामध्ये म्हाडाकडून पोलीस आयुक्तालयाला एक इमारत पोलीस कर्मचा-यांसाठी गेल्या काही वर्षापासून भाड्याने दिली गेली आहे. सदर इमारतीत बरेचसे कर्मचारी राहातात. त्यातील बरेचसे कर्मचारी निवृत्तही झालेले आहेत. ही इमारत पोलीस आयुक्तालयाच्या मालकीची नसून म्हाडाच्या मालकीची आहे. त्या इमारतीचे ब-याच वर्षाचे भाडे दिलेले नाही. 4 वर्षापूर्वी जवळपास 72 लाख रुपये भाडयापोटी देणे होते, ही रक्कम आता जवळपास दुप्पट झाली असेल. हे भाडे म्हाडाला देणे पोलीस आयुक्तालयाकडून बाकी आहे. इतकेच नव्हे तर त्या इमारती इतक्या पडक्या अवस्थेत आहेत की, त्या इमारती कधीही पडून जीवित आणि वित्त हानी होण्याची शक्यता आहे. ही बाब मी आपल्या विभागाला कमीत कमी गेल्या पाच ते सहा वर्षात चार ते पाच वेळा निदर्शनास आणून दिलेली आहे आणि लेखीही दिलेले आहे. परंतु अद्यापपर्यन्त याची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही. मी आज या ठिकाणाहून आपणास असे सुस्पष्ट निर्देश देतो की, या संदर्भात एक बैठक घ्यावी. त्या बैठकीस माननीय पोलीस आयुक्तांना व पोलीस महासंचालकांना बोलवावे, मी स्वत: त्या बैठकीस हजर असेन. शेवटी या संदर्भात सर्व कर्मचा-यांनी विनंती केलेली आहे. म्हाडा परिसरातील जेवढया इमारती आहेत त्या इमारतीमधील सगळया भाडेकरुंनी एकत्रितरीत्या त्या त्या इमारतीप्रमाणे आपापल्या सोसाटया केल्या. या इमारती म्हाडाने काही अटींवर त्यांना विकत दिल्या. अशा प्रकारे त्या इमारती त्यांना हस्तांतरीत केल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या सोसायटया तयार केल्या. आज बरेचसे पोलीस कर्मचारी त्या ठिकाणी राहात आहेत, त्यातील काही निवृत्तही झालेले आहेत. त्यांची मुले पोलीस खात्यात कामाला आहेत.शेवटी राज्य शासनाचा नियम म्हणून त्यांना ते करावे लागत आहे. त्यांना मी दोष देत नाही. परंतु अशा लोकांना तुम्ही ताबडतोब खाली करायला लावले.

...नंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

उपसभापती.........

ही जी बाब आहे ती अत्यंत गंभीर आहे. कारण या संदर्भात मी स्वत: सांगितले आहे. चार ते पाच वेळा मागील सहा वर्षाच्या काळात व्यक्तिगतरित्या पत्र लिहिले आहे. पोलीस महासंचालकांच्या रेकॉर्डवर ही गोष्ट आहे. 72 लाख रुपये अधिक मागील चार वर्षाचे भाडे थकित आहे. ही रक्कम पोलीस आयुक्तांनी म्हाडाला द्यावयाची आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या इमारतींची तपासणी केल्यानंतर सा.बां.विभागाने दिलेल्या अभिप्रायाप्रमाणे या सर्व इमारती दुरुस्त करण्यापलिकडे गेलेल्या आहेत. अशा अवस्थेत त्याठिकाणी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. ती मागणी रितसर ताबडतोब मंजूर करावी अशा प्रकारची त्यांची मागणी गृह विभागाकडे आलेली आहे. मी देखील विनंती केली आहे. काय घ्यायचा तो निर्णय ताबडतोब सात दिवसात घेण्यात यावा. कारण पुढे पावसाळा सुरु होईल. तत्कालीन पोलीस महासंचालक यांनी धोरणात्मक निर्णय होईल की काय असे म्हटले होते. पोलीस कर्मचाऱ्यांकरिता ज्या इमारती पोलीस विभागाच्या मालकीच्या आहेत त्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा किंवा कसे ही बाब वेगळी आहे. परंतु भाड्याच्या घरात पोलीस कर्मचारी रहात आहेत. त्या इमारतीचे भाडे दिले जात नसेल, दुरुस्ती केली जात नसेल तर तिथे राहणारे कर्मचारी भाडे देणार असतील तर द्यायला हरकत नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. अशा प्रकारची बरीचशी उदाहरणे आहेत. त्या लोकांनी इमारती घेतल्या आहेत. हा निर्णय सात दिवसाच्या आत होणे आवश्यक आहे. हा निर्णय मी दिला नसता. परंतु पाच-सहा वेळा पत्र लिहून देखील गृह विभागाकडून औदासिन्य दाखविण्यात येते ही बाब योग्य नाही. म्हणून येत्या सात दिवसात पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सोसायटीचा एक प्रतिनिधी व मी स्वत: आणि गृहराज्यमंत्री यांची एक बैठक घेण्यात यावी.

श्री.रमेश बागवे : सभापती महोदय, होय. आपण दिलेल्या निदेशाची दखल घेऊन बैठक घेण्यात येईल.

डॉ.नीलम गोऱ्हे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.जयंत प्र.पाटील यांनी सुरक्षा व्यवस्थेच्या संदर्भात प्रस्ताव उपस्थित केला होता. मला एका प्रश्नासंदर्भात मार्गदर्शन हवे आहे. आम्ही विधानभवनामध्ये येतो. आमदार महोदयांनी स्वत:ची बॅग किंवा महिला आमदारांनी पर्स धातू शोधक यंत्रामध्ये टाकली पाहिजे की नाही? मला काही वेळेला वाद घालायला आवडत नाही म्हणून

..2..

डॉ.नीलम गोऱ्हे.........

माझी पर्स धातू शोधक यंत्रामध्ये टाकते. परंतु हे जास्त होत आहे. जे असेल ते नियमाने व्हावे. आमदारांच्या बॅग किंवा पर्स धातू शोधक यंत्रामध्ये टाकल्या पाहिजेत का? मग सगळ्या मंत्र्यांना सुध्दा तो नियम लागू करावा.

उपसभापती : ज्यावेळी 3 मार्च, 2010 रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली, या बैठकीच्या अगोदर सुरक्षाविषयक एक बैठक झाली. सन्माननीय सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक, आणि मी स्वत: त्या बैठकीला उपस्थित होतो. सुरक्षेच्या संदर्भात कोणतीही तडजोड करावयाची नाही असे ठरल्यामुळे या गोष्टीला सामोरे जावे लागत असेल. सुरक्षेविषयी आपण कमी जास्त न करणे उत्तम. थोडासा त्रास सहन करावा एवढी विनंती करतो.

सभागृहाची विशेष बैठक आता स्थगित होत असून दुपारी 12.45 वाजता सभागृहाची नियमित बैठक सुरु होईल.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 12.23 ते 12.45 वाजेपर्यंत स्थगित झाली.)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(स्थगिती नंतर)

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती)

पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तरे

मुंबई विभागातील विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देऊन त्यांना सेवेत कायम करण्याबाबतची कार्यवाही

(1) * 3518 **श्री.कपिल पाटील , श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी , श्री.जयंत पाटील** : सन्माननीय **शालेय शिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(1) शासनाने परिपत्रक काढूनही मुंबई विभागातील विना अनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता अद्यापही दिली नाही, हे खरे आहे काय,

(2) असल्यास, वैयक्तिक मान्यता न दिल्यामुळे शाळा अनुदानावर येताच संस्थाचालक जुन्या शिक्षकांना सेवेतून कमी करतात हे ही खरे आहे काय,

(3) असल्यास, याबाबत शासन कोणती कार्यवाही वा उपाययोजना करणार आहे?

श्री.बाळासाहेब थोरात : (1) व (2) हे अंशत: खरे आहे. या संदर्भातील कार्यवाही तातडीने करण्याबाबतच्या सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

(3) प्रश्न उद्‌भवत नाही.

श्री. कपिल पाटील : महोदय, हा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. मुंबई विभागातील 1240 कायम विना अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्यातील 25 हजार शिक्षकांचा हा प्रश्न आहे. मंत्री महोदयांनी पहिल्या प्रश्नाला "हे अंशत: खरे आहे" असे उत्तर दिले आहे. परंतु शेवटच्या प्रश्नाला मात्र"प्रश्न उद्‌भवत नाही" असे उत्तर दिलेले आहे. कदाचित हा यंत्रणेचा दोष असावा. गेली अनेक वर्षे हे शिक्षक काम करीत आहेत, त्यांना सर्व्हिस बुक नाहीत, पर्सनल ॲप्रुव्हल नाही. अशा परिसिथतीत या सर्व शिक्षकांची सर्व माहिती मागवून त्यांना व्यक्तिगत मान्यता देण्याचे काम शासन तातडीने करणार काय ? तसेच हा प्रस्ताव संस्थांकडून शासनाकडे येणार नाही हे लक्षात घेऊन स्वत:हून ही माहिती मागवावी व मान्यता द्यावी. तसेच वेतनाच्या संदर्भात सुध्दा अमलबजावणी शासन करणार काय ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : महोदय, सन्माननीय सदस्यांच्यामागणीप्रमाणे यापूर्वी 7 मार्च, 2009 ला सूचना दिल्या आहेत. अशा प्रकारच्या सूचना शिक्षण संचालकांना तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनाही दिलेल्याआहेत. त्यामुळे यामध्ये जे काम अपूर्ण असेल ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने तसेच जसे सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले त्यादृष्टीने काम केले जाईल.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.3518.......

श्री. वसंतराव खोटरे : सभापती महोदय, राज्यात कायम विना अनुदानित तत्वावर ज्या शाळा आहेत त्यातील "कायम" हा शब्द शासनाने काढून टाकला त्याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन करतो. परंतु या शाळांना संच मान्यता दिलेली नाही, व्यक्तिगत मान्यताही दिलेल्या नाहीत, सर्व्हिस बुक दिलेले नाहीत. हा प्रश्न केवळ मुंबईपुरताच मर्यादित नसून संपूर्ण राज्याचाच प्रश्न आहे. दि. 7 मार्च, 2009 रोजी शासनाने एक परिपत्रक काढून संबंधितांना सूचना दिल्या आहेत. तरी देखील त्यानुसार अद्यापही कार्यवाही झालेली नाही. म्हणून शासन याबाबत कडक धोरण स्वीकारणार काय ? तसेच संच मान्यता आणि व्यक्तिगत मान्यता देऊन अशा शाळांमध्ये रोष्टरप्रमाणे नेमणुका करण्यात येणार आहेत काय ? दुसरा प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालये सुध्दा कायम विना अनुदान तत्वावर दिलेली आहेत. त्यात गरिबांच्या मुलींना शिक्षण मिळत आहे. परंतु त्यातील "कायम" हा शब्द अद्यापही काढलेला नाही. म्हणून हा "कायम" शब्द देखील या अधिवेशनापूर्वी काढण्यासंबंधीचा निर्णय घेणार काय ? कारण दिनांक 25 मार्च, 2010 पासून कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक आझाद मैदानावर उपोषणासाठी बसलेले आहेत. म्हणून शासन हा निर्णय ताबडतोब घेणार काय ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, हा प्रश्न वेगळ्या पध्दतीने उपस्थित करावा लागणार आहे. पहिला प्रश्न हा राज्याशी निगडित असा प्रश्न असून दि. 7 मार्च, 2009 ला यासंबंधीच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि एक वर्षात त्यांनी जे काम केले आहे त्यात संच मान्यता आणि व्यक्तिगत मान्यता यासंबंधी संगणकीकृत काम करुन बरेचसे काम झालेले आहे. ऑनलाईन हे काम करण्याचे सुरु आहे. तसेच विनाअनुदानित कायम विना अनुदानित तसेच अनुदानित अशा सर्व बाबतीत हे काम करणे आवश्यक आहे. यासंबंधी एक शिबीर घेऊन लवकरात लवकर कारवाई केली जाईल.

श्री. जयंत प्र.पाटील : महोदय, मंत्री महोदयांची काय अडचण आहे हे मला कळत नाही. विना अनुदानित तत्वावरील शाळांमध्ये जे शिक्षक काम करीत आहेत त्यांना मान्यता देण्याबाबत अनेक वेळा अडचणी येतात. मी 40 विनाअनुदानित शाळा चालवितो. त्या शाळांना मान्यता देताना 50 हजार रुपये मागतात....

यानंतर श्री. जुन्नरे ...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र. :3518......

श्री. जयंत प्र.पाटील ......

त्यामुळे ज्या कायम विनाअनुदान व विना अनुदान तत्वावरील शाळा आहेत त्यासंदर्भात ताबडतोब निर्णय करुन या शाळांना मान्यता देईल काय ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, जे शैक्षणिक वर्ष सुरु होईल त्या वर्षामध्ये संच मान्यता आणि व्यक्तीगत मान्यतेच्या बाबतीत शिबीर पध्दतीने निर्णय घेण्यात येईल. दोन शिबीरामध्ये यासंदर्भात निर्णय घेऊ व ज्या बाबींची पूर्तता राहिलेली आहे त्यासाठी तिसरे शिबीर घेऊन संच मान्यता आणि व्यक्तीगत मान्यतेची कार्यवाही केली जाईल. यामध्ये जर कोणाची वैयक्तिक तक्रार असेल तर संबंधितावर कारवाई करण्यास शासनाची तयारी आहे.

श्री. रामनाथ मोते : सभापती महोदय, राज्यातील विना अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांच्या मान्यतेच्या संदर्भातील हा विषय आहे. या राज्यातील सर्व खाजगी शाळांना 1981 ची नियमावली लागू आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने मी मंत्रीमहोदयांना विचारु इच्छितो की, 1981 च्या नियमावलीमध्ये शिक्षकांची मान्यता घेण्याच्या संदर्भात कोणत्या तरतूदी या कायद्यामध्ये नसल्यामुळे अडचणी येतात, त्या बाबतीत विचार करुन 1981 च्या नियमावलीमध्ये शासन दुरुस्ती करणार आहे काय ? संच मान्यता व वैयक्तिक मान्यता घेणे हे आपण प्रत्येक शाळेवर बंधनकारक करणार आहात काय ? तसेच सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्याचा फायदा अनुदानित शाळांना मिळाला कारण या शाळांना शासनाकडून अनुदान मिळत असते. परंतु विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित ज्या शाळा आहेत त्यांना शासनाकडून नव्हे तर संस्थांकडून पगार दिला जात असतो. यासाठी जो जी.आर.निघाला तो अनुदानित शाळांसाठी निघाला आहे. खरे म्हणजे हा जी.आर.नियमाप्रमाणे या शाळांनाही लागू होऊ शकतो. पण त्यामध्ये " विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित " असा शब्द नसल्यामुळे अनेक संस्थाचालक पगार देण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील जो प्रस्ताव प्रलंबित आहे त्यासंदर्भात आपण तातडीने निर्णय घेणार आहात काय ?

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

...2

04-01-2010 (असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही) S-2

ता.प्र.क्र. :3518......

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, संच मान्यता आणि व्यक्तिगत मान्यतेच्या संदर्भात विभागाला सूचना 7 मार्च, 2009 रोजी दिलेल्या आहेत. या शाळातील शिक्षकांना पगार देणे हे बंधनकारक आहेच. तसेच सन्माननीय सदस्यांनी 1981 च्या नियमावलीतील कोणत्या गोष्टीमुळे अडचणी येतात, असा प्रश्न विचारलेला आहे. मी यासंदर्भात सांगू इच्छितो की, ही बाब तपासून कार्यवाही केली जाईल.

...3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

आद्यशिक्षिका व स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी आधुनिक शैक्षणिक केंद्र उभारण्याची शासनाच्या विचाराधीन बाब

(२) * ३६७७ श्री.दिवाकर रावते , डॉ.निलम गोऱ्हे , श्री.किसनचंद तनवाणी : सन्माननीय **शालेय शिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आद्यशिक्षिका व स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी आधुनिक शैक्षणिक केंद्र उभारण्याची बाब, शासनाच्या विचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजनेचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे,
(३) तसेच उक्त योजनेसाठी किती निधीची आवश्यकता आहे व सदर काम किती कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे?

श्री. बाळासाहेब थोरात : (१), (२) व (३) असा प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सातारा जिल्हयाचे सन्माननीय पालक मंत्री श्री. रामराजे निंबाळकर यांनी आद्यशिक्षिका व स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नायगाव जन्मगावी त्यांच्या जन्म दिनी तेथे जमलेल्या जमावापुढे या गावात आधुनिक शैक्षणिक केंद्र उभे करु व हे केंद्र तातडीने मंजूर करुन घेऊ, अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे माननीय पालक मंत्र्यांनी जी घोषणा केलेली आहे त्यासंदर्भातील माहिती मंत्रीमहोदयांना आहे काय तसेच तशा प्रकारचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हयाकडून आणि माननीय पालक मंत्र्यांकडून शिक्षण खात्यास प्राप्त झाला आहे काय ?

श्री. बाळासाहेब थोरात :सभापती महोदय, आद्यशिक्षिका व स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या जन्मदिनी सातारा येथे दर वर्षी कार्यक्रम होत असतो. या कार्यक्रमाला काही पाहुणे मंडळीही जात असतात. सन्माननीय सदस्य श्री. दिवाकर रावते यांनी विचारले आहे की, सातारा जिल्हयाचे पालक मंत्री श्री. रामराजे निंबाळकर यांनी नायगाव येथे शैक्षणिक संकूल उभे करण्याची घोषणा केली होती. याबाबतीत मी एवढेच सांगेन की, आद्यशिक्षिका व स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे नायगाव हे जन्म गाव आहे. हे गाव छोटे आहे. मुलींच्या शिक्षणाची दिशा संपूर्ण राज्याला आणि देशाला देण्याचे काम या विभुतीमुळेच झालेले आहे. आद्यशिक्षिकास व स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी आधुनिक शैक्षणिक केंद्र उभे करण्याच्या संदर्भात जो विचार मांडलेला आहे त्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करुन मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठविला जाईल.

......४

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

डॉ.नीलम गो-हे : सभापती महोदय, आद्यशिक्षिकास व स्त्री शिक्षणाच्या जनक ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले याच्या जन्मदिनी नायगाव येथे शासनाचे प्रतिनिधि म्हणून उपमुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री जात असतात. नायगाव येथे आता सुध्दा काही विकासात्मक कामे सुरु आहेत.

यानंतर श्री. गायकवाड...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.3677....

डॉ.नीलम गोऱ्हे...
सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे उत्तर माननीय मंत्रिमहोदयांनी दिलेले आहे. त्याचे मी स्वागत करते. तसेच या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. याचे कारण शासनाने लेखी उत्तर नकारात्मक दिलेले आहे. माननीय पालकमंत्र्यांनी घोषणा करून देखील आपल्या विभागाकडून नकारात्मक उत्तर देणे हे बरोबर नाही. त्यात बदल झाला पाहिजे. माझा दुसरा प्रश्ना असा आहे की, पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले नाव देणे हा प्रश्न स्वतंत्र आहे. म.फुले यांच्या विचारांचे जतन व्हावे म्हणून पुण्यातील भिडेवाडा यासंबंधी पुणे महानगरपालिकेने पावले उचलली आहेत. पण शासनाने कुठलीही मदत दिलेली नाही. त्यास मदत देण्यासंबंधी शासन विचार करेल काय ? तसेच पुणे विद्यापीठाला सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ असे नाव देण्याचा ठराव साहित्य संमेलनामध्ये झालेला आहे. त्याची अंमलबजावणी शासन करेल काय ?

श्री.बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, येथे उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न वेगळे आहेत. त्यावर भाष्य करणे योग्य होणार नाही. पालकमंत्री श्री.रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी भाष्य केले असेल. त्यांच्या प्रस्ताव आमच्या पर्यंत पोहोचला नसल्यामुळे त्यामध्ये आम्हाला त्रुटी दिसत आहे. त्यांनी कल्पना म्हणून बाब मांडली असेल आणि आपणा सर्वांना तेच वाटते आहे. ते पुढे नेण्याचे काम आम्ही निश्चितपणे करू.

श्री.उल्हास पवार : सभापती महोदय, साहित्य संमेलनामध्ये एका संस्थेने विनंती करणारे पत्र पाठविले की, असा ठराव करा. साहित्य संमेलनाच्या महामंडळाने पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूकडे पाठवावे अशा प्रकारचा ठराव केला. रेकॉर्डवर यावे म्हणून मी येथे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत आहे. साहित्य महामंडळाने एकूण 5 ठराव केले. ते वेगळे आहेत. त्यात हा सहावा ठराव नाही. हे जे निवेदन आले ते पुणे विद्यापीठाकडे विचारार्थ पाठवावे असा ठराव आहे.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष होते. वर्तमानपत्रात साहित्य संमेलनामध्ये ठराव करण्यात आला अशा प्रकारची बातमी आलेली आहेत.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.3677....

श्री.उल्हास पवार : सभापती महोदय, सगळ्या वर्तमानपत्रात नीट लिहून आले आहे. दोन-तीन वर्तमानपत्रात येथे सन्माननीय सदस्यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे बातमी आली आहे.

श्री.दिवाकर रावते : मग आपण खुलासा करायला पाहिजे होता.

श्री.उल्हास पवार : सभापती महोदय, यासंबंधी खुलासा करण्याची आवश्यकता नाही. कारण अनेक वर्तमानपत्रात नीट पूर्णपणाने बातमी आलेली आहे.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, माननीय सदस्य श्री.उल्हास पवार यांनी दिलेली माहिती बरोबर आहे. साहित्य महामंडळ लबाडी करते. हे निवेदन परस्पर दिलेले आहे. या मागणीला पाठिंबा देखील दिलेला नाही. खरे म्हणजे त्या महामंडळाचा निषेध केला पाहिजे, अशी सभागृहाची भावना आहे. या निमित्ताने महामंडळाची लबाडी उघडकीस आलेली आहे, त्यामुळे मी श्री.उल्हास पवार यांना धन्यवाद देतो.

....

...3

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

कर्मचाऱ्यांच्या नजरचुकीमुळे आय.टी.आय. निदेशकांची होत असलेली ससेहोलपट

(३) * ३४०० श्री.रामनाथ मोते , श्री.संजय केळकर , श्री.विनोद तावडे , प्रा.बी.टी.देशमुख , श्री.विक्रम काळे , श्री.व्ही.यु. डायगव्हाणे , श्री.कपिल पाटील , श्री.वसंतराव खोटरे , श्री.जयंत पाटील : तारांकित प्रश्न क्रमांक ५९ ला दिनांक ८ डिसेंबर, २००९ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात : सन्माननीय **उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासन निर्णय व त्याबाबतच्या टिप्पणीमध्ये टंकलेखनाच्या राहून गेलेल्या चुकांमुळे वेतनश्रेण्यांचे आकडे चुकीचे पडल्यासंदर्भात, या चुकांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या विचाराधीन प्रश्नावरील शासनाचा विचार पूर्ण झालेला आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबतची जबाबदारी कोणावर निश्चित करण्यात आलेली आहे,
(३) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या विलंबाची कारणे काय आहेत,
(४) तसेच उक्त चुक दुरुस्त न केल्यामुळे अनेकांची आर्थिक कुचंबणा होत असून अनेकांकडून आर्थिक वसुली करण्यात येत आहे, अनेकांची सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे प्रलंबीत आहेत, अशी तक्रार करणारे जे निवेदन दिनांक २० जून, २००८ रोजी किंवा त्यासुमारास महाराष्ट्र राज्य आय.टी.आय.निदेशक संघटनेच्या सचिवांनी प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांना सादर केलेले आहे ते लक्षात घेता ही चूक दुरुस्त करण्यास होणाऱ्या विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्रीमती वर्षा गायकवाड, श्री.राजेश टोपे यांच्याकरिता : (१) होय.
(२) व (३) जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
(४) रु.७४५०-११५००/- या वेतनश्रेणी ऐवजी शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षकांप्रमाणे रु.७५००-१२०००/- अशी सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. सदर प्रकरणी वित्तीय भार असल्यामुळे शासनाच्या विविध विभागांची मान्यता घेऊन सदर प्रस्तावास मंत्रीमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यावर निर्णय झाल्यावर थकबाकीची रक्कम अदा करण्यात येईल.

श्री.वसंतराव खोटरे : सभापती महोदय, तारांकित प्रश्नोत्तराच्या यादीतील अनुक्रमांक 47 वरील प्रश्न या प्रश्नाशी निगडित आहे. त्यामुळे अनुक्रमांक 47 वरील प्रश्न या प्रश्नाशी जोडण्यात यावा अशी मी विनंती करीत आहे.

सभापती : मी तपासून पाहतो.

श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदय, अनुक्रमांक 47 वरील प्रश्न सारखाच असेल तर तो जोडून घेण्यात यावी अशी माझी विनंती आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या निदेशकांच्या वेतनश्रेणीसंबंधीचा प्रश्न आहे. लेखी उत्तर वाचल्यानंतर शासन मुद्दाम आम्हाला जाणीवपूर्वक क्रोधित करण्याचा प्रयत्न करते की काय ? असे वाटते. प्रत्येक वेळेस आम्हाला आरडाओरड करावी लागते. सन्माननीय सदस्य प्रा.बी.टी.देशमुख हे पोटतिडकीने प्रश्न 4

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.3400

श्री.रामनाथ मोते...

मांडत असतात. त्यामुळे त्यांचा रक्तदाब वाढतो की काय ? अशी भिती आम्हा सर्वांना असते.

श्री.जयंत पाटील : सभापती महोदय, माननीय सदस्य प्रा.बी.टी.देशमुख हे अजून 10 वर्षे या सभागृहात कामकाज करणार आहेत.

सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.बी.टी.देशमुख अजून 25 वर्षे कामकाज करणार आहेत.

श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदय, आमच्यासुद्धा देखील त्याच भावना आहेत.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, आम्हाला क्रोधित करणे हा देखील एक विनोद आहे. आता सन्माननीय सदस्य रक्तदाबाचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे, हा देखील एक विनोद आहे.

श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदय, हाच प्रश्न दिनांक 24 जुलै 2007, 14 डिसेंबर 2008, 8 डिसेंबर 2009 रोजी उपस्थित करण्यात आला होता. येथे स्पेसिफिक असे उत्तर दिलेले आहे.

यानंतर श्री.सरफरे...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/ MMP/ KGS/ SBT/ KTG/ 13:00

ता.प्र.क्र. 3400...

श्री. रामनाथ मोते ...

या वेतनश्रेण्या छापण्यामध्ये आमची चूक झाली आहे, ती आम्ही दुरुस्त करतो. 17 जानेवारी 2004 च्या शासन निर्णयप्रमाणे आम्ही त्यांची अंमलबजावणी करतो, आणि त्याची थकबाकी सुध्दा देतो असे सांगितले. परंतु या संदर्भात अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याठिकाणी 7004 ऐवजी 7005 करणे एवढाच माझा प्रश्न आहे. मत्रिमहोदयांनी असे उत्तर दिले आहे की, अजूनही आम्हाला मंत्रिमंडळासमोर जावयाचे आहे. गेल्या चार वर्षापासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अधिवेशन संपण्यापूर्वी निकाली काढणार काय?

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, येत्या कॅबिनेटच्या मिटींगमध्ये हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

श्री. व्ही. यू. डायगव्हाणे : सभापती महोदय, निदेशकांच्या वेतनश्रेणीचा महत्वाचा प्रश्न आहे. पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीमध्ये यांची आणि शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीमध्ये समतूल्यता होती. परंतु सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीमध्ये तफावत केली आहे. यासंबंधी वारंवार प्रश्न उपस्थित करुन सुध्दा याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे असे उत्तर दिले जाते. हे उत्तर आता नेहमीचे झाले आहे. तेव्हा माझा प्रश्न असा आहे की, कॅबिनेटची मान्यता आपण एक महिन्याच्या आत घेऊन हा प्रश्न निकाली काढणार काय?

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, माननीय सदस्यांची जी भावना आहे तीच सरकारचीही भावना आहे. याबाबत एक आठवडयामध्ये निर्णय घेतला जाईल.

प्रा. बी. टी. देशमुख : सभापती महोदय, दि.1.1.1996 रोजी पासून वेतनश्रेणीत झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी 2010 हे साल उगवते ही या राज्याच्या दृष्टीने दुर्दैवाची गोष्ट आहे. दि.1.1.1996 पासून वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये झालेली चूक दुरुस्त करण्यासाठी दि.17 जानेवारी 2004 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. हा शासन निर्णय माननीय मंत्र्यांनी या सभागृहामध्ये निवेदन केल्यानंतर निघाला. या जी.आर. ची अंमलबजावणी सुरु झाली त्यावेळी लक्षात आले की, सभागृहातील मा.मंत्रिमहोदयांचे निवेदन आणि जी.आर. बरोबर आहे, त्यात बिनचूकपणा होता. परंतु एका क्लार्कने कॅबिनेट नोट टाईप करीत असतांना नजर चुकीने टायपिंग मिस्टेक केली. मंत्रिमहोदयांनी दि.28 जुलै 2007 ला असे उत्तर दिले की,

यू 2/-

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/ MMP/ KGS/ SBT/ KTG/

ता.प्र.क्र. 3400...

प्रा.बी.टी.देशमुख...

"शासनाने जी.आर. काढला होता त्यामध्ये काही चुका झाल्या होत्या. कॅबिनेटसमोर ठेवण्यात आलेल्या नोटींगमध्ये टायपिंग मिस्टेक झाली होती." मंत्रिमहोदय त्यावेळी असे म्हणाले होते की, "यासाठी पुन्हा कॅबिनेटसमोर जावे लागेल." तेव्हा या जी.आर. ची अंमलबजावणी आपण किती दिवसात करणार? "एक महिन्याच्या आत अंमलबजावणी करुन त्यांना थकबाकी देणार काय?" या प्रश्नावर त्यांनी दि.24 जुलै 2007 ला "होय" असे उत्तर दिले. सभापती महोदय, दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, यातील पेन्शनरांना 1996 पासून आजपर्यंत अत्यंत अवहेलना सहन कराव्या लागत आहे. त्या संदर्भात मंत्रिमहोदयांना प्रश्न विचारल्यानंतर 21 मार्च 2006 रोजी असे उत्तर देण्यात आले की, "20 मार्च 2006 ला या संदर्भातील जी.आर. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढून वि-त विभागाला पाठविला आहे, आणि वित्त विभागाकडून येत्या 15 दिवसात ही अधिसूचना ए.जीं.कडे जाईल." म्हणजे "दि. 20 मार्च रोजी जी.आर. काढल्यानंतर त्याची प्रत वित्त विभागाकडे पाठविल्यानंतर वित्त विभागाकडून महालेखाकारांच्या कार्यालयाला कळविल्यानंतर हा विषय तिथे संपतो". सभापती महोदय, माननीय मंत्रिमहोदयांच्या उत्तरानंतर 21 मार्च 2006 रोजी चर्चेत आपण असे म्हटले आहे की, "सन्माननीय मंत्रिमहोदयांनी दिलेले उत्तर ऐकल्यानंतर असे स्पष्ट होते की, तंत्र शिक्षण विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या जी.आर. ची प्रत वित्त विभागाकडे पाठविल्यानंतर वित्त विभागामार्फत महालेखाकार यांच्या कार्यालयाला तसे कळविणे आवश्यक होते. It may be a slip of tongue म्हणा किंवा झालेली चूक म्हणा. अशी चूक पुन्हा घडू नये." आता माझा प्रश्न असा आहे की, याठिकाणी कारण नसतांना आपण म्हणता त्याप्रमाणे टायपिंग मिस्टेक झाली म्हणून आपण या लोकांची अवहेलना करीत आहात ती योग्य नाही. आपण म्हणाल्याप्रमाणे एक आठवडयाच्या आत मंत्रिमंडळापुढे हा प्रस्ताव ठेवणार आहात. कॅबिनेटच्या नोटमध्ये टायपिंग मिस्टेक झाल्याचे मंत्रिमहोदयांनी या सभागृहामध्ये सांगितले आहे.म्हणून प्रश्न असा आहे की, एक आठवडयाच्या आत आपण मंत्रिमंडळाच्या समोर हा विषय ठेऊन व मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेऊन पुढील आठवडयात त्यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यासंबंधीचे नियम 46 अन्वये निवेदन या सभागृहासमोर करणार काय?

यू 3/-

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/ MMP/ KGS/ SBT/ KTG/

ता.प्र.क्र. 3400...

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहामध्ये निर्णय सादर केला जाईल. तसेच, यामध्ये जे दोन अधिकारी कारणीभूत आहेत त्यांना कारणे दाखवा नोटिस देण्यात आली आहे.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, वेतनामधील फरकाबाबतचा निर्णय ज्यावेळी कॅबिनेटमध्ये होईल तेव्हा त्याची अंमलबजावणी त्या तारखेपासून होईल. ज्या टायपिंग मिस्टेकमुळे हे सर्व घडले आहे. तेव्हा त्या तारखेपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करणार काय?

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, याबाबत तपासून पाहून निर्णय घेऊ.....

(अडथळा)

सभापती महोदय, होय. त्याबाबतची सभागृहाची भावना बघून निर्णय घेण्यात येईल.

प्रा. बी. टी. देशमुख : सभापती महोदय, मंत्रिमहोदयांनी तपासून पाहून असे म्हटल्यामुळे पुन्हा यामध्ये घोटाळा होईल. ते त्यांना मिस्टेक दुरुस्त करुन मूळ तारखेपासूनच दिले पाहिजे.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

APR/ SBT/ MMP/ पूर्वी श्री.सरफरे 13:05

ता.प्र.क्र.3400 . . ..

सभापती : माननीय मंत्री महोदया, टायपिंग चूक असेल किंवा असे काही कारण असेल, पण खरोखर जो निर्णय झालेला आहे, तो टाईप झाला नाही असे आपले मत आहे. म्हणून याबाबतीत अधिवेशन संपण्यापूर्वी जो निर्णय घेणार आहात, तो पूर्वलक्षी प्रभावाने घेण्यात यावा.

प्रा.वर्षा गायकवाड : होय.

श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, आपल्या निर्देशामुळे याबाबतीत चांगला निर्णय झाला . परंतु यामध्ये एक गोष्ट राहून जाईल. या कालावधी मध्ये जे रिटायर झाले आहेत, त्यांच्या पेन्शनवर परिणाम झालेला आहे, त्याबाबतीत आपण काय करणार आहात ? हा पहिला प्रश्न आहे आणि शासनाने हे मान्य केले आहे आणि यामध्ये ज्या क्लेरिकल माणसाची टायपिंग चुक झाली आहे.शासनाने आदेश देऊन सुध्दा चार वर्षे झाली. दि.20 मार्च 2008 पासूनचा हा निर्णय आहे. आहे. यामध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांनी चुक केली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करणार आहात काय ?

प्रा.वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, मी दोन्ही प्रश्नांच्या बाबतीत अगोदर उत्तरे दिलेली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे.

श्री.भाई जगताप : सभापती महोदय, माझा असा प्रश्न आहे की, जे रिटायर झालेले आहेत, त्यांच्या पेन्शनबाबत काय करणार ?

प्रा.वर्षा गायकवाड (खाली बसून) : सभापती महोदय, मी मघाशीच सांगितलेले आहे.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, सदनामध्ये या प्रश्नाच्या निमित्ताने अत्यंत गंभीर बाब समोर आलेली आहे. 2004 साली एक कर्मचारी टायपिंगची चूक करतो आणि या सदनामध्ये या विषयाच्या संबंधात वारंवार प्रश्न उपस्थित करुन, या सदनाचा जो वेळ खर्ची होत आहे. म्हणून यामध्ये निग्लीजन्स् ऑफ ड्युटी हा विषय उपस्थित होतो. तेव्हा चुक करणारा जो कोणी कारकून किंवा टायपिस्ट असेल त्याच्यावर कोणी कारवाई करणार आहात ? कारण हा विषय गंभीर आहे, यामध्ये सदनाचा एवढा वेळ गेला आहे. 2004 पासून सहा वर्षे हजारो शिक्षकांना मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित रहावे लागले. तर अशा प्रकारे शिक्षकांना सहा वर्षे या लाभापासून वंचित ठेवणारा, टायपिंगची चूक करणारा जो कोणी कर्मचारी आहे, त्याच्यावर कारवाई केली आहे काय ? जर कारवाई केली नसेल तर ती आजच्या आज जाहीर करण्यात यावी. ही काय गंमत आहे काय ?

प्रा.वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, डेप्युटी सेक्रेटरी श्री.शिंत्रे आणि कक्ष अधिकारी श्री.

. . . .व्ही-2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

जगताप हे दोघेही आता रिटायर झालेले आहे. परंतु आमची भूमिका कोणालाही पाठिशी घालण्याची नाही. म्हणून दोघांनाही पत्रान्वये दि.08 एप्रिल 2010 रोजी कार्यालयामध्ये बोलाविलले आहे आणि दोघांचीही चौकशी सुरु आहे.

. . . .व्ही-3

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

आदिवासी/नक्षलग्रस्त भागातील खाजगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नती व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता योजना लागू करणेबाबतची मागणी

(4) *2766 श्री.व्ही.यु. डायगव्हाणे, श्री.कपिल पाटील, श्री.जयंत पाटील, श्री.दिलीपराव सोनवणे , श्री.वसंतराव खोटरे : तारांकित प्रश्न क्रमांक 46222 ला दिनांक 17 डिसेंबर, 2008 रोजी दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात : सन्माननीय **शालेय शिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(1) गडचिरोली व इतर आदिवासी/नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील खाजगी माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 6 ऑगस्ट, 2002 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे एकस्तर पदोन्नती व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता या दोन्ही योजना जशाच्या तशा लागू कराव्या या आशयाचे एक निवेदन एका लोकप्रतिनिधीने मा.गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री, गडचिरोली जिल्हा यांना दिनांक 25 जानेवारी, 2010 रोजी देऊन चर्चा केली हे खरे आहे काय,

(2) असल्यास, शालेय शिक्षण विभागाने दिनांक 14 ऑगस्ट, 2008 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे उक्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत नाही, हेही खरे आहे काय,

(3) असल्यास, उपरोक्त शासन निर्णयातील जाचक अटी दूर करुन त्याचा लाभ सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब लागू करण्याबाबत शासनाची काय भूमिका आहे व त्यानुसार कार्यवाही केव्हापर्यंत होणे अपेक्षित आहे?

श्री. बाळासाहेब थोरात : (1) होय.

(2) व (3) 14 ऑगस्ट 2008 च्या शासन निर्णया अन्वये सदरची सवलत फक्त बदली पात्र शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यानांच लागू आहे.

श्री.व्ही.यू.डायगव्हाणे : सभापती महोदय, हा अत्यंत महत्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागामध्ये काम करणाऱ्या अशासकीय माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना एकस्तर पदोन्नती देण्याच्या संदर्भात सदनामध्ये 18 वेळा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या विषयाबाबत आम्हाला कोर्टामध्ये जावे लागले आणि कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे दि.14 ऑगस्ट 2008 रोजी जी.आर.काढण्यात आला. पण या जी.आर.प्रमाणे एकाही शिक्षकाला फायदा होत नाही. याचे कारण . . .

सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.व्ही.यू.डायगव्हाणे यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री.व्ही.यू.डायगव्हाणे : सभापती महोदय, सभापती महोदय, याचे कारण असे आहे की, सहा वर्षे नक्षलग्रस्त भागामध्ये काम केले पाहिजे येथपर्यंत बरोबर आहे. त्यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत बिगर नक्षलवादी एरियामध्ये त्यांची बदली झाली पाहिजे. ज्या संस्था नक्षलग्रस्त एरिया मध्ये आहेत . . . .

. . . .व्ही-4

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.व्ही.यू.डायगव्हाणेसाहेब, आपल्याला प्रश्न विचारावयाचा नाही काय ? जर प्रश्न विचारावयाचा असेल तर डायरेक्ट विचारावा. एखादा अपवाद म्हणून सन्माननीय सदस्य प्रा.बी.टी.देशमुख सर किंवा इतर कोणी असेल तर ठीक आहे. परंतु सगळयानींच प्रश्न डेव्हलप करावयाचा असे म्हटले तर दोन-तीन प्रश्नांवर देखील चर्चा होणार नाही.

श्री.व्ही.यू.डायगव्हाणे : सभापती महोदय, मी प्रश्नच विचारतो. दि.14 ऑगस्ट 2008 च्या शासन निर्णयामध्ये जी त्रुटी आहे, त्यामुळे शिक्षकांची दुसरीकडे बदली होऊच शकत नाही. कारण तेथे त्यांची संस्थाच नाही. म्हणून यामध्ये बदल करुन सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या प्राध्यापक आणि शिक्षकांना ही योजना 2002 च्या नियमाप्रमाणे लागू होईल काय ?

श्री.बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, नक्षलग्रस्त आणि आदिवासी भागामध्ये काम करणारे जे सरकारी कर्मचारी आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून पहिल्यांदा 2002 मध्ये जी.आर.काढण्यात आला आणि 2008 मध्ये शिक्षण विभागाचा जी.आर. निघाला. परंतु अनुदानित आणि विना-अनुदानित विद्यालये आहेत. त्यामध्ये अनुदानित जी विद्यालये आहेत त्याबाबतीत तो जी.आर.लागू आहे. परंतु एखाद्या संस्थेची जर एकच शाळा असेल आणि अशा वेळी त्याची बदली होऊ शकत नसेल तर त्याला मात्र हा जी.आर.लागू होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, म्हणजेच बदली होणारा जो कर्मचारी आहे, त्याला हा जी.आर.लागू होत आहे ही वस्तुस्थिती यामध्ये आहे. म्हणून मी यानिमित्ताने सदनाला आणि सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की, जे कायम आदिवासी आणि नक्षलवादी भागामध्ये रहात आहेत आणि काम करीत आहेत. त्यांची बदलीच होऊ शकत नाही.

यानंतर कु.थोरात . . ..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

SMT/ KGS/ SST/ प्रथम सौ. रणदिवे... 13:10

ता.प्र.क्र.2766.....

श्री. बाळासाहेब थोरात...

सभापती महोदय, म्हणून त्यांना तो लाभ मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती पहाता पुन्हा एकदा विभागामार्फत एक प्रयत्न करील आणि याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे नेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाईल.

श्री. विक्रम काळे : सभापती महोदय, हा प्रश्न आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागामध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांचा आहे. त्यामुळे अशा अवघड ठिकाणी काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळाला पाहिजे म्हणून हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी आपला प्रस्ताव वित्त विभागकडे जाणार आहे काय आणि त्याला आपण मान्यता घेणार आहात काय?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, मी या प्रश्नाचे उत्तर दिलेले आहे.

श्री. कपिल पाटील :सभापती महोदय, या प्रश्नाचे दोन भाग आहेत. बदलीपात्र असलेले शिक्षक की ज्यांना हा जी.आर. ऑलरेडी लागू आहे. अनेक संस्थांच्या शाळा त्या जिल्हयात आणि आदिवासी भागातही आहेत. त्यांना हा जी.आर. लागू केला जात नाही ही अडचण असल्यामुळे त्यांना तो ताबडताब लागू केला पाहिजे. ज्यांची बदलीच होऊ शकत नाही कारण संस्था बाहेर नाही हा दुसरा भाग आहे. जे बदलीपात्र असनूही उदा. रयत शिक्षणसंस्था आहे शिवाजी शिक्षणसंस्था आहे, यांच्या शाखा आदिवासी भागात आहेत त्या शिक्षकांना हा ताबडतोब लागू झाला पाहिजे, त्याबाबतीत कोणतीही अडचण नाही पण ते नाकारले जात आहे. ज्यांची बदली होऊ शकत नाहीत अशा आदिवासी विभागातील ज्या शाळा आहेत त्यांना सुध्दा हा लागू केला पाहिजे. या दोन्ही बाबत तातडीने कार्यवाही करणार काय?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, सनमाननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेली बाब तपासून पाहिली जाईल.

श्री. रामनाथ मोते : सभापती महोदय, सामान्य प्रशासन विभागाचा दि. 6 ऑगस्ट, 2002 चा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाला लागू झालेला आहे. त्याअनुषंगाने दि.14 ऑगस्ट,2008 ला शासनाने जी.आर. काढला आणि त्याअनुषंगाने ही योजना लागू केली. सभापती महोदय, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अशी कोणतीही अट किंवा निकष नाही. फक्त शालेय शिक्षण

...2..

ता.प्र.क्र.2766...

श्री. रामनाथ मोते....

विभागाच्या जी.आर.मध्ये सहा वर्षाची अट आणि बदलीची अट टाकलेली आहे त्यामुळे दि.6 ऑगस्ट, 2002 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागाला सुध्दा त्याच पध्दतीने हा भत्ता लागू करणार काय?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, दि.6 ऑगस्ट, 2002 चा सामान्य प्रशासन विभागचा महत्वाचा जी.आर.आहे. सन्माननीय सदस्य सांगत आहेत त्याप्रमाणे त्यामध्ये आणि यामध्ये काही फरक आढळून येत असेल तर तशा प्रकारे सुध्दा पडताळून पाहिले जाईल आणि त्यामध्ये जर तसा दोष रहात असेल तर तो दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

...3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

SMT/ KGS/ SST/

संगणकशास्त्र या वैकल्पिक विषयाला अनुदान देतांना दिली जाणारी भेदभावपूर्ण वागणूक

(५) * २६३५ श्री.दिलीपराव सोनवणे , प्रा.बी.टी.देशमुख , श्री.वसंतराव खोटरे , श्री.विक्रम काळे : तारांकित प्रश्न क्रमांक ५०१६६ ला दिनांक ४ जून, २००९ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या संदर्भात : सन्माननीय **उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पदवी स्तरावरील अनुदानप्राप्त विज्ञान शाखेअंतर्गत शिकविल्या जाणाऱ्या संगणक शास्त्र या वैकल्पिक विषयाला अनुदान देतांना दिल्या जाणाऱ्या भेदभावपूर्ण वागणूकीबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने २००७ च्या याचिका क्रमांक ९९८ मध्ये दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे कारवाई करण्याच्या विचाराधीन प्रश्नावरील शासनाचा विचार पूर्ण झालेला आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वरुप काय आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कारवाई झालेली नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या विलंबाची कारणे काय आहेत?

प्रा. वर्षा गायकवाड, श्री. राजेश टोपे यांच्याकरिता : (१) नाही.

(२), (३) याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे.

श्री. दिलीपराव सोनवणे : सभापती महोदय, संगणकशास्त्र हा विषय वैकल्पिक विषय म्हणून असल्यानंतर 1991 अगोदर ज्या संस्थांनी हा विषय सुरु केला होता त्यांना तो अनुदानावर देण्यात आला आणि 1991 नंतर मात्र कायम विनाअनुदान तत्वावर दिलेला आहे. 1991 नंतरच्या कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर असलेल्या काही संस्थांना हा विषय अनुदानावर देण्यात आलेला आहे मात्र काही संस्थांना तो अद्यापपर्यंत अनुदानावर दिलेला नाही. तेव्हा ज्यां संस्थावर अशा प्रकारचा अन्याय झालेला आहे त्या संस्थांना हा विषय अनुदानावर देण्यात येईल काय?

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे त्याबाबतीत शासनस्तरावर कार्यवाही चालू आहे आणि त्याबाबतीत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल.

प्रा. बी. टी. देशमुख : सभापती महोदय, "शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे" हे उत्तर नॉर्मली बरोबर आहे पण हायकोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर सुध्दा दोन दोन वर्षे ही कार्यवाही चालूच आहे हे बरोबर नाही. सभापती महोदय, मी आपली परवानगी मागतो. सभागृहाची वेळ घेण्याची माझ ी कधीच इच्छा नसते पण माननीय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2007 च्या याचिका क्रमांक 998 मध्ये दिनांक 26 नोव्हेंबर, 2007 मध्ये निकाल दिलेला आहे. त्यामध्ये असे म्हटलेले आहे की, " However, if the State Government has granted permission to some

..4..

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.2635...

प्रा. बी. टी. देशमुख...

colleges and institutions to start the above subject on No Grant Basis, in that case, we permit the Petitioner to make representation in this regard to the State Government within a period of four weeks from today and if such representation is made, the State Government is directed to take decision on merit, according to the Law and Procedure applicable in this regard, within a period of 8 weeks of the date of such representation."

सभापती महोदय, माननीय उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. दि.26 नोव्हेंबर, 2007 रोजी त्या संस्थेने आपल्याकडे दि.19-12-2007 रोजी रीप्रेझेंन्टेशन किंवा निवेदन आपणास सादर केलेले आहे. त्यानंतर आठ आठवडयाच्या आत शासनाने याबाबतचा निर्णय घ्यावयाचा होता पण तसा तो घेतला नाही. सभागृहामध्ये याबाबतीत काय निर्णय घेण्यात येणार आहे सांगण्यात आले आहे.

यानंतर श्री. बरवड...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र. 2635 .... प्रा. बी. टी. देशमुख ....

"23 भेदभावाचे मुद्दे त्या निवेदनामध्ये आपल्या लक्षात आणून दिले, हे खरे आहे काय ? असा प्रश्न विचारला असता आपण 'होय' अशा पध्दतीचे उत्तर दिलेले आहे. शासनाने केवळ 'होय' असे उत्तर दिलेले नाही तर सभागृहामध्ये 23.12.2008 रोजी माननीय मंत्रिमहोदयांनी सभागृहात असे सांगितले की, "पुढच्या अधिवेशनाच्या अगोदर हा विषय उच्च शिक्षण विभागाकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यतेसाठी आणला जाईल आणि पुढील अधिवेशनाच्या अगोदर या विषयाच्या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल." पण तसा निर्णय घेतला गेला नाही. सभापती महोदय, त्यानंतर एक ॲफिडेव्हिट शासनाच्या वतीने कोर्टामध्ये करण्यात आले. त्यावर कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. खरे म्हणजे हे सचिवांचे काम असते. दुसऱ्या एका प्रकरणामध्ये प्रधान सचिवांना 50 हजार रुपये दंड झाला, तिसऱ्या एका प्रकरणामध्ये त्यांना 5 हजार रुपये दंड झाला. या प्रकरणामध्ये दंड झालेला नाही. परंतु हायकोर्टाने शासनाच्या ॲफिडेव्हिट बाबत जो निर्णय दिला त्यामध्ये असे म्हटले आहे की,

" ....it is mentioned in the affidavit that the proposal of the Petitioners for grant-in-aid could not be decided by the Cabinet/Competent Authority because of imposition of Code of Conduct by the Election Commissioner. It is also mentioned in the affidavit that as soon as period of Code of Conduct comes to an end, issue about extending grant-in-aid to the computer science course run by the Petitioners will be placed before the Cabinet/Competent Authority for necessary consideration and decision." हायकोर्टाने पुढे असे म्हटले आहे की, " In the circumstances, we dispose of the writ petition and expect that the decision be taken as early as possible after the period of Code of Conduct comes to an end." माझे असे म्हणणे आहे की, आपण स्वत: सभागृहामध्ये सांगितले की, आठ आडवड्यांच्या आत आम्ही निर्णय घेऊ. भेदभाव झालेला आहे. निरनिराळे 23 प्रकारचे भेदभाव आहेत. ते भारतीय संविधानाच्या खंड 14 च्या विरुध्द आहे. आपण याबाबतीतील निर्णय आठ दिवसांमध्ये, पंधरा दिवसांमध्ये घेणार काय ?

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ SST/ KGS/

ता.प्र.क्र. 2635 ....

प्रा. वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, जेव्हा आपण या कोर्सला अनुदान दिले होते त्यावेळी तो ऑप्शनल विषय होता. त्यानंतर कॉम्प्युटर सायन्स हा विषय रेग्युलर चालू झाला आहे. त्यानंतर मधल्या काळात कायम विनाअनुदानितचा कायदा आणला. सन्माननीय सदस्यांचा असा प्रश्न आहे की, एका हप्त्यामध्ये निर्णय घेणार काय ? एका हप्त्यामध्ये हा विषय निर्णयासाठी कॅबिनेटपुढे घेऊन जाऊ.

...3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ SST/ KGS

शिक्षण मंडळाने अकरावीचा अभ्यासक्रम सुधारण्याचा घेतलेला निर्णय

(६) * २६८२ श्रीमती अलका देसाई , श्री.अनिल परब , डॉ.दिपक सावंत , श्री.किरण पावसकर , श्री.दिवाकर रावते , श्री.मोहन जोशी , श्री.सुभाष चव्हाण , श्री.सय्यद ज़मा , श्री.पांडुरंग फुंडकर , श्री.रामनाथ मोते , श्री.संजय केळकर : सन्माननीय **शालेय शिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शिक्षण मंडळाने अकरावीचा अभ्यासक्रम दोन वर्षापूर्वी बदलल्यानंतर आता उक्त अभ्यासक्रम पुन: सुधारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दोन वर्षापूर्वीच्या अभ्यासक्रम बदलानुसार गेल्या वर्षापासून उक्त अभ्यासक्रमाची पुस्तके मंडळाने स्वत: अधिकृत पुस्तके म्हणून प्रकाशित केली हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, आता चालू वर्षासाठी अभ्यासक्रम बदलल्यामुळे/ व्याप्ती वाढवल्यामुळे मंडळाने गेल्या वर्षीच्या अभ्यासक्रमानुसार प्रकाशित केलेली अकरावीची सुमारे दीड लाख पुस्तके व त्यासाठी इ ाालेला खर्च वाया गेला हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी लाखो रुपयांचा निधी वाया गेला हे ही खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याप्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली वा करण्यात येत आहे,
(६) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत?

प्रा. वर्षा गायकवाड, श्री.बाळासाहेब थोरात यांच्याकरिता : (१) हे खरे नाही.
इ.११ वी चा अभ्यासक्रम २००६-०७ पासून बदललेला आहे. त्यास ४ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
(२) सन २००९-२०१० मध्ये मंडळाने प्रथमच इ. ११ वी ची भाषेतर काही विषयांची पाठयपुस्तके प्रकाशित केली.
(३) हे खरे नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्‌भवत नाही.

श्रीमती अलका देसाई : सभापती महोदय, उपप्रश्न क्रामंक 1 आणि 2 ला शासनाने असे उत्तर दिलेले आहे की, इयत्ता 11 वी चा अभ्यासक्रम शिक्षण खात्याने चार वर्षापूर्वी म्हणजे सन 2006-07 मध्ये बदललेला आहे. दर तीन वर्षांनी 11 वी चा अभ्यासक्रम बदलला पाहिजे असे महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याचे अलिखित धोरण आहे काय ? 9 वी आणि 10 वी च्या विद्यार्थ्यांनी जो अभ्यास केलेला आहे त्या विद्यार्थ्यांचा या बदलामुळे जो तोटा होणार आहे त्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, चार वर्षापूर्वी 11 वी चा अभ्यासक्रम बदलण्यात आलेला आहे. डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये असे सांगितले होते की, आपण 9 वी आणि 11 वी च्या

...4...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ SST/ KGS/

ता. प्र. क्र. 2682.... श्री. बाळासाहेब थोरात ....

काही विषयांच्या बाबतीत अपग्रेडेशन करणार आहोत. परंतु त्यानंतर केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने जो निर्णय घेतला त्यानुसार कशा पध्दतीने अपग्रेडेशन झाले पाहिजे.याबाबतीत त्यांच्या सूचना आल्यानंतर आता आपण फक्त 9 वी च्या बाबतीत अपग्रेडेशन करीत आहोत. आपण हा अभ्यासक्रम बदलतो याचा अर्थ पूर्ण अभ्यासक्रम बदलत नाही तर गणित आणि सायन्स या दोनच विषयाचे अपग्रेडेशन करतो. या वर्षी 9 वी चे अपग्रेडेशन होईल. त्याची पुस्तके जून, 2010 पासून उपलब्ध करुन दिली जातील. पुढच्या वर्षी 10 वी आणि 11 वी चे अपग्रेडेशन होईल. त्यामध्ये गणित आणि सायन्स हे दोन विषय संपूर्ण देशामध्ये समान पध्दतीने शिकविले जावेत याकरिता नामदार श्री. कपिल सिब्बल जे नवीन धोरण आणत आहेत त्याचा तो भाग आहे.

यानंतर श्री. खंदारे ...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

NTK/ MMP/ SBT/ यापूर्वी श्री.बरवड 13:20

ता.प्र.क्र.2682.... श्री.बाळासाहेब थोरात....

केंद्र सरकारने सांगण्यापूर्वी हे अपग्रेडेशन करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने केला होता. आता केंद्राच्या सूचना आल्यामुळे त्यात सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार दहावी व अकरावीचा अभ्यासक्रम जून, 2011 पासून आणि बारावीचा जून, 2012 पासून गणित व विज्ञान या विषयाचा अभ्यासक्रम कार्यान्वित होणार आहे.

श्री. सय्यद जमा : सभापति महोदय, आज 1 अप्रैल 2010 से भारत सरकार ने राइट टू एज्यूकेशन का कायदा लागू किया है. मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या इस बारे में कोई प्रस्तावना आपको पहले प्राप्त हुई थी ? माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा बताया है कि कक्षा 10 का साइंस और गणित विषयों का सिलेबस वर्ष 2011-12 तक देश के स्तर पर करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कहा है. मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि साइंस और गणित विषयों का सिलेबस देश के स्तर पर करने का आदेश आपको किस विभाग ने दिया है ?

श्री.बाळासाहेब थोरात : सन्माननीय सदस्यांचा प्रश्न वेगळा आहे. 'राईट टू एज्यूकेशन' हा कायदा 2002 मध्ये मंजूर झाल्यानंतर तो आजपासून अंमलात आला आहे. केंद्रीय शिक्षण विभागामार्फत काही गोष्टी कळविल्या जात आहेत आणि त्यासंबंधी शासन कार्यवाही करीत आहे.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, मी मंत्री महोदयांचे स्वागत करतो. कारण अभ्यासक्रम बदललाच पाहिजे. अगोदरच आपण मागे आहोत. इयत्ता 9 ते 12 वीचा अभ्यासक्रम बदलला जाणार आहे. एससीआरटीच्या माध्यमातून इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम त्या अनुषंगाने बदलला पाहिजे. एकदम इयत्ता नववीत आल्यानंतर मुलांची अडचण होते. तसा बदलीही राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाशी सुसंगत करणार काय, आपण राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाशी सुसंगत नसल्यामुळे आपली मुले स्पर्धा परीक्षांमध्ये इतर सर्व परीक्षांमध्ये मागे पडतात,. म्हणून त्याची सुरुवात तातडीने केली जाईल काय ?

श्री.बाळासाहेब थोरात : ही परिवर्तनाची सतत चालू असलेली प्रक्रिया आहे. जागतिक स्तराबरोबर आपल्या देशातील मुले राहिली पाहिजेत म्हणून केंद्र सरकार सुध्दा प्रयत्न करीत आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या माध्यमातून सुध्दा प्रयत्न चालू आहेत. उलट महाराष्ट्र राज्य काही बाबतीत पुढे असते. त्यादृष्टीने सर्व कार्यवाही होत आहे.

2....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.2682....

डॉ.दीपक सावंत : मंत्री महोदयांनी सांगितले की, अभ्यासक्रम बदलला आहे. अभ्यासक्रम बदलला आहे की त्याची व्याप्ती वाढविली आहे हा मुलभूत प्रश्न आहे. व्याप्ती वाढविल्यानंतर त्या अभ्यासक्रमाची 1.50 लाख पुस्तके होती ती रद्दीमध्ये गेली आहेत काय ?

श्री.बाळासाहेब थोरात : अभ्यासक्रमाचे अपग्रेडेशन शासन करीत आहे हे खरे आहे. त्याचा स्तर बदलत आहोत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पुस्तके वाया जात आहेत हा दुय्यम विषय आहे. अकरावीचा अभ्यासक्रम पुढील वर्षापासून सुरु होणार आहे. त्याची पुस्तके उपयोगात येणार आहेत. इयत्ता नववीची काही पुस्तके वाया जातील, परंतु ते महत्वाचे आहे असे मी मानत नाही.

3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे प्रतिनिधी व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने झालेल्या चर्चेअंती १० मुद्यांवर मतैक्य

(७) * २५९८ प्रा.बी.टी.देशमुख , श्री.वसंतराव खोटरे , श्री.दिलीपराव सोनवणे , श्री.विक्रम काळे : सन्माननीय **उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे (MFUCTO) प्रतिनिधी व महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उच्च शिक्षण मंत्री व मुख्य सचिव यांच्यात मंत्रालयातील,मा.मुख्य सचिवांच्या दालनात दिनांक २६ ऑगस्ट, २००९ रोजी झालेल्या चर्चेअंती निरनिराळ्या १० मुद्यांवर मतैक्य झाले व अशा मुद्यांचे इतिवृत्त त्याच दिवशी उभयपक्षी स्वाक्षरीत झाले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या १० मुद्यांवर आतापावेतो शासनातर्फे मुद्देनिहाय काय कारवाई करण्यात आलेली आहे,

(३) काही मुद्यांवर अजूनही कारवाई झालेली नसल्यास, ते मुद्दे कोणते,

(४) प्रश्न भाग (३) मधील मुद्यांवर कारवाई न होण्याची कारणे काय आहेत?

प्रा.वर्षा गायकवाड, राजेश टोपे यांच्याकरिता : (१) होय.

(२) दिनांक २६ ऑगस्ट, २००९ च्या इतिवृत्तातील मुद्दयांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा मुद्देनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :-

मुद्दा क्र.१ :- केंद्र शासनाकडून अर्थसहाय्य न मिळाल्यास थकबाकीची रक्कम राज्य शासन, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे देणार आहे. परंतु केंद्र शासनाने अद्याप तसा निर्णय घेतला नसल्यामुळे राज्य शासनाकडून सद्य:स्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश काढण्याची आवश्यकता नाही.

मुद्दा क्र. २, ३ व ४ च्या अनुषंगाने दि. १९.११.२००९ रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत.

मुद्दा क्र.५ :- समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे.

मुद्दा क्र.६ :- च्या अनुषंगाने दि. २९.८.२००९ रोजी परिपत्रक निर्गमित केले आहे.

मुद्दा क्र.७ :- च्या अनुषंगाने दि. १ सप्टेंबर, २००९ रोजी पत्र निर्गमित करण्यात आले आहे.

मुद्दा क्र.८ :- च्या अनुषंगाने मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांना पत्र पाठविले आहे.

मुद्दा क्र.९ :- च्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.

मुद्दा क्र.१० :- च्या अनुषंगाने दि. ७ सप्टेंबर, २००९ रोजी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

(३) व (४) प्रश्न उद्‌भवत नाही.

प्रा.बी.टी.देशमुख : सभापती महोदय, या प्रश्नातील एकूण 10 मुद्यांपैकी क्रमांक नऊ व पहिला मुद्दा वगळता उर्वरित आठ मुद्यांबाबत समाधानकारक कारवाई करण्यात आलेली आहे. मुद्दा क्रमांक 9 च्या बाबतीत मी मंत्री महोदयांच्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, दिनांक 13.3.2010 रोजी भारत सरकारचे फायनल गॅझेट नोटिफिकेशन इंजिनिअरींग कॉलेजच्या शिक्षकांच्या बाबतीत इश्यू झाले आहे त्याची प्रत महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या अध्यक्षांनी दिनांक दिनांक 23.3.2010 रोजीच्या निवेदनाद्वारे शासनाकडे सादर केलेली आहे. हे फायनल नोटिफिकेशन आता

4...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

केंद्र शासनाने निर्गमित केलेले असल्यामुळे याबाबतचा राज्य शासनाचा शासन निर्णय केव्हा निर्गमित केला जाणार आहे ?

प्रा.वर्षा गायकवाड : सभापती महोदय, दोन महिन्याच्या आत लागू होईल. एआयसीटीईने ते लागू केलेले आहे. त्यानुसार तंत्रशिक्षण विभागाला सुध्दा लागू केले जाईल.

प्रा.बी.टी.देशमुख : सभापती महोदय, कार्यवृत्तातील पहिल्या मुद्याबाबत एक अत्यंत चांगली गोष्ट झाली आहे ती अशी की, महाराष्ट्रामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा व केंद्र शासनाचा हा निर्णय जशाचा तसा लागू केल्यामुळे 80 टक्के मदत केंद्र शासनाकडून मिळणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचा-यांप्रमाणे त्यांना भत्ते दिले आहेत. त्यामुळे मूळ योजनेला बाधा येत नाही असे केंद्र शासनाकडून मध्य प्रदेश कोर्टामध्ये ॲफिडेव्हिट सादर केले आहे.

यानंतर श्री.शिगम.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(ता.प्र.क्र. 2598..... (प्रा. बी.टी.देशमुख...

आपल्याकडे त्याची प्रत असेल. नसेल तर ती मी आपणास द्यायवयास तयार आहे. माझे म्हणणे असे आहे की, केन्द्र शासनाकडून 80 टक्के मदत मिळत असताना त्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून क्लेम जावयास पाहिजे. हा क्लेम राज्य शासनाकडून केन्द्र शासनाला गेला आहे काय ? तो गेला नसेल तर, राज्य शासन किती तारखेच्या आत तो क्लेम केन्द्र शासनाकडे पाठविणार आहे ?

प्रा. वर्षा गायकवाड : आम्ही दिनांक 6 जानेवारी 2010 ला केन्द्र शासनाच्या जो भाग आहे त्यासंदर्भात पत्र पाठविलेले आहे. तसचे दोन वेळा रिमाइंडर देखील पाठविलेली आहेत. 80 टक्के क्लेम आपल्याला मिळावयास पाहिजे. त्यासाठी वारंवार मागणी केलेली आहे.

प्रा. बी.टी. देशमुख : केन्द्र शासनाकडून आलेले पत्र अतिशय स्पष्ट आहे. राज्य शासनाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करुन आपला क्लेम दाखल केला पाहिजे, असे पत्रामध्ये म्हटलेले आहे. ते पत्र वाचून दाखविण्यामध्ये वेळ जाईल. माझे म्हणणे असे आहे की, थकबाकीच्या संदर्भात माननीय मंत्री महोदयांनी मागच्या वेळी सांगितले होते की 15 जानेवारी पर्यन्त आम्ही कार्यवाही करु. परंतु ती झाली नाही आणि आजपर्यन्तही ती कार्यवाही झालेली नाही हे माननीय मंत्री महोदयांच्या उत्तरातून स्पष्ट झालेले आहे.80 टक्के थकबाकीसाठी क्लेम दाखल झाल्याशिवाय पैसे कसे मिळतील ? जवळ जवळ 1900 कोटीच्यावर निधी आपल्याला केन्द्र शासनाकडून मिळणार आहे. आपला क्लेम दाखल न होणे ही गोष्ट बरोबर नाही. थकबाकीच्या संदर्भातील 80 टक्के क्लेम आपण केन्द्र शासनाला केव्हा सादर केला ?

प्रा. वर्षा गायकवाड : 6 जानेवारी 2010ला क्लेम केलेला आहे.

प्रा. बी.टी.देशमुख : किती कोटीचा क्लेम केलेला आहे ?

प्रा. वर्षा गायकवाड : 1908.134 कोटीचा.... जवळपास 1900 कोटीचा क्लेम केलेला आहे.

....2...

बिळूर (ता.जत, जि.सांगली) गावातील ब्रासग्रो कंपनीचे बनावट औषध लेबल लावून होत असलेली विक्री

(८) * ५७०८ श्री.गुरुमुख जगवानी , श्री.विनोद तावडे , श्री.नितीन गडकरी , श्री.संजय केळकर , श्री.रामनाथ मोते , श्री.पांडुरंग फुंडकर , श्री.प्रतापसिंह मोहिते-पाटील : सन्माननीय **कृषी मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बिळूर (ता.जत, जि.सांगली) गावातील ब्रासग्रो कंपनीचे बनावट औषध डबल लेबल लावून विकत असल्याचे दिनांक १४ डिसेंबर, २००९ रोजी वा त्या सुमारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीनुसार सदर प्रकरणी दोषी आढळून आलेल्या व्यक्तिविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे,

(४) नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) अंशत: खरे आहे.

(२) होय, सदर प्रकरणी एका शेतकऱ्याची तक्रार आल्यानंतर जिल्हा तक्रार निवारण समितीने, सदर शेतकऱ्याच्या द्राक्ष बागेस भेट देऊन पाहणी केली आहे. त्यावेळी तक्रारदार शेतकऱ्याच्या द्राक्ष बागेचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नसल्याचे जिल्हा तक्रार निवारण समितीला आढळून आले आहे. सदर औषध हे किटकनाशक अधिनियम, १९६८ व नियम, १९७१ या कायद्यामध्ये येत नाही.

(३) चौकशीमध्ये कोणीही दोषी आढळून आलेले नाही.

(४) प्रश्न उद्‌भवत नाही.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : उत्तराच्या भाग (1)मध्ये "अंशत: खरे आहे" असे उत्तर दिलेले आहे. उत्तराच्या भाग (2) मध्ये "शेतक-याची तक्रार, तक्रार निवारण समितीकडे दिलेली आहे" असे म्हटलेले आहे. पुढे असे म्हटलेले आहे की " सदर औषध हे किटकनाशक अधिनियम, 1968 व नियम, 1976 या कायद्यामध्ये येत नाही." सभापती महोदय, सांगली जिल्हयातील द्राक्ष बागांवर ही औषध फवारणी करण्यात आली. औषधाची एकच बाटली सापडली. अशा प्रकारच्या असंख्य बाटल्यांची त्या भागामध्ये विक्री झालेली आहे. अशा प्रकारचे बोगस औषध विकणारे जे कोणी सूत्रधार असतील त्यांच्यावर शासनाने काय कारवाई केलेली आहे ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : हे जैविक प्रकारचे औषध आहे. याचे रजिस्ट्रेशन करण्याची तरतूद किटक नाशक अधिनियम 1968मध्ये नाही. हे औषध मर्यादित स्वरुपात विक्रीसाठी आले. केवळ 11 बाटल्या विक्रीसाठी आल्या. बाटलीवर डबल लेबल लावलेले असल्यामुळे बनावट औषध

..3..

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

असल्याबाबत शेतक-याने सभापतींकडे तक्रार केली. ही तक्रार, तक्रार निवारण समितीकडे पाठविण्यात आली. जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी, महाबीजचा प्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेचे एक सदस्य आणि स्वत: सभापती यांनी पिकाची पाहणी केल्यानंतर औषधाचा कोणताही दुष्परिणाम झाल्याचे आढळून आले नाही. शेतक-याने देखील ते मान्य केलेले आहे. या निमित्ताने काही उत्पादनांची तपासणी केलेली असून ज्या काही त्रुटी आढळल्या त्याबाबतीत कारवाई केलेली आहे.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : मूळ प्रश्न असा आहे की, त्या जैविक औषधाच्या बाटलीवर डबल लेबल लावण्याचे कारण काय ? त्याबाबत शेतक-याने तक्रार केलेली आहे. औषध फवारणीमुळे त्या द्राक्ष बागांचे नुकसान झालेले नसेल तर शेतक-याने कशासाठी तक्रार केली होती ?

...नंतर श्री. भोगले...

अस्सुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.5708.... श्री.पांडुरंग फुंडकर....

ज्याअर्थी शेतकऱ्याने तक्रार केली त्याअर्थी त्या शेतकऱ्याला फसविण्याचे काम ब्रासग्रो कंपनीने केलेले आहे. अशा अनेक कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहेत. 2 हजार रुपये प्रती लीटर दराने एंड्रीन औषध दिले जाते. परंतु त्या औषधाचा वापर करुन एक अळी देखील मरत नाही. यासंबंधी शासन विचार करणार आहे की नाही? शेतकऱ्यांना असेच वाऱ्यावर सोडणार आहात का?

श्री.बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, हा प्रश्न ब्रासग्रो नावाच्या औषधापुरता मर्यादित आहे. अशा काही तक्रारी येतात त्याबद्दल कारवाई केली जाते. कंपनीवर, विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाते. अशा घटन घडत नाहीत असे नाही. परंतु त्यादृष्टीने स्पष्ट कारवाई केली जाते. हे औषध जैविक आहे. केवळ बाटलीवर डबल लेबल लावल्याचे दिसल्यानंतर त्या शेतकऱ्याला ते बनावट आहे असे वाटले. चौकशी केल्यानंतर पहिले लेबल व्यवस्थित लावले नसल्याचे दिसून आले, त्या लेबलमध्ये तफावत असल्यामुळे त्यावर दुसरे लेबल लावले. तो विक्रीचा एक भाग आहे. हे औषध उत्पादक करणारी कंपनी नाशिकची आहे. या औषधाचा द्राक्ष मणीचा आकार मोठा होण्यासाठी उपयोग केला जातो. या औषधाचा दुष्परिणाम आढळून आलेला नाही. रजिस्ट्रेशन नसल्यामुळे वेगळी कारवाई करु शकतो असे नाही. रजिस्ट्रेशन असलेल्या औषधांचा प्रश्न वेगळा आहे. रजिस्ट्रेशन नसलेली औषधे बाजारात येत आहेत. त्या संदर्भात कोणतेही बंधन नाही. जैविक स्वरुपाची औषधे आहेत. त्यांची विक्री केली जात आहे. याबाबत वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता निश्चितपणे आहे. कृषि विभाग निश्चितपणे कशा प्रकारे यावर बंधन आणता येईल किंवा गुणवत्तेबाबत कोणते निकष लावावेत याबाबत विचार करेल.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, औषधे व खते या दोन्हीबाबत शेतकऱ्यांची फसवणूक चालू आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत. मंत्रीमहोदयांना याची कल्पना आहे. या औषधांच्या बनावटगिरीच्या संदर्भात तपासणी केली असता औषध खरे आहे असे म्हटले आहे. किती टक्के दोष आढळून आला? 5 टक्के, 7 टक्के दोष आढळून आला का? 25 टक्के किंवा 15 टक्के दोष आढळून आला तर अपात्र ठरविणार आहात का? प्रयोगशाळेत याची तपासणी केली असावी. औषध खरे आहे असे म्हणता व कारवाई करता येत नाही असेही सांगत आहात हे बरोबर नाही. अशा कंपन्यांवर निर्बंध आणता आले नाही तर मोठया प्रमाणात अशा कंपन्या फोफावतील.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.5708....

श्री.बाळासाहेब थोरात : हे रजिस्टर्ड औषध नाही. जैविक प्रकारातील नवी औषधे निर्माण केली जात आहेत, ती बाजारात विक्रीला येत आहेत. जे सेंद्रिय पध्दतीने शेती करतात असे शेतकरी निरनिराळे प्रयोग करीत पुढे जाताना दिसत आहेत. या औषधाचे स्टॅण्डर्डायझेशन नाही. त्यामध्ये असलेले कन्टेन्ट तेच आहेत. शेतकरी ते घेतो आणि त्याला फायदा होतो असे चित्र दिसून येते. अशा औषधाबाबत कोणतेही बंधन नाही. किटकनाशक अधिनियम या औषधाला लागू होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु सन्माननीय सदस्य सांगतात त्याचा विचार करुन धोरण ठरविणे आवश्यक होईल. या चर्चेच्या निमित्ताने तशा प्रकारचे धोरण ठरविले जाईल.

नंतर 2बी.1...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

शासनाकडून शाळेला देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेचा निधी उपलब्ध करुन दयावयाची कार्यवाही

(9) * 3506 श्री.भगवान साळुंखे, श्री.रामनाथ मोते, श्री.संजय दत्त, श्री.सुभाष चव्हाण , श्री.चरणसिंग सप्रा , श्री.एम.एम.शेख , श्रीमती मधु जैन , प्रा.सुरेश नवले , श्री.राजन तेली , श्री.अशोक ऊर्फ भाई जगताप, श्री.चंद्रकांत पाटील, श्री.विनोद तावडे, श्री.सय्यद ज़मा, श्री.जैनुद्दीन जव्हेरी, श्री.माणिकराव ठाकरे, श्री.मोहन जोशी, श्री.प्रतापसिंह मोहिते-पाटील, श्री.जयप्रकाश छाजेड, श्री.राजेंद्र मुळक , श्रीमती मधु जैन : सन्माननीय **शालेय शिक्षण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(1) शासनाकडून शाळेला देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेला माहे सप्टेंबर, 2009 पासून शासनाकडून निधी देण्यात आला नसल्याने, शाळेतील मुले पोषण आहारापासून वंचित असल्याचे माहे डिसेंबर, 2009 मध्ये वा त्या दरम्यान निदर्शनास आले हे खरे आहे काय,

(2) असल्यास, शालेय पोषण आहार निधी शाळांना उपलब्ध करुन न देण्यामागील कारणे काय आहेत,

(3) शालेय पोषण आहार निधी त्वरीत उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(4) अद्याप, कार्यवाही केली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत?

श्री.बाळासाहेब थोरात : (1) नाही.

(2) प्रश्न उद्‌भवत नाही.

(3) शालेय पोषण आहार योजनेसाठी सन 2008-09 या वर्षातील उर्वरित शिल्लक निधी जिल्ह्यांकडे रुपये 58.25 कोटी एवढा होता. त्यानंतर एप्रिल ते डिसेंबर 2009 या कालावधीमध्ये रुपये 323.22 कोटी निधी वितरित करण्यात आला आहे.

(4) प्रश्न उद्‌भवत नाही.

श्री. भगवान साळुंखे : महोदय, शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जो निधी राज्यातील शाळांना दिला जातो तो जिल्ह्यांमध्ये विलंबाने दिला जातो. त्यामुळे शाळेच्या मुख्याध्यापकांना त्यासंबंधीची खरेदी करण्यासाठी ताण पडतो. म्हणून माझा प्रश्न असा आहे की, हा नियमितपणे व वेळेवर शासन उपलब्ध करुन देणार काय ? तसेच हे अन्न शिजविण्यासाठी जरी स्कूल कमिटी आणि ग्राम शिक्षण समितीने निर्धारित केले असले तरी शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवरच त्याचा ताण पडतो. त्याचा परिणाम अध्यापन व गुणवत्तेवर होतो. म्हणून शासन हे अन्न शिजविण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करुन ही योजना राबविणार काय ?

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र. 3506......

श्री. बाळासाहेब थोरात : महोदय, दुसरा प्रश्न जो विचारला त्यासंदर्भात राज्य व केंद्रशासन सुध्दा गांभीर्याने विचार करीत अअसून ही योजना अधिक चांगल्या प्रकारे व प्रभावीपणे कशी राबविता येईल यासाठी काही बदल सुध्दा अपेक्षित आहेत. सन्माननीय सदस्यांनी पहिला प्रश्न विचारला त्याबाबत सांगावयाचे तर अनुदान उशिरा मिळाल्याने अडचणी निर्माण होतात. यासंबंधी एकंदरित विचार करता तीन महिने अगोदर ॲडव्हान्स द्यावा की कसे असाही विचार सुरु आहे. तसेच या वर्षात ज्याप्रमाणे एप्रिल, जून, डिसेंबर आणि मार्चमध्ये निधीचे वितरण करण्यात आले त्याचे कारण म्हणजे केंद्रशासनाकडून हा निधी प्रथम आपल्या वित्त विभागाकडे येतो, नंतर शिक्षण विभागामार्फत शिक्षण संचालकांकडे जातो. त्यानंतर हा निधी जिल्हा परिषदा, गडशिक्षणाधिकारी आणि त्यानंतर शाळांकडे जातो. अशा प्रकारच्या स्टेप्स आहेत. त्या स्टेप्स कशा कमी करता येतील आणि यामध्ये कशी गती आणता येईल हे महत्वाचे आहे. तसेच जिल्हा परिषदेकडून सुध्दा खालच्या स्तरावर निधी उशिरा जातो असे आढळून आले आहे. अशा सर्व बाबींचा विचार करुन लवकरात लवकर शेवटच्या स्तरापर्यंत निधी कसा पोहचेल याबाबतीत एक पध्दती अवलंबिण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे व त्यादृष्टीने केंद्राकडेही आपण विनंती करणार आहोत.

श्री. चरणसिंग सप्रा : महोदय, शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत जो आहार पुरविला जातो त्यावर क्वॉलिटी कंट्रोलतर्फे चेक वगैरे आहे काय ? तसेच त्यात पौष्टिकता आहे काय ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : हा आहार कशा प्रकारचा असावा यासंबंधीचे केंद्रशासनाचे स्पष्ट निदेश आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यात कोणकोणते घटक असावेत या सर्व गोष्टींचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे हा आहार पौष्टिक असण्याच्या दृष्टीनेच कार्यवाही केली जाते व त्यानुसारच हा पुरवठा केला जातो.

श्री. सुभाष चव्हाण : महोदय, काही निधी आपण राज्यात वितपितर केला त्यापैकी शिल्लक राहिलेला निधी किती आहे ? आणि ही योजना चांगल्या प्रकारे अमलात आणण्याच्या दृष्ठीने सुधारित वितरण योजना आणण्याचे सांगितले ती किती दिवसात राबविली जाईल ?

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र. 3506......

श्री. बाळासाहेब थोरात : महोदय, कालच 31 मार्च संपलेला आहे. त्यामुळे याविभागात नेमका किती निधी शिल्लक आहे ही माहिती माझ्याकडे सध्या उपलब्ध नाही. तसेच सन्माननीय सदस्यांनी सुधारित वितरण योजना कधीपासून राबविणार असा प्रश्न विचारला त्याबाबत मला असे सांगावयाचे आहे की, तीन महिन्यात यासंबंधीची सुधारणा करण्यात येईल.

श्री. गोपीकिसन बाजोरिया : महोदय, शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत मुलांपर्यंत आहार पोहचत नाही. तसेच मंत्री महोदयांनी या योजनेबाबत खूप चांगले सांगितले की केंद्राकडून राज्याकडे आणि राज्याकडून शिक्षण संचालक आणि जिल्हा परिषद स्तरावर हा निधी पोहचविला जातो. माझा प्रश्न असा आहे की, हे संपूर्ण नियोजन मार्केटिंग फेडरेशनच्या कंट्रोलमध्ये आहे आणि कंझुमर फेडरेशनलाच या योजनेसाठी क्वॉलिफाईड केले जाते. कंझुमर फेडरेशन मात्र या कामाचा ठेका ठराविक ठेकेदारांनाच देत असते. एखाद्या वेळेस धान्याचे भाव वाटले की हे ठेकेदार कोर्टात जातात त्यामुळे देखील शाळांपर्यंत या योजनेतील आहार पोहचत नाही. म्हणून यामध्ये शासन पारदर्शकता आणणार आहे काय ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : महोदय, यासंबंधीची जी पध्दती आहे ती देखील निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच मार्केटिंग फेडरेशन ही एक शासनाचीच संस्था आहे. यासंदर्भात एकूण 6 निविदा प्राप्त झाल्या होत्या आणि त्यातील मार्केटिंग फेडरेशनच्या निविदा आपण स्वीकारलेल्या आहेत. धान्याच्या वाहतुकीचे काम ते त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊन करीत असतात. अशा सर्व प्रक्रियांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयापर्यंत चार प्रकरणे रिटच्या रुपाने गेली....

यानंतर श्री. जुन्नरे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र. : 3506......

श्री. बाळासाहेब थोरात .....

सभापती महोदय, हायकोर्टाने हा विषय 4 वेळा तपासलेला आहे. या ठिकाणी अजून काही पारदर्शकता आणण्याची आवश्यकता सन्माननीय सदस्यांना वाटत असेल तर त्यादृष्टीने विचार केला जाईल.

श्री. रामनाथ मोते : सभापती महोदय, शासनाने उत्तरात म्हटले आहे की, 2008-2009 चा 58 कोटी रुपये निधी शिल्लक होता. हे 58 कोटी रुपये निधी शिल्लक राहण्याची कारणे काय आहेत ? तसेच महागाईच्या काळात अन्न शिजवून देण्याबाबत जे काही दर ठरवून दिलेले आहे त्या दरामध्ये वाढ करण्यासंबंधी शासन काही विचार करणार आहे काय ?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, विद्यार्थी संख्या तसेच इतर बाबी पाहून निधी दिला जात असतो. काही कारणामुळे जो काही निधी शिल्लक आहे तो वर्षअखेर आपल्याला दिसतो आहे. अन्न शिजवण्याचे दर वाढविण्यात येणार आहे काय, असा प्रश्न सन्माननीय सदस्यांनी विचारलेला आहे. मी यासंदर्भात सांगू इच्छितो की, अन्न शिजवण्याच्या दराची माहिती घेऊन त्यासंदर्भात विचार केला जाईल.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार योजनेतून खिचडी दिली जाते परंतु मुंबईतील रात्र् शाळेत आठवीचे विद्यार्थी असतांना सुध्दा या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू केली नाही, हे खरे आहे काय ? तसेच रात्र शाळेत आठवी पर्यंतचे जे विद्यार्थी शिक्षण घेतात त्यांना पोषण आहार दिला जाणार आहे काय?

श्री. बाळासाहेब थोरात : सभापती महोदय, रात्र शाळेकरिता ही योजना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे यासंदर्भात केंद्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवून संबंधित मागणी करण्यात येईल.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, 7-8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे. त्यामुळे रात्र शाळेत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित का ठेवतात ?

श्री. बाळासाहेब थोरात :सभापती महोदय, ही बाब तपासून योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

...2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती :सन्माननीय शिक्षण मंत्री, शालेय पोषण आहार ही अत्यंत महत्वाची बाब असल्यामुळे आपल्या दालनामध्ये या प्रश्नाच्या संदर्भातील सन्माननीय सदस्यांसमवेत एक बैठक घ्यावी तसेच अन्य काही प्रश्न असतील तर त्याची सुध्दा सोडवणूक करण्यासाठी आपण जरुर प्रयत्न करावेत.

श्री. बाळासाहेब थोरात : ठीक आहे.

....3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागातील विकास कामे पूर्ण करण्याबाबत करावयाची कार्यवाही

(१०) * ६०८६ डॉ.वसंत पवार , श्री.विक्रम काळे , श्रीमती उषाताई दराडे : सन्माननीय **जलसंधारण मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक जिल्हा परिषदेला लघु पाटबंधारे विभागाच्या विकास कामांना रूपये ५ कोटी मंजूर झाले असताना व विभागात २००२ कामे असताना सदर कामांना प्रशासकीय मंजूरी न मिळाल्याने सदर रक्कम अखर्चित राहिली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार पुढे प्रलंबित असलेली विकास कामे पूर्ण करणेबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे,

(४) अद्याप कोणतीच उपायायोजना केली नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत ?

श्री.बाळासाहेब थोरात : (१) लघु पाटबंधारे (पूर्व) विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक यांना लघु पाटबंधारे योजनांना व कोल्हापुरी बंधारे या योजनांच्या शिर्षाखलील सन २००८-०९ मध्ये रु.१०५५.४९ लक्ष निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी रु.५४५.५२ लक्ष इतका खर्च होऊन रु.५०९.९७ लक्ष एवढा निधी अखर्चित राहिला. त्या विभागात २००२ कामे नसून १२८ कामे आहेत. या सर्व कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्यामुळे निधी अखर्चित राहिला आहे, अशी वस्तुस्थिती नाही.

(२) प्रश्न उद्भवत नाही.

(३) चौकशीच्या प्रश्न उद्भवत नाही.

अपूर्ण कामे प्रगतीपथावर असून सदर कामे मार्च, २०१० अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

(४) प्रश्न उद्भवत नाही.

श्री. विक्रम काळे :सभापती महोदय, १०-२० लाख निधी अखर्चित राहणे हे आपण समजू शकतो परंतु या ठिकाणी जवळपास ५०९ लक्ष एवढा निधी अखर्चित राहिलेला आहे. कामे असतांना आणि त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली असतांना सुध्दा हा निधी अखर्चित राहिलेला आहे. जी कामे मंजूर झाली होती ती कामे मार्च २०१० पर्यंत पूर्ण होतील, असे उत्तरात म्हटलेले आहे. आता मार्च महिना सुध्दा संपलेला आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे पूर्ण झालेली आहेत काय ? तसेच या ठिकाणी ५०९ लक्ष हा इतका निधी अखर्चित राहिलेला आहे. जर त्या ठिकाणी कामेच नव्हती तर त्या ठिकाणी एवढया मोठया प्रमाणात निधीची तरतूद का केली गेली ? त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची चौकशी वरिष्ठ अधिका-यांमार्फत करणार आहात काय ?

...४...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र. :६०८६......

श्री. बाळसाहेब थोरात : सभापती महोदय, निधी का खर्च झाला नाही याबाबत चौकशीची काही आवश्यकता नाही. मागील वर्षी लोकसभेच्या निवडणूका होत्या त्यावेळेस आचारसंहिता असल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले होते परंतु हा निधी नंतर खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. नोव्हेंबरमध्ये कामाला गती आली होती परंतु त्याच वेळेस फयान वादळ आल्यामुळे ज्या ठिकाणी काम सुरु होते त्या ठिकाणी पाणी आल्यामुळे प्रश्न निर्माण झाले. परंतु ३१ मार्च,२०१० पर्यंत येथील सर्व कामे पूर्ण होऊन निधी खर्च होण्यात काही अडचण येणार नाही.

...५...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

राज्य शासनाने एनटीसीच्या ५ गिरण्यांच्या जमीन विक्रीतुन मिळालेल्या रकमेची अल्प गुंतवणूक केल्याने गिरणीकामगार रोजगारापासून वंचीत राहील्या प्रकरणीची करावयाची कार्यवाही

(११) * २७२० श्री.पांडुरंग फुंडकर , श्री.नितीन गडकरी , श्री.विनोद तावडे : सन्माननीय **वस्त्रोद्योग मंत्री** पुढील गोष्टींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुंबईतील एनटीसीच्या बंद पडलेल्या २२ गिरण्यांपैकी ५ गिरण्यांच्या जमीन विक्रीस केंद्र व राज्य शासनाने परवानगी दिल्यामुळे एनटीसीला सुमारे २००० कोटी रुपये मिळाले आहेत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या २००० कोटींपैकी एनटीसीने आधुनिकीकरणासाठी फक्त १४८.६७ कोटी रुपयेच वापरले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, १५ वर्षापूर्वी बीआयएफआर व नियंत्रण मंडळाला एनटीसीने १० गिरण्या चालविण्याचे आश्वासन दिले होते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आधुनिकीकरणासाठी अत्यल्प रक्कम गुंतविल्यामुळे १० गिरण्या सुरु होऊ शकल्या नाहीत व त्यामुळे मुंबईतील हजारो गिरणी कामगारांना मिळणाऱ्या रोजगारापासून वंचित व्हावे लागले, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, एनटीसीने आश्वासित केल्याप्रमाणे १० गिरण्या पुन्हा चालू करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे कोणते विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत वा येत आहेत ?

श्री. प्रकाश सोळंके, श्री.मोहम्मद आरीफ (नसीम) खान यांच्या करिता : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) हे खरे नाही.

एनटीसीने आधुनिकीकरणासाठी एकूण रु.२४९०.१३ कोटी खर्च केले आहेत.

(३) बीआयएफआरच्या स्वीकृत पुनरुज्जीवन योजनेनुसार ३ गिरण्यांचे विलिनीकरण चालू गिरण्यांमध्ये केलेले आहे. ३ गिरण्यांचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे व ४ गिरण्यांचे जॉईन्ट व्हेंचरद्वारे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.

(४) हे खरे नाही.

(५) प्रश्न उद्‌भवत नाही.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, मुंबईच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. एनटीसीच्या ज्या २२ गिरण्या बंद पडलेल्या होत्या त्यातील ५ गिरण्या विकण्यास केंद्रशासनाने आणि राज्य शासनाने परवानगी दिली होती व त्यातून २००० कोटी रुपये एनटीसीला मिळाले होते.

यानंतर श्री. गायकवाड...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.पांडुरंग फुंडकर....

ता.प्र.क्र.2720 .....

मुंबईतील बंद पडलेल्या 22 गिरण्यांपैकी 10 गिरण्यांचे नूतनीकरण करायचे आहे. त्यासाठी आपण हा निधी खर्च करणार आहोत. त्यामध्ये कामगारांना काम द्यायचे असे आपले धोरण आहे. बी.आय.एफ.आर.च्या स्वीकृत पुनरुज्जीवन योजनेनुसार 3 गिरण्यांचे विलीनीकरणे चालू गिरण्यांमध्ये केले आहे, त्यामध्ये किती गिरणी कामगारांना रोजगार देण्यात आला आहे ? यामध्ये कंत्राटी कामगार किती आहेत, त्यांचे वेतन किती आहे ? या तीन गिरण्यांमध्ये किती कामगारांना सामावून घेण्यात आले ? असा माझा पहिला प्रश्न आहे. माझ्या प्रश्न क्रमांक 5 ला शासनातर्फे लेखी उत्तर देण्यात आलेले नाही. 10 गिरण्या सुरू करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनाकडे कोणते विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत वा येत आहेत ? असा माझा प्रश्न होता. आता शासनाने प्रयत्न थांबविले आहेत काय ? आपण केंद्र सरकारकडे जात नाही काय ? केंद्र सरकारकडे आपण विशेष प्रयत्न केले नाहीत काय ? याचे आपण उत्तर दिलेले नाही. गिरणी कामगारांना आपण वाऱ्यावर सोडले आहे काय ? म्हणून मला माझ्या पाचव्या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे. ज्या तीन गिरण्यांचे विलीनीकरण करण्यात आले त्यात किती कामगारांना सामावून घेण्यात आले, यात कंत्राटी कामगार किती आहेत व त्यांचे वेतन किती आहे ?

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या अखत्यारितील 5 सूत गिरण्यांची जमीन विक्री झाली. त्यासंबंधातील हा प्रश्न आहे. सदर जमिनीच्या विक्रीतून दोन हजार कोटी रूपये महामंडळाला मिळाले. बी.आय.एफ.आर.च्या स्वीकृत पुनरूज्जीवन योजनेनुसार एकूण 2490.13 कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च आधुनिकीकरण, कामगार स्वेच्छानिवृत्तीचा, कामगारांचा पगार, व्यापारी देणी, बँक व वित्तीय संस्था देणी, व्याज, गॅरंटी फी व अन्य यावर करण्यात आला आहे. ज्या गिरणी कामगाराने स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली आहे, ती त्यांना देण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व कामगार आजही कामावर आहेत. आज कुठलाही कामगार बेकार झालेला नाही.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ता.प्र.क्र.2720 ....

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, 10 गिरण्यांपैकी 3 गिरण्यांचे विलिनीकरण चालू गिरण्यांमध्ये केले आहे. त्यामुळे माझा प्रश्न असा आहे की, 7 गिरण्यांमध्ये किती कामगार होते ? त्यापैकी किती कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे ? उर्वरित किती कामगारांना चालू गिरण्यांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे ?

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, आधुनिकीकरण केलेल्या गिरण्यांमध्ये एकूण 2500 कामगारांना सामावून घेण्यात आलेले आहे.

सभापती : प्रश्नोत्तराचा तास संपला आहे.

......

...3

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ.शी./मु.शी.: कागदपत्रे सभागृहासमोर ठेवणे.

श्री.प्रकाश सोळंके (महसूल राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मर्यादित, पुणे यांचा सन 2001-2002, 2002-2003 व 2003-204 चा अनुक्रमे एकोणचाळीसावा, चाळीसावा व एकेचाळीसावा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो.

सभापती : वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आले आहेत.

यानंतर श्री.सरफरे....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ.शी.: अणुऊर्जा औष्णिक विद्युत प्रकल्पाकरिता घ्यावयाची पर्यावरण विषयक अनुमती

मु.शी.: अणुऊर्जा औष्णिक विद्युत प्रकल्पाकरिता घ्यावयाची पर्यावरण विषयक अनुमती यासंबंधी माननीय पर्यावरण मंत्र्यांचे निवेदन

श्री. सचिन अहिर (पर्यावरण राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. परशुराम उपरकर यांनी "अणुऊर्जा औष्णिक विद्युत प्रकल्पाकरिता घ्यावयाची पर्यावरण विषयक अनुमती" या विषयासंबंधी नियम 289 अन्वये दिलेल्या प्रस्तावास अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मी पुढील निवेदन करीत आहे.

"मे. न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन इंडिया लि., जैतापूर, जि. रत्नागिरी या अणुऊर्जा औष्णिक विद्युत प्रकल्पाने पर्यावरण विषयक जाहीर सुनावणीकरीता अर्ज सादर केलेला असून लोकसुनावणी दि.16.05.2010 रोजी प्रस्तावित आहे. अशा प्रकारच्या औष्णिक विद्युत केंद्रांना उद्योग उभारणीचे काम सुरु करण्यापूर्वी पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 च्या अंतर्गत पर्यावरण विषयक अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. या अनुमती प्रक्रियेमध्ये स्थानिक पातळीवर पर्यावरण विषयक जाहीर सुनावणी घेतली जाते व त्यामध्ये स्थानिक लोकांकडून प्राप्त सूचना/आक्षेप इ. याबाबतचा सविस्तर अहवाल पर्यावरण अनुमती देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण मंत्रालय/पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पाठविण्यात येतो.

मे. जेएसडब्लू यांच्या प्रस्तावित औष्णिक विद्युत प्रकल्पाबाबत रत्नागिरी जिल्हा जागरुक मंच व इतर यांनी क्र.131/2006 व्दारे मा. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केलेली आहे व त्यामध्ये इतर औष्णिक विद्युत प्रकल्पाबाबत सुध्दा माहिती सादर करण्यात आलेली असून सद्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

कोकण किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग, रायगड व रत्नागिरी या जिल्हयांमध्ये 19 खाणी कार्यरत असून 10 खाणी प्रस्तावित आहेत. अशा प्रकारच्या खाण प्रकल्पांना सुध्दा पर्यावरण विषयक अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. पर्यावरण विषयक अनुमतीच्या प्रक्रियेमध्ये स्थानिक पातळीवर पर्यावरण विषयक

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/ MMP/ SBT/

श्री.सचिन अहिर....

जाहीर सुनावणी घेऊन लोकांच्या सूचना व आक्षेप याची नोंद घेऊन प्रकल्पांना 04-01-2010 अनुमती देण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती आहे.खाण क्षेत्रात खनिज विकास निधीच्या अंतर्गत पर्यावरण पूरक प्रकल्प हाती घेणे आवश्यक आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हयाबाबत शासनाने दि.02.01.2009 रोजी जारी केलेल्या धोरणानुसार पर्यावरण संवर्धनाच्या उद्देशापूर्तीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हयात पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्वंकष निकष लागू करुन औष्णिक विद्युत प्रकल्प व खाण उद्योगांना अनुमती देणे नमूद केलेले आहे.

1. वीज निर्मिती प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रणाबाबत कडक अटी घालून परवानगी देण्यात येईल. मात्र सदर उद्योगांनी फ्ल्यु गॅस डिसल्फरायझेशन यंत्रणा बसविणे आवश्यक राहील. तसेच फ्लाय ॲश अधिसूचनेच्या तरतुदीनुसार ॲश वापराबाबतचा कार्यक्रम पूर्वनियोजित असावा.

2. खाण प्रकल्पांना प्रदूषण नियंत्रणाबाबत कडक अटी घालून परवानगी देण्यात येईल. तथापि, उपरोक्त उद्योगांच्या प्रस्तावित ठिकाणांची हवा व जल प्रदूषणाच्या दृष्टीने "धारण क्षमता अध्ययन" (Carrying Capacity Study) लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात यावा.

पश्चिम घाटातील जैव विविधता तसेच पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने उपाय योजना करण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने प्रसिध्द शास्त्रज्ञ श्री.माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती मार्च 2010 मध्ये नियुक्त केलेली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 6 महिने कालावधी दिलेला आहे.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ.शी./मु.शी.: नियम 93 अन्वये सूचनेच्या निवेदनासंबधी

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, या राज्यातील हजेरी सहाय्यकांसंबंधी मी काल या सभागृहामध्ये नियम 93 अन्वये सूचना दिली होती. त्यावर आपण उद्या म्हणजे आज निवेदन करण्याबाबत शासनाला निदेश दिले होते. परंतु आज नियम 93 अन्वये सूचनांच्या निवेदनांमध्ये सदर विषयावरील निवेदन आलेले नाही. संबंधित हजेरी सहाय्यक उपोषणाला बसले असल्यामुळे आज निवेदन करावे असे आपण शासनाला सांगितले होते. तेव्हा आज त्यासंबंधीचे निवेदन व्हावे असे आपण शासनाला पुन्हा अवगत करावे अशी माझी आपणास विनंती आहे.

सभापती : संबंधित विभागाकडून निवेदन मागवून घेऊन आज दिवसभरामध्ये करण्यात येईल.

पृ.शी. :
मु.शी. : **नियम 93 अन्वये सूचना.**

सभापती : माननीय सदस्य सर्वश्री पांडुरंग फुंडकर, जगदीश गुप्ता यांनी "पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी पोलीस उपनिरीक्षकाच्या पदावरील पदोन्नतीसाठी दि. 24 ऑगस्ट, 2000 व दि. 25 ऑगस्ट, 2000 रोजी सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक व पोलीस हवालदार यांची चाचणी परीक्षा आयोजित करणे, पास झालेल्या 284 उमेदवारांचा समावेश रिक्त असलेल्या 601 पदांमध्ये न केल्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांवर झालेला अन्याय"या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे.तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती . . . .

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री.जयंत प्र.पाटील, कपिल पाटील यांनी "गोदावरी सहकारी संस्था मर्यादित, मोगरा, जि.बीड या संस्थेच्या नऊपैकी आठ संचालकांनी चेअरमन व सचिव यांच्या वर मनमानी कारभाराचा ठपका ठेऊन उपोषणास बसण्याचा घेतलेला निर्णय" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य सर्वश्री.कपिल पाटील, जयंत प्र.पाटील यांनी "श्री संत लिंगनाथ स्वामी विद्यालय, भोंगवली, ता.भोर, जि.पुणे या शाळेत भ्रष्ट व मनमानी कारभार होत असल्यामुळे शाळेवर प्रशासक नेमण्याच्या मागणीसाठी दि.5 एप्रिल 2010 पासून भोंगवली या गावातील ग्रामस्थ बेमुदत उपोषण करण्याची केलेली घोषणा" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.किरण पावसकर, ॲड.अनिल परब, डॉ.दीपक सावंत, श्री.परशुराम उपरकर यांनी "मुंबईतील अंधेरी (पूर्व) येथील मे.मिस्त्री प्रभुदास मानजी इंजिनिअरींग प्रा.लि.या कंपनीच्या मालकाने कामगारांची देणी न देता संबंधित जमीन विकासकाला दिली जात असल्याबाबत" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी "हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असणारा रायगड किल्ला पुरातत्व खात्याच्या दुर्लक्षामुळे किल्ल्याचे वैभव लोप पावत असल्याबाबत" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी "लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथील इंदिरा नगरात राहणाऱ्या एका 21 वर्षीय विवाहितेवर 11 जणांनी केलेला बलात्कार" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत यांनी "माहे जानेवारी 2010 वा त्यासुमारास...

. . . .2 एफ-2

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती . . . .

मध्यरात्रीच्या वेळी मद्यधुंद अवस्थेत श्रीमती नुरिया हवेलीवाला या महिलेने गाडी चालविताना मरीन लाईन्स् येथे गस्तीवर असलेल्या सब इन्स्पेक्टर व दोन पादचाऱ्यांना धडक दिल्याने त्यांचा झालेला मृत्यू" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सर्वश्री.गोपिकिशन बाजेरिया, दिवाकर रावते, किसनचंद तनवाणी यांनी "अकोला शहरातील स्थानिक रिझर्व माता मंदिरात दर दिवशी हजारो भाविक येत असल्याने सदर संस्थानला "क" दर्जाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित करुन तीर्थक्षेत्राच्या विकासाकरिता शासनाने 1 कोटी रुपये मंजूर करण्याची आवश्यकता." या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सर्वश्री.विनोद तावडे,रामनाथ मोते, संजय केळकर,चंद्रकांत पाटील यांनी "महिला दिनाचे औचित्य साधून राज्याचे गृहमंत्री यांनी मुंबईतील पाच पोलीस ठाण्यांना वरिष्ठ निरीक्षक या पदावर महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याची घोषणा करुनही अद्याप सदर महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक या पदाचा कार्यभार देण्यात आला नसल्याबाबत "या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.परशुराम उपरकर यांनी "सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील कणकवली-तरंदळे या रस्त्यावर पडलले खड्डे व डांबरीकरणाचे रखडलेले काम" या विषयावर नियम 93 अन्वये सूचना दिली आहे. तो नियम 93 चा विषय होत नसल्याने, मी सूचनेस अनुमती नाकारीत आहे. मात्र या विषयावर शासनाने निवेदन करावे.

इतर सूचनांना मी माझ्या दालनातच अनुमती नाकारलेली आहे.

. . . . 2 एफ-3

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

APR/SBT/ KGS 13:55

नियम 93 अन्वयेच्या निवेदनाबाबत

सभापती : आज माझ्याकडे नियम 93 अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनांच्या संबंधात चार निवेदने प्राप्त झालेली आहेत.

श्री.व्ही.यु.डायगव्हाणे : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे.आपण 15 तारखेला नियम 93 अन्वये जी सूचना देण्यात आली होती,त्याबाबत निवेदन करावे असा आदेश दिला. तसेच परवा देखील सदनामध्ये सांगितले की, या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत सदरहू निवेदन निश्चित सदनासमोर येईल. परंतु आपण दिलेले आदेश देखील कोणी मानावयास तयार नाही. तेव्हा निदान पुढच्या आठवड्यामध्ये तरी ती निवेदने सदनासमोर आली पाहिजेत,नाहीतर पुढच्या आठवड्यामध्ये आमच्याकडे निवेदनांचा गठ्ठा येईल.सभापती महोदय, आपल्या निर्देशाचे सुध्दा पालन होत नाही. 19 तारखेला निवेदन करावे अशी सूचना दिली होती.

सभापती : मी 19 तारखेला नियम 93 अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या बाबतीत निवेदने करावीत अशी मी सूचना केली होती. त्याप्रमाणे जरुर काही विभागाकडून निवेदने आली आहेत आणि काही सूचनांच्या बाबतीतील निवेदने अद्याप यावयाची आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत विभागाकडून जास्तीतजास्त निवेदने लवकर यावीत म्हणजे सन्माननीय सदस्यांचा शेवटच्या दिवशी निवेदने येण्याच्या बाबतीतील जो अनुभव आहे, तसे ते होणार नाही. सोमवारी जास्तीतजास्त निवेदन कशी प्राप्त होतील दृष्टीने शासनाला जरुर सूचना देण्यात येतील.

. . . .2 एफ-4

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ.शी. : शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यात नळ पाणी पुरवठा

योजना मंजूर होऊनही निर्माण झालेला पाण्याचा दुष्काळ

मु.शी. : शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यात नळ पाणी पुरवठा योजना मंजूर होऊनही निर्माण झालेला पाण्याचा दुष्काळ याबाबत सर्वश्री. संजय केळकर, विनोद तावडे, रामनाथ मोते, भगवानराव साळुंखे वि.प.स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना

श्री.रणजित कांबळे(पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री) : सभापती महोदय, सर्वश्री संजय केळकर,विनोद तावडे,रामनाथ मोते,भगवानराव साळुंखे यांनी "शहापूर (जि.ठाणे) तालुक्यात नळ पाणी पुरवठा योजना मंजूर होऊनही निर्माण झालेला पाण्याचा दुष्काळ"या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

. . . .2 एफ-4

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.संजय केळकर : सभापती महोदय, हा पाणीपुरवठा योजनांच्या संबंधातील विषय आहे. ठाणे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये पाणी पुरवठा योजनेचे काम गेल्या 5-10वर्षापासून सुरु आहे.

पण त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत अशी स्थिती आहे. शहापूर हा आदिवासी तालुका आहे. या तालुक्यातील वेळूक ग्राम पंचायतंर्गत मौ.ढेंगणमाळ व तेलमपाडा हे दोन पाडे असून, ही आदिवासी भागातील, दुर्गम भागातील गावे आहेत. जेथे 100 टक्के आदिवासी रहातात. या लोकांनी दोन वर्षापूर्वी 45 हजार रुपये लोकवर्गणी भरली. परंतु ही लोकवर्गणी भरल्यानंतर त्यांना असे सांगण्यात आले की, येथे पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध नाही. याठिकाणी निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की,"सदर योजना राबविण्यासाठी श्री.संजय केळकर, विधान परिषद सदस्य यांनी त्यांच्या 25-02-2010 च्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना निवेदनाव्दारे मागणी केली आहे." परंतु प्रत्यक्षात आम्ही 16 नोव्हेंबर, 25 जानेवारी व 25 फेब्रुवारी अशा तीन पत्राव्दारे फॉलोअप केला होता. केवळ एका पत्राव्दारे नाही. माझा प्रश्न असा आहे की, ही दोन्ही गावे 100 टक्के आदिवासी आहेत, त्यांनी 45 हजार रुपये भरले आहेत. मग तुम्ही दोन वर्षे त्यांना कशासाठी ताटकळत ठेवले. त्यांना वेळीच सांगावयाचे होते, त्यांनी लोकवर्गणीतून पैसे भरल आहेत. शासनाने निवेदनामध्ये म्हटलेले आहे की, 130 नळ पाणी पुरवठा योजना मंजूर केलेल्या आहेत. पण योजना मंजूर झालेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्यातील किती पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झालेल्या आहेत ? तसेच या दोन पाडयांवरील लोकांनी नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी जे पैसे भरलेले आहेत, ती नळ पाणी पुरवठा योजना कधी सुरु करणार आहात ? तिसरा प्रश्न असा आहे की, निवेदनामध्ये असे म्हटलेले आहे की, "शहापूर तालुक्यातील टँकरग्रस्त गावांसाठी 36 योजना मंजूर असून त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे टँकर लॉबीला फायदा होण्यासाठी सदरची योजना मंजूर करण्यात आलेली नाही." माझे याबाबतीत स्पेसिफीक म्हणणे आहे की, शहापूर तालुक्यामध्ये टँकरचे माफिया आहेत. मोठया प्रमाणात संगनमताने टँकरच्या माध्यमातून पैसे खाल्ले जातात.. ..

सभापती : सन्माननीय सदस्यांनी प्रश्न विचारावा.

श्री.संजय केळकर : सभापती महोदय, यामुळे याबाबत चौकशी करणार आहात काय ? कारण आम्ही हे प्रकार प्रत्यक्ष शासनाच्या संबंधित खात्याच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहेत.

यानंतर कु.थोरात . . .

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

SMT/ KTG/ SBT/ KGS/ MMP/ प्रथम सौ. रणदिवे..... 14:00

श्री. संजय केळकर...

सभापती महोदय, उत्तरात असे म्हटलेले आहे की, 130 नळपाणी पुरवठा योजना मंजूर केलेल्या आहेत. यातील किती नळपाणी पुरवठा कार्यान्वीत झालेल्या आहेत? या दोन नळपाणी पुरवठा योजनां करिता जे पैसे भरलेले आहेत त्या नळपाणी पुरवठा योजना कधी सुरु करण्यात येणार आहेत? निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, "टँकरग्रस्त गावासाठी 36 योजना मंजूर असून त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. टँकर लॉबीला फायदा होण्यासाठी सदरची योजना मंजूर करण्यात आलेली नाही." सभापती महोदय, शहापूर तालुक्यामध्ये अशा प्रकारचे टँकरचे माफिया आहेत. संमनमताने टँकरच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जतो हे आम्ही प्रत्यक्ष शासनाच्या उघडकीस आणून दिलेले आहे त्यामुळे शासन याची चौकशी करणार आहे काय?

श्री. रणजित कांबळे : सभापती महोदय, शहापूर तालुक्यात जवळपास 205 गावे आणि 431 वाडया आहेत शहापूर तालुक्याची लोकसंख्या जवळपास 2,75,000 इतकी आहे. शहापूर तालुक्यात 94 स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना आहेत. त्यामध्ये जवळपास 25 जुन्या योजना होत्या त्या बंद झालेल्या आहेत. त्यामुळे भारत निर्माण किंवा इतर वेगवेगळया योजनामध्ये 21 ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन योजना घेतलेल्या आहेत त्यापैकी 13 योजनांचा पहिला टप्पा मंजूर झालेला असून त्यांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 6 योजनांचा दुसरा टप्पा मंजूर झालेला आहे व दोन योजनांचा शेवटचा टप्पा मंजूर झालेला आहे. दोन योजना एमएसईबीचे बिल न भरल्यामुळे बंद आहेत. याठिकाणी प्रश्न विचारण्यात आला की, दोन गावांमध्ये लोकवर्गणी भरल्यानंतर देखील त्या गावांची योजना चालू झालेली नाही किंवा त्यां योजनेला पैसे दिलेले नाहीत. सभापती महोदय, ही ग्रामपंचायत पाच वाडयाची ग्रामपंचायत आहे. या ग्रामपंचायतीत वेळूक, पाठोड आणि पाठोडपाडा यांच्यासाठी दोन वेगवेगळया पाणी पुरवठा योजना आहेत. या दोन वाडयांसाठी जी योजना मागितलेली आहे तिचा खर्च जवळ पास 70 लाख रुपये आहे. प्रश्न पैशाचा नाही. प्रश्न असा आहे की, त्यांच्याकडे पाण्याचा स्त्रोत जवळ नाही. या योजनेसाठी पाण्याचा स्त्रोत जो प्रस्तावित आहे तो भातसा धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये आहे. याचे हेड 180 मीटरवर आहे. त्यामुळे या योजनेमध्ये दोन स्टेजमध्ये पंपींग होणार आहे. याची रनिंग कॉस्ट जवळपास साडेतीन हजार रुपये दर वर्षी येणार आहे. लोकसंख्या लक्षात ठेवून जनरल स्टॅण्डपोस्ट लक्षात घेऊन ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत व्हायबल नाही. आपण जनरल स्टँडपोस्टला 100 रुपये दर लावतो. ते सोडून जे वैयक्तिक ....

..2..

श्री. रणजित कांबळे...

कनेक्शन्स देण्यात येतील आणि ज्यांच्या भरवशावर ही योजना चालणार आहे त्यांचे दर जवळपास रुपये 1850/- आहेत. त्यामुळे या योजनेची व्हायेबिलिटी नाही. दुसरे असे की, या गावामध्ये स्वत:चा पाण्याचा स्त्रोत आहे एप्रिलपर्यंत येथे पूरेसे पाणी असते. दोन महिन्यासाठी या गावामध्ये प्रत्येकी एक टॅकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. वेळूक ग्रामपंचायतीची जी योजना होती त्या योजनेमध्ये ही योजना समाविष्ट केली तर या योजनेची रनिंग कॉस्ट कमी होण्याची शक्यता आहे. तशा प्रकारची सूचना देखील जिल्हा परिषदेने दिली होती. पण या दोन्ही गावांनी आम्हाला आमची वेगळी योजना पाहिजे अशा प्रकारचा आग्रह धरला होता. त्यामुळे व्हायेबिलिटी कॉस्ट लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेच्या पाणी व्यवस्थापन समितीने ती नाकारली होती.

श्री. संजय केळकर : सभापती महोदय, याठिकाणी टँकर लॉबी आहे. याबाबतीत खुलासा करण्यात यावा.

श्री. रणजित कांबळे : सभापती महोदय, टँकर लॉबी आहे असा सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. निश्चितपणे ते तपासण्यात येईल.

....3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : बांदा अर्बन बँकेच्या संचालकांनी केलेला गैरव्यवहार
मु. शी. : बांदा अर्बन बँकेच्या संचालकांनी केलेला गैरव्यवहार याबाबत सर्वश्री किरण पावसकर,परशुराम उपरकर, ॲड.अनिल परब वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री. प्रकाश सोळंके (सहकार राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, सर्वश्री किरण पावसकर,परशुराम उपरकर,ॲड. अनिल परब यांनी "बांदा अर्बन बँकेच्या संचालकांनी केलेला गैरव्यवहार" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

... 4...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. किरण पावसकर : सभापती महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्हयातील, सावंतवाडी तालुक्यातील बांदानगर अर्बन क्रेडिट को-ऑप.सोसायटीत असलेले पैसे हे शेतकरी, देवस्थान मंडळ आणि अनेक संस्थांचे आहेत. माननीय मंत्रिमहोदयांनी निवेदनामध्ये नमूद केलेले आहे की, संस्थेला कर्जदारांकडून रु.17,98,10,766/-येणे आहे. या बँकेच्या संचालकांनी आणि बँकेच्या प्रशासनाने या पैशाची विभागणी करुन आपल्या नातेवाईकांना कर्जरुपाने पैसे देऊन हा गैरव्यवहार केलेला आहे. निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की,"फेब्रुवारी,2010 अखेर रु.7,17,04,000/- वितरित करण्यात आलेले आहेत." उर्वरित रक्कम किती कालावधीत देण्यात येणार आहे? ठेवीदारांनी आताच दि.26 जानेवारीला एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते.

यानंतर श्री. बरवड...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. किरण पावसकर .....

कारण ठेवीदारांनी आताच 26 जानेवारीला एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले होते आणि त्यावेळी त्यांना प्रशासनाकडून असे सांगण्यात आले की, आम्ही लवकरात लवकर आपले पैसे देऊ. आपण त्यांच्याकडून कोणत्या मार्गाने पैसे आणणार आहात ? कर्जदारांकडून काहीही तारण न घेता त्यांना कर्ज दिलेले आहे. याला संस्थेचे संचालक जबाबदार आहेत. ही बँक अस्तित्वात आल्यापासून तेच संचालक आहेत, त्यामध्ये कोणतही बदल झालेला नाही. त्यांच्याकडून ते वसूल करणार काय ? या सहकार क्षेत्राला बदनाम करणाऱ्या अशा संचालकांवर शासन काय कडक कारवाई करणार ?

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, सदर संस्थेचे जे संचालक मंडळ आहे त्याबाबत उत्तरामध्ये असे म्हटले आहे की, 2005-06 आणि 2006-07 या वर्षाचे फेर लेखापरीक्षण करण्यात आलेले आहे आणि त्याचा जो अहवाल आहे त्यानुसार कलम 88 अन्वये त्यांची चौकशी चालू आहे. सन्माननीय सदस्यांनी विनातारण कर्ज दिल्याचे किंवा नातेवाईकांना कर्ज दिल्याचे सांगितले ते सर्व त्या चौकशीमध्ये अंतर्भूत होईल. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर जसा अहवाल असेल त्याप्रमाणे संचालकांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : अकोला जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागाच्या भरारी पथकाने घातलेल्या धाडीत हजारो क्विंटल धान्यसाठे जप्त करण्यात येणे

मु. शी. : अकोला जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागाच्या भरारी पथकाने घातलेल्या धाडीत हजारो क्विंटल धान्यसाठे जप्त करण्यात येणे याबाबत श्री. गोपिकिशन बाजोरिया, वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री. अनिल देशमुख (अन्न नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री) : सभापती महोदय, श्री. गोपिकिशन बाजोरिया यांनी "अकोला जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागाच्या भरारी पथकाने घातलेल्या धाडीत हजारो क्विंटल धान्यसाठे जप्त करण्यात येणे" या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

...3 ...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/

श्री. गोपिकिशन बाजोरिया : सभापती महोदय, मला एकच प्रश्न विचारावयाचा होता परंतु माननीय मंत्रिमहोदयांनी निवेदनामध्ये लांबलचक उत्तर दिल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. आमचे हे सहा जिल्हे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे जिल्हे आहेत. आपण ज्या धाडी टाकलेल्या आहेत त्यामध्ये सध्याच्या परिस्थितीमध्ये किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि त्यामध्ये जर शेतकऱ्यांचे धान्य असेल तर त्यांना मुभा देऊन सोडणार काय ? निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, एकूण 95 ठिकाणी धाडी टाकण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये 68 प्रकरणे प्रथमदर्शनी उघडकीस आली आहेत असे म्हटले आहे. मग 27 व्दितीयदर्शनी प्रकरणांच्या बाबतीत काय झाले ? 68 प्रकरणांमध्ये 7 प्रकरणे मर्यादित साठा असलेली आणि 15 प्रकरणे शेतकऱ्यांची असलेली अशी 22 प्रकरणे आपण सोडलेली आहेत. एकूण 44 प्रकरणे प्रलंबित आहेत असे आपल्या उत्तरातून दिसून येते. या 44 प्रकरणांमध्ये जर शेतकऱ्यांचा माल जप्त केलेला असेल तर त्यांना आपण मुभा देणार काय आणि उर्वरित 27 व्दितीयदर्शनी प्रकरणाचे काय झाले ?

श्री. अनिल देशमुख : सभापती महोदय, एकूण 68 प्रकरणांमध्ये प्रथमदर्शनी दोष आढळून आले आहेत आणि त्यामध्ये जे जे शेतकरी आपले 7/12 देतील त्यांचा माल आपण नियमानुसार सोडतो. त्यांचा माल सोडला जाईल.

श्री. गोपिकिशन बाजोरिया : बाहेरच्या जिल्ह्याचा शेतकरी असेल तर त्याचा माल सोडणार काय ?

श्री. अनिल देशमुख : बाहेरच्या जिल्ह्याचा शेतकरी असेल तर त्यांचा माल सोडू. व्यापाऱ्यांचा सोडणार नाही. शेतकरी असतील आणि त्यांनी 7/12 दिला तर त्यांचा माल आपण जनरली सोडतो. पण बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन जे दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये साठवणूक करतात त्यांचा माल आपण सोडणार नाही. आपण त्यांच्यावर कडक कारवाई करु.

...4...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर जलवाहिन्या फुटण्याच्या घडत असलेल्या घटना

मु. शी. : मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर जलवाहिन्या फुटण्याच्या घडत असलेल्या घटना याबाबत डॉ.नीलम गोऱ्हे, सर्वश्री जयंत प्र. पाटील, कपिल पाटील, वि. प. स. यांनी दिलेली नियम 93 अन्वये सूचना.

श्री. भास्कर जाधव (नगरविकास राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, डॉ. नीलम गोऱ्हे, सर्वश्री जयंत प्र. पाटील, कपिल पाटील यांनी "मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर जलवाहिन्या फुटण्याच्या घडत असलेल्या घटना " या विषयावर नियम 93 अन्वये जी सूचना दिली होती, तिला अनुलक्षून आपण निदेश दिल्याप्रमाणे मला निवेदन करावयाचे आहे. निवेदनाच्या प्रती सदस्यांना अगोदरच वितरित केलेल्या असल्याने मी हे निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

...5 ...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/

डॉ. नीलम गोऱ्हे : सभापती महोदय, या निवेदनामध्ये बरेच सविस्तर उत्तर दिलेले आहे आणि त्यातील प्रश्नही स्पष्ट होत आहेत. फक्त तीन नंबरचा जो मुद्दा आहे त्यामध्ये शासनाने असे म्हटले आहे की, लिबर्टी गार्डन येथे अनधिकृत विंधन विहीर खोदताना जमिनीच्या पृष्ठभागाखाली सुमारे 70 मीटर खोलीवर असलेल्या भांडूप ते चारकोप पाणीपुरवठा बोगद्यास भोक पडले. मुंबई शहरामध्ये अनेकवेळा बांधकाम करीत असताना आणि विशेषत: अनेक वेळा खोदकाम करताना असे प्रकार घडतात. हा केवळ मुंबईचाच प्रश्न नाही तर पुणे, नाशिक या ठिकाणी सुध्दा असे दिसून येते की, एकच रस्ता तीन-तीन वेळा, चार-चार वेळा वेगवेगळ्या कारणांसाठी खोदण्याचे काम चालू असते. मग त्यामुळे लोकांचे टेलिफोन बंद होणे, पाईप फुटणे अशा अनेक गोष्टी घडतात. हा जो अनधिकृत विंधन विहीर खोदण्याचा प्रकार घडला त्याबाबतीत शासनाने काय कारवाई केली ?

यानंतर श्री. खंदारे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.भास्कर जाधव : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी अत्यंत महत्वाचा, मुलभूत आणि जो कळीचा मुद्दा समजला जातो अशाप्रकारचा प्रश्न विचारला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची कोणत्याही प्रकरची परवानगी न घेता केबल लाईन टाकणे, बोअर वेल घेणे असे प्रकार होत असतात. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकने व शासनाने असे निदेश दिलेले आहेत की, यापुढे अशाप्रकारे मुंबई महानगरपालिकची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतल्याशिवाय जर कोणी खोदकाम करील त्याच्यावर निश्चितपणे फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल. त्याचबरोबर त्यांच्याकडून झालेल्या नुकसानीची भरपाई घेण्यात येईल. ही बोअर वेल अनधिकृतपणे मारली गेली त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही, परंतु त्यांच्यावर उचित अशी कारवाई केली जाईल.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, निवेदनामध्ये असे नमूद केले आहे की, ही पाईप लाईन 80 वर्षापेक्षा जास्त काळ जुनी झाली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे पाईप लाईनचे आयुष्य 50 वर्षापेक्षा जास्त नसते. असे असताना ही आयुष्य मर्यादा संपल्यानंतरही ज्यांनी ही लाईन बदलली नाही त्यांच्यावर शासन काय कारवाई करणार आहे ? ही पाईप लाईन बदलण्यासाठी ती फुटेपर्यंत त्याची वाट पाहणार आहे काय ?

श्री.भास्कर जाधव : सभापती महोदय, ही पाईप लाईन जुनी आहे. साधारणपणे 1927 साली टाकलेली ही लाईन आहे. या लाईनचे आयुष्य 50 वर्षे होते. ते संपून जवळजवळ 80-85 वर्षे झालेली आहेत. तानसा धरणातून मुंबईपर्यंत ही लाईन आलेली आहे. ही लाईन बदलण्याची सुरुवात मुंबई महानगरपालिकेने केलेली आहे.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, मंत्रिमहोदयांनी सांगितलेले हे कारण खरे आहे. परंतु ही लाईन फुटते, पाण्याची गळती होते. त्याच्याबरोबरच याच्या पाठीमागे टँकर माफिया कार्यरत आहेत हे खरे आहे काय आणि त्याची चौकशी केली जाईल काय ? जे पाण्याची चोरी करतात त्यांच्याविरुध्द कारवाई केली जाईल काय ?

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

NTK/ KGS/ KTG/

श्री.भास्कर जाधव : ही पाईप लाईन फुटल्यानंतर ती सातत्याने दुरुस्त होते. त्याच्यातून पाणी माफियांची प्रकरणे मोठया प्रमाणात पुढे येत आहेत. गेल्या 6 महिन्यामध्ये 1200 लोकांचे अनधिकृतरित्या घेतलेले कनेक्शन कापले आहे. 118 जणांविरुध्द एफआयआर दाखल केला आहे. 378 बुस्टर पंप जप्त केले आहेत. तरी देखील शासनाला ही कारवाई पुरेशी आहे असे वाटत नाही. त्यामुळे ही कारवाई कडक व जास्तीत जास्त शीघ्र गतीने करण्यात यावी असा धोरणात्मक निर्णय शासनाने घेतला आहे.

श्री.गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तर देताना असे सांगितले की, ही पाईप लाईन जुनी झाल्यामुळे तिच्यावरील प्रेशरमुळे फुटते आणि त्यामुळे पाणी गळती होते. सभापती महोदय, मुंबई महानगरपालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. काल टी.व्ही.च्या माध्यमातून पाईप लाईन फुटल्याचे दाखविले होते. या पाईप फुटीकडे व पाण्याच्या गळतीकडे मुंबई महानगरपालिकेचे लक्ष नाही. त्यांनी पाणी पुरवठा व्यवस्था व्यवस्थितपणे करण्यासाठी शासन मुंबई महानगरपालिकेला निदेश देणार आहे काय ? याबाबतचा खर्च शासनाने केला तरी ही जबाबदारी त्यांची आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पाईप लाईन फुटणार नाही आणि पाणी गळती होणार नाही यादृष्टीने शासन मुंबई महानगरपालिकेला निदेश देणार आहे काय ?

श्री.भास्कर जाधव : सभापती महोदय, गेल्या वर्षभरामध्ये 1031 ठिकाणी पाईप लाईन गळती समोर आलेली आहे. या गळतीकडे मुंबई महानगरपालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे असे शासनाच्या लक्षात आलेले आहे. त्याची त्यांना जाणीव करुन दिलेली आहे. पुढील काळामध्ये वारंवार होणाऱ्या गळतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले तर शासनाला त्याची दखल घ्यावी लागेल असे त्यांना कळविले आहे.

ॲड.अनिल परब : मुंबईच्या दृष्टीने पाणी गळतीचा हा गंभीर प्रश्न आहे. पाणी गळतीबरोबर पाणी चोरीचा संबंध आहे. ही लाईन फुटल्यानंतर दुरुस्ती केली जाते आणि त्याच्यातून वारंवार गळती होती. वीज चोरी करणा-यांविरुध्द कडक कारवाई करण्यासाठी कायदा केला आहे. त्याप्रमाणे पाणी चोरी करणार लोक आहेत त्यांच्या संदर्भात कडक कायदा करण्यासाठी उपाययोजना करणार आहे काय ?

श्री.भास्कर जाधव : सजेशन फॉर ॲक्शन.

यानंतर श्री.शिगम.....

अशुध्दीत प्रत / प्रसिध्दीसाठी नाही

MSS/ KGS/ KTG/ पूर्वी श्री. खंदारे 14:15

प्रा. सुरेश नवले : मुंबईमध्ये पाणी चोरणा-या टोळ्या आहेत. त्या टोळ्यांची माहिती स्वाभिमान संघटनेने राज्य शासनाला आणि महानगरपालिकेला दिलेली आहे. तेव्हा स्वाभिमान संघटनेने जी माहिती दिलेली आहे त्याबाबत राज्य शासनाने कोणती कारवाई केलेली आहे ?

श्री. भास्कर जाधव : अशा प्रकारची माहिती शासनाकडे आजपर्यन्त उपलब्ध झाल्याची माझी माहिती नाही.

डॉ. विनोद तावडे : सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील आणि सन्माननीय सदस्या डॉ.नीलम गो-हे यांनी टँकर लॉबीचा या ठिकाणी उल्लेख केला. या प्रश्नाच्या संदर्भात अशी चर्चा आहे की, प्रशासनातील काही लोकांना हाताशी धरुन अशा प्रकारे पाईप फोडण्याचे प्रकार करुन जलवाहिनीच्या सुरक्षिततेचे 70-80 कोटीचे टेंडर काढले जाण्याची शक्यता आहे काय ?

श्री. भास्कर जाधव : सन्माननीय सदस्य श्री. विनोद तावडे यांना जी माहिती सांगितली ती तपासून पाहिली जाईल. परंतु शासनाकडे तरी या क्षणापर्यन्त तशा प्रकारची माहिती नाही.

...2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

औचित्याचे मुद्दे

सभापती : औचित्याचे मुद्दे मांडण्यांसाठी शुक्रवारी परवानगी दिली जाते. परंतु उद्या शुक्रवारी सुट्टी असल्यामुळे मी आज गुरुवारी औचित्याचे मुद्दे मांडण्यास परवानगी देत आहे.

सन्माननीय सदस्य श्री. रामनाथ मोते यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

श्री. रामनाथ मोते : सभापती महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा आहे. राज्यामध्ये मराठी माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसें दिवस कमी होत आहे. अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत. या मराठी शाळा टिकाव्यात म्हणून शासनाने विद्यार्थी संख्येचे निकष बदलले आहेत. शासनाने माध्यमिक शाळांसाठी शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. त्यानुसार विद्यार्थी संख्या आणि तुकडीचे प्रमाण आदिवासी भागामध्ये 15, ग्रामीण भागामध्ये 20 आणि शहरी भागामध्ये 25 केलेली आहे. हा निर्णय फक्त माध्यमिक शाळांना लागू केलेला आहे. राज्यामध्ये हजारो प्राथमिक शाळा आहेत. त्यामधील विद्यार्थी संख्या कमी होत असून तुकड्या टिकविणे अडचणीचे होत आहे. अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे की, शासनाने माध्यमिक शाळांसाठी जो जी.आर. काढलेला आहे तो जी.आर. प्राथमिक शाळांसाठी देखील काढणे आवश्यक आहे. तेव्हा प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत ताबडतोबीने निर्णय घ्यावा अशी मी या औचित्याच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करीत आहे.

--

सभापती : यानंतर सन्माननीय सदस्या डॉ. नीलम गो-हे यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्यास परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

डॉ. नीलम गो-हे : सभापती महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा आहे. मध्य निर्मितीच्या संदर्भात शासनाचे धोरण काय आहे असा प्रश्न मागील डिसेंबरच्या अधिवेशनापासून या सदनामध्ये सातत्याने विचारला जात आहे. सभापती महोदय, माननीय राज्यपालांनी जेव्हा अभिभाषण केले त्यावेळी असे जाहीर केले होते की मध्य निर्मितीच्या नवीन कारखान्यांना परवानगी दिली जाणार नाही. कृषी उत्पादनाचे अनेक प्रकार आहेत. कृषी उत्पादनांपासून ज्यूस, जेली, मिठाई इत्यादी पदार्थ मोठ्या प्रमाणावर तयार केले जातात आणि या पदार्थांना जागतिक बाजारपेठेत देखील या पदार्थ्यांनी मोठे नाव कमावलेले आहे. अशा वेळी शेती उत्पादनावर प्रक्रियाकरणारे उद्योग उभे

..3..

MSS/ KGS/ KTG/ पूर्वी श्री. खंदारे 14:15

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(डॉ. नीलम गो-हे...

करणे आवश्यक असताना या राज्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे माननीय मंत्री महोदय श्री.गणेश नाईक यांनी काजू आणि जांभळापासून मद्य निर्मिती होईल असे सभागृहामध्ये जाहीर केले. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाचे राज्यमंत्री श्री. सचिन अहिर यांनी "त्यास आमचा विरोध आहे" असे जाहीर केल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रातून प्रसिध्द झालेले आहे. तेव्हा या संदर्भात शासनाची नेमकी भूमिका काय आहे ? जर कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरु करण्यास राज्य सरकार परवानगी देणार असेल तर ते उद्योग स्थानिक शेतक-यांच्या सहकारी संस्थांना दिले पाहिजे. जर ते उद्योग धनदांडग्यांच्या आणि धनिकांच्या ताब्यात गेले तर जूस, जेली यासारखे शुध्द पदार्थ मिळणार नाहीत. तेव्हा याबाबतीत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी मी हा औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे.

--

...नंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : यानंतर सन्माननीय सदस्या ॲड.उषा दराडे यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

ॲड.उषा दराडे : सभापती महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा आहे.

सभापती महोदय, मी खालील सार्वजनिक महत्वाच्या व निकडीच्या बाबीवर औचित्याच्या मुद्दा उपस्थित करीत आहे. बीड जिल्हयामध्ये 734 वस्तीशाळा असून त्यापैकी 304 वस्तीशाळांचे श्रेणीवर्धन करण्यात आले आहे. 352 शाळांचे रुपांतर नावीन्यपूर्ण पर्यायी शिक्षण केंद्रात करण्यात आले आहे. उर्वरित 78 शाळा शासन निकषानुसार बंद करण्यात येणे. शासनाच्या दिनांक 31 जुलै, 2009 च्या अध्यादेशावर 78 शिक्षकांना अद्याप नियुक्ती न देणे तसेच त्यांच्यात पसरलेला असतोष व निराशेचे वातावरण. त्यांनी दिनांक 31 मार्च, 2010 पासून उपोषण करण्याचा घेतलेला निर्णय. याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यावी.

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : यानंतर सन्माननीय सदस्या ॲड.उषा दराडे यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

ॲड.उषा दराडे : सभापती महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा आहे.

सभापती महोदय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्राच्या ठिकाणी नर्सेसना मदत करणाऱ्या स्त्री परिचारिकांना पूर्णवेळ काम करुनही अंशकालीन संबोधण्यात येते. वास्तविक पाहता ग्रामीण भागात आरोग्य सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या या महिला राज्याच्या व राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये व्यस्त असणे, त्यांना केवळ 900 रुपये दरमहा वेतन देण्यात येणे, त्यांना रजा व सुट्टीचा लाभ न मिळणे, प्रवास करुनही प्रवास भत्ता मिळत नाही. त्यांच्यावरील अन्याय थांबत नाही. त्यांच्या काही मागण्या आहेत. प्रा.आ.केंद्रामध्ये व उपकेंद्रामध्ये काम करणाऱ्या अंशकालीन स्त्री परिचारिकांना चतुर्थश्रेणीचे वेतन द्यावे, दिनांक 27 फेब्रुवारी, 2008 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे दरमहा 1200 रुपये वेतन देऊन वाढीव थकबाकी देण्यात यावी. स्त्री परिचारिकांना सुट्टीचा लाभ देऊन प्रवास भत्ता देण्यात यावा. नवीन भरती करताना स्त्री परिचारिकांना प्राधान्य देऊन राखीव जागा ठेवण्यात याव्यात. सर्व राखीव जागा भरताना त्यांच्या वारसांना सेवेत सामावून घ्यावे. असा मी औचित्याचा मुद्दा मांडीत आहे.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.संजय केळकर यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

श्री.संजय केळकर : सभापती महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा आहे.

सभापती महोदय, राज्याच्या तिजोरीमध्ये व उत्पन्नामध्ये भर पाडण्याचे सोडून काही विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारीमुळे उत्पन्न टाळण्याचे प्रयत्न होत आहेत. सभापती महोदय, मेहेर डिस्ट्रीलरी प्रायव्हेट लिमिटेड, डहाणू या कंपनीकडे 1992 सालापासून आजतागायत 139 कोटी रुपये व्याज वगळता उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल थकित आहे, हे योग्य नाही. सदर रक्कम उत्पादकाकडून व्याजासह वसूल करण्यात यावी अशा प्रकारचा उच्च न्यायालयाचा आदेश आलेला आहे. परंतु शासन स्तरावर सदर थकबाकी वसुलीची कोणतीच कारवाई दृश्य स्वरुपात दिसून येत नाही. अनेकदा पत्रव्यवहार करुनही उत्तर दिले जात नाही. जिल्हयामध्ये त्या खात्याच्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांकडून वसुली होण्यासारखी परिस्थिती नसल्यामुळे फाईल बंद करण्यात येते की काय अशी भीती वाटत आहे. एका बाजूला थोडीशी थकबाकी झाली तरी विजेचे कनेक्शन कापले जाते. थोर साहित्यिक श्री.ना.धों.महानोर यांच्या घरातील वीज कनेक्शन कापले गेले. शेतकऱ्याने 10-15 हजार रुपये कर्जाची वेळेवर परतफेड केली नाही तर ताबडतोब कारवाई केली जाते. सदर 139 कोटी रुपये मेहेर डिस्ट्रीलरीकडे थकित असताना त्यांच्यावर कोणाची मेहेरनजर आहे? या महत्वाच्या विषयावर औचित्याच्या मुद्याद्वारे मी शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो.

..4..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : यानंतर सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, माझा औचित्याचा मुद्दा आहे.

सभापती महोदय, आज राष्ट्रीय जनगणनेचे काम सुरु होत आहे, त्याच वेळेला मुलांना शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा संसदेने मंजूर केला. त्या कायद्याचा अंमल सुरु होत आहे. माननीय पंतप्रधान देशाला उद्देशून त्या संदर्भात आज भाषण करणार आहेत. मला आपले लक्ष एका महत्वाच्या मुद्याकडे वेधावयाचे आहे. दहावी व बारावीच्या परीक्षा झाल्या असून त्या परीक्षांचे पेपर तपासण्याचे आणि रिझल्ट लावण्याच्या कामाकडे माध्यमिक शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई महापालिकेने स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांवरचा भार कमी करण्यासाठी या शिक्षकांवर राष्ट्रीय जनगणनेचे काम सोपविले आहे. महापालिकेकडे सफाई खात्यात पदवीधर कर्मचारी प्रचंड संख्येने कार्यरत आहेत. जवळजवळ 80 हजाराहून अधिक पदवीधर उपलब्ध असताना त्यांना हे काम न देता शिक्षक रिझल्ट लावण्याचे कामामध्ये व्यग्र आहेत त्यांच्याकडे हे काम दिले तर दहावी व बारावीच्या महत्वाच्या प्रश्नामध्ये चुका होण्याची, रिझल्ट लावण्यामध्ये विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अडथळे निर्माण होतील, ते अडथळे दूर करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी माझी आपल्याला विनंती आहे की, आजच या संदर्भात मुंबई महापालिकेला निर्देश देऊन पर्यायी व्यवस्था करावी. रिझल्टचे काम थांबले तर ते जून-जुलैपर्यंत पुढे जाईल आणि प्रचंड गोंधळ होईल. आपण आज किंवा उद्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नासंबंधी चर्चा करणार आहोत. त्या संदर्भात माझी आपल्यामार्फत शासनाला कळकळीची विनंती आहे. तसेच जे शिक्षक या कामामध्ये व्यग्र आहेत त्यांना हे काम न देता महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनादिले जावे. यासंदर्भात आजच शासनाला आपण निदेश दिले तर बरे होईल. कारण पुढील तीन दिवस सुट्टया आहेत.

श्री. रामनाथ मोते : महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील यांनी जरी मुंबईपुरता प्रश्न उपस्थित केला असला तरी हा प्रश्न केवळ मुंबईपुरताच मर्यादित नसून संपूर्ण राज्यात हीच परिस्थिती असल्याने संपूर्ण राज्यासंबंधीचे निदेश देण्यात यावेत. शाळा सुरु झाल्यानंतर राज्यातील शिक्षक जनगणनेचे काम करण्यास तयार आहेत. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा कालावधी व त्यानंतर पेपर तपासणीचे काम असल्यामुळे राज्याच्या दृष्टीने निदेश देणे आवश्यक आहे.

नंतर 2एल.1....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : मी शेवटी सर्व औचित्याच्या मुद्यांच्या संदर्भातील निदेश देणार आहे. आता सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपला औचित्याचा मुद्दा मांडावा.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, आपल्या दालनात अनेक वेळा चर्चा झाली. तसेच आपणही या विषयावरील लक्षवेधी सूचना मान्य केल्या आहेत. एनआरएचएम ही योजना केंद्रशासनाची असून ती राज्यात राबविली जाते. संपूर्ण ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागात देखील काही भागात ही योजना चालू आहे. दारिद्र्येषेखालील लोकांसाठी विशेषत: ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांना यायोजनेचा फायदा मिळतो. त्यात प्रामुख्याने जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व योजना, रुग्ण कल्याण योजना, लसीकरण व बळकटीकरण योजना अशा अनेक सुविधा या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन दिल्या जातात. यामध्ये होणारी आर्थिक उलाढाल पाहिली तर फार मोठ्या प्रमाणात असते. वाणगीदाखल मी सन 2005 ते सन 2009 मधील आकडे सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या काळात 2908.89 कोटी रुपयाचे ॲलोकेशन आपल्या राज्यासाठी झाले होते. त्यापैकी फक्त 1299.91 कोटी इतकाच खर्च झाला. अशा प्रकारे ही योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे एक मोठे स्थान आहे. कारण या योजनेत पैसा येतो पण त्याचा हिशेब कुठेच लागत नाही, तो दिला जात नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच एनआरएचएम च्या माध्यमातून सुध्दा हिशेब दिला जात नाही. अशा प्रकारे शेवटच्या घटकापर्यंत पैसे न पोहचता यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो आणि आदिवासीला पैसे मिळत नाही. म्हणून यासंबंधीची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. आपल्यामार्फत मी शासनाला अशीही विनंती करणार आहे की, या योजनेची सीआयडीमार्फत सन 2005-2010 या कालावधीतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी.

....2....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : आता सन्माननीय सदस्य श्री. किरण पावसकर यांनी दोन औचित्याचे मुद्दे मांडण्याची परवानगी मागितलेली आहे. त्यांनी आपले औचित्याचे मुद्दे मांडावेत.

श्री. परशुराम उपरकर : सभापती महोदय, राज्यातील मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय व सर्व आरक्षण असलेल्या उमेदवारांकरिता निवडणुकीत किंवा 10 वी नंतर माध्यमिक व उच्च शिक्षण मिळविताना आरक्षणाच्या जागेवर जागा उपलब्ध करताना जात वैधता प्रमाणपत्राची अट शासनाने कायद्याद्वारे शासन निर्णयानुसार जाहिर केलेली आहे. त्यामुळे 10 वी नंतर कोणत्याही प्रवेशाकरिता मागास प्रवर्गातल्या जागेचा अर्ज दाखल करताना व्हॅलिडिटी मिळविण्याकरिता पालकांचे निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारांचे अतोनात हाल होत आहेत. ज्याअर्थी सदर जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्याची अट शासनाने मागास प्रवर्गातील मुलांकरिता इयत्ता 5 वी पासून वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव पाठवून भविष्यात होणारी तारांबळ थांबवावी, याबाबत शासनाने तात्काळ निवेदन करावे.

महोदय, यानंतर आपल्या परवानगीने मी दुसरा औचित्याचा मुद्दा मांडत आहे.

सन 1993 चा बॉम्बस्फोट आणि 26/11 चा हल्ला, हे हल्ले करताना अतिरेक्यांनी समुद्रमार्गे हल्ले केल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. याकरिता शासनाने उपाययोजना म्हणून समुद्र किनारपट्टीवरील निरीक्षण करण्याकरिता व अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीसाठी सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च करुन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 गस्ती नौकांपैकी एक अत्याधुनिक गस्ती नौका दिलेली आहे. या गस्ती नौकेची उद्घाटने झालेली असून या गस्ती नौकेवर प्रशिक्षीत कर्मचारी व इंधनासाठी तरतूद नसल्याने या चारही गस्ती नौका सिंधुदुर्गातील समुद्र किनाऱ्यावर विनावापर उभी आहेत. हल्लीच मागील महिन्यात समुद्र किनाऱ्यावर हाय ॲलर्टच्या सूचना दिलेल्या आहेत. यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला केंद्राकडून मिळालेल्या गस्ती नौका विना वापर उभ्या असल्याने त्या पाण्यात राहून सडून गेल्यामुळे बंदर विभागाने त्याचा लिलाव काढलेला आहे. यामुळे या गस्ती नौकांवर प्रशिक्षित कर्मचारी देऊन गस्ती घालण्यास सुरुवात व्हावी, याबाबत शासनाने तात्काळ निवेदन करावे.

यानंतर श्री. जुन्नरे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती : या ठिकाणी जे औचित्याचे मुद्दे मांडण्यात आलेले आहेत त्या सर्व मुद्यांची शासनाने नोंद घ्यावी. या ठिकाणी सन्माननीय महसूल मंत्री श्री. नारायण राणे येथे उपस्थित आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो की, शिक्षकांना जनगणनेचे जे काम दिले आहे त्याबाबतीत सुध्दा आपण लक्ष घालावे तसेच अन्य मुद्दे सुध्दा महत्वाचे आहेत. विधी मंडळ संबंधित विभागांना यासंदर्भातील माहिती वेळोवेळी कळवित असतेच.

श्री. नारायण राणे : सभापती महोदय, सर्व मुद्यांची नोंद घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

सभापती : आज सकाळी आजच्या कामकाज पत्रिकेच्या संदर्भात विरोधी पक्ष नेते श्री. पांडुरंग फुंडकर, शिवसेनेचे गट नेते श्री. दिवाकर रावते यांच्या सोबत मी आणि गृहमंत्र्यांनी चर्चा केलेली आहे. अजून कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संदर्भातील उत्तर पूर्ण व्हावयाचे आहे तसेच नक्षलवाद चळवळीच्या संदर्भातील चर्चा आणि त्या चर्चेचे उत्तर सुध्दा आजच आपल्याला पूर्ण करावयाचे आहे. त्यामुळे या दोन चर्चेला दोन वेगवेगळे उत्तर घेण्यापेक्षा दोन्ही चर्चेचे उत्तर एकत्रित घेऊ. नक्षलवादी चळवळीच्या विषय हा नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातील अंतिम आठवडयाचा प्रस्ताव होता. म्हणून यासंदर्भात मी असा निर्णय घेत आहे की, लक्षवेधी सूचना झाल्यानंतर नियम 260 अन्वये नक्षलवादी चळवळीच्या संदर्भातील चर्चा सुरु होईल व ही चर्चा झाल्यानंतर या चर्चेस व कायदा व सुव्यवस्था या प्रस्तावावरील चर्चेस सन्माननीय गृहमंत्री एकत्र उत्तर देतील.

डॉ. दीपक सावंत : माननीय गृहमंत्री जेव्हा उत्तराला सुरुवात करतील तेव्हा त्यांनी सांगावे की, या या चर्चेचे हे उत्तर आहे.

सभापती : कायदा व सुव्यवस्थेच्या उत्तराचा एक भाग पूर्ण झाला आणि दुसरा भाग सुरु झाला असेच तुम्हाला म्हणावयाचे आहे ना ? ठीक आहे.

तसेच आज नियम 97 अन्वये सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील तसेच अन्य सदस्यांची अल्पकालीन चर्चा आहे. ती चर्चा आज न घेता सोमवार दिनांक 5 जानेवारी, 2010 रोजी सकाळी 11.30 ते 1.00 या दरम्याने घेतली जाईल व या चर्चेचे उत्तर त्याच दिवशी पूर्ण करण्यात येईल.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

..2

सभापती......

मध्यंतरी 12 मार्च, 2010 रोजी आपण नियम समितीची बैठक घेतली होती. या बैठकीत कामकाजाचे सुसूत्रीकरण रहावे यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीमध्ये ज्या काही 4-5 लक्षवेधी सूचना असतील त्यांना मी 45 मिनिटे वेळ देण्याचे ठरविले होते. हा निर्णय नियम समितीमध्ये एकमताने घेण्यात आला होता. त्या नियम समितीच्या बैठकीत सन्माननीय फुंडकर साहेब येऊ शकले नव्हते त्यामुळे मी त्यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली होती. आज पासून माझी अशी इच्छा आहे की, लक्षवेधी सूचना 4 असो, 5 असो किंवा कितीही असली तरी जसा प्रश्नोत्तराच्या तासाला एक तासाचा अवधी दिला जातो तसाच या लक्षवेधी सूचनेसाठी सुध्दा 45 मिनिटांचा अवधी दिला जाईल.

आता सभागृहाची बैठक मध्यंतरासाठी स्थगित होईल आणि दुपारी 3.00 वाजता पुन: भरेल.

(दुपारी 2.34 ते 3.00 मध्यंतर)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(मध्यंतरानंतर)

(सभापतीस्थानी माननीय उपसभापती)

उप सभापती : आता लक्षवेधी सूचना घेण्यात येतील. आज कामकाज पत्रिकेवर 5 लक्षवेधी सूचना दाखविण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे एका लक्षवेधी सूचनेला 9 मिनिटे मिळणार आहेत. सर्व लक्षवेधी सूचनांसाठी 45 मिनिटे आहेत. आता लक्षवेधी सूचना क्रमांक 1 घेण्यात येईल.

पृ.शी.: जळगाव जिल्हयातील सहकारी पतपेढ्या आर्थिक संकटात येणे

मु.शी.: जळगाव जिल्हयातील सहकारी पतपेढ्या आर्थिक संकटात येणे,यासंबंधी श्री.अरुण गुजराथी, वि.प.स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री.अरूण गुजराथी (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय सहकार मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे अशी विनंती करतो.

"जळगांव जिल्हयातील अनेक सहकारी पतपेढया आर्थिक संकटात येणे, अनेक गरीब नागरिकांच्या ठेवीच्या रकमा परत न मिळणे त्यामुळे सदर पतपेढयांवर प्रशासक नेमण्यासंदर्भात शासनाचे झालेले दुर्लक्ष, सहकार खात्याकडून ठेवीदारांना न्याय न मिळणे जळगांव जिल्हयातील ठेवीदारांना अंशत: रकम देण्यासाठी शासनाने २० कोटी रुपये देण्याची घोषणा करणे, तथापि ती रकम अद्याप ठेवीदारांना प्राप्त न होणे याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठेवीदारांनी उपोषण करणे व जिल्हयातील अनेक तालुक्यांमध्ये निषेध व मोर्चे काढून उक्त ठेवीदारांनी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न करणे, तथापि शासनाचे झालेले दुर्लक्ष परिणामी संबंधित ठेवीदारांमध्ये निर्माण झालेले चिंतेचे व असंतोषाचे वातावरण याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची कार्यवाही व उपाययोजना."

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.प्रकाश सोळंके (सहकार राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

उप सभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे.)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.अरूण गुजराथी : सभापती महोदय, अत्यंत महत्त्वाचा आणि गंभीर विषय आहे. पतपेढ्यांमध्ये एक ते दीड टक्का व्याज जास्त मिळत असल्यामुळे गरीब, मध्यमवर्गीय लोक पतपेढयांमध्ये आपली ठेव ठेवतात. एवढेच नव्हे तर सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक,विधवा यांच्या ठेवी पतपेढयांमध्ये असतात. श्रीमंत, व्यापारी, उद्योजक आपले पैसे पतपेढ्यांमध्ये ठेव म्हणून ठेवत नाही. जळगाव जिल्ह्यामध्ये 907 पतपेढ्या आहेत. यापैकी 40 पतपेढ्या अडचणी आहेत. असे शासनाचे म्हणणे आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे यापेक्षा जास्त पतपेढ्या अडचणीत आहेत. एकूण ठेव 613 कोटी रूपये आहे. त्यातील 103 कोटी रूपये प्राप्त करण्यात आले आहे. 510 कोटी रूपये राहिले आहेत. 210 कोटी रूपयांसाठी जबाबदारी फिक्स केली आहे. सदर 210 कोटी रूपये कसे मिळतील याचा खुलसा मंत्रिमहोदयांनी करावा आणि उर्वरित 300 कोटी रूपये प्राप्त करण्यासाठी शासन पुढे काय करणार आहे ? माझ्या सदर प्रश्नांसंबंधी मंत्रिमहोदयांनी खुलासा केल्यानंतर अजून एक संधी प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी द्यावी ही विनंती.

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अरूण गुजराथी यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या ठेवी पतसंस्थामध्ये असतात. त्यामुळे या विषयाला निश्चितपणे अतिशय महत्व आहे असे मला पहिल्यांदा सांगितले पाहिजे. जळगाव जिल्ह्यामध्ये 900 च्या वर पतसंस्था नोंदणीकृत आहेत. त्यातील 40 पतसंस्था निश्चितपणे अडचणीत आलेल्या आहेत. 40 संस्थांमध्ये जे काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत त्यासंबंधी सहकार खात्याने 2005-2006 वर्ष गृहीत धरून टेस्ट ऑडिट केले. त्यानुसार पुढची कारवाई पतसंस्थांवर करण्यात आली. 31 पतसंस्थांचे टेस्ट ऑडिट करण्याचे आदेश झालेले आहेत. त्यापैकी 29 टेस्ट ऑडिट प्राप्त झालेले आहेत. 2 संस्थांचे रेकॉर्ड मिळत नाही म्हणून ते पूर्ण झालेले नाही. त्यांचे रेकॉर्ड मिळविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. टेस्ट ऑडिटच्या माध्यमातून 26 संस्थांविरोधात कलम 88 ची चौकशी आदेशित करण्यात आली आहे. त्यापैकी 10 संस्थाच्या विरोधात कारवाई पूर्ण झालेली आहे. 16 संस्थांच्या विरोधात कलम 88 ची कारवाई सुरू आहे. 10 संस्थाची कलम 88 द्वाराची चौकशी पूर्ण झालेली असून 110 संचालकांवर 210 .68 कोटी रूपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. एक गोष्ट निश्चितपणे ...4

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.प्रकाश सोळंके.....

सांगितली पाहिजे की, संचालकांचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांच्याकडून वसुली करण्यामध्ये अनंत अडचणी आहेत याची शासनाला जाणीव आहे.

यानंतर श्री.सरफरे....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. प्रकाश सोळंके....

परंतु शेवटी या संचालकांनी विनातारण कर्ज दिले, आपल्या नात्यागोत्यांना पैसे दिले म्हणून त्यांच्यावर सुध्दा जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे यासाठी शासनाने कारवाई केली आहे. त्यांच्याविरुध्द गुन्हे सुध्दा नोंदविण्याचे काम शासनाने केले आहे. सभापती महोदय, दुसरा प्रश्न असा की, यामध्ये ठेवीदारांचे पैसे गुंतलेले आहेत. त्यामध्ये अनेक ठेवीदार सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत, महिला आहेत, परित्यक्त्या आहेत, बी.पी.एल. चे लोक आहेत. यामध्ये 200 कोटींच्या ठेवी आहेत. प्रत्येक ठेवीदाराला प्रत्येकी 10 हजार रुपयेप्रमाणे ठेवी परत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे व त्याप्रमाणे कारवाई सुरु केली आहे. जवळ जवळ 9 कोटी 10 लाख रुपयांचा निधी 124 पतसंस्थांना दिला असून 9 हजार 576 ठेवीदारांना तो परत केला आहे. आजपर्यंत ठेवीदारांना 5 कोटी 3 लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे. आणि आठवडाभरात उर्वरित सभासदांच्या ठेवी परत करण्यात येतील.

सभापती महोदय, समाजसेवक माननीय श्री. अण्णा हजारे हे मागील आठवडयात उपोषणाला बसले होते. आणि त्यांची प्रमुख मागणी शासनाने हे पैसे परत दिले पाहिजेत अशी होती. त्यांची विनंती शासनाने मान्य केली असून 32 कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. आणि 167 कोटी रुपये देण्याचे शासनाने कबूल केले आहे. मघाशी सांगितलेल्या परित्यक्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारी, महिला व बी.पी.एल. या चार कॅटॅगरीमध्ये आणखी काही केसेस समाविष्ट आहेत. त्यामध्ये काही लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे, काही लोकांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. अशा हार्टशीप केसेस आहेत. त्यांना सुध्दा प्रत्येकी 10 हजार रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय झाला आहे. हे पैसे लवकरात लवकर सहकार आयुक्तांच्या खात्यामध्ये जमा केले जातील. आणि 167 कोटी रुपयांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया जुलै 2010 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

श्री. अरुण गुजराथी : सभापती महोदय,...

उपसभापती : मी सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक लक्षवेधी सूचनेकरिता 9 मिनिटांचा वेळ देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे याबाबत माननीय सभापतींनी घेतलेला निर्णय आपण पाळला पाहिजे...

श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेवरील उत्तराने जर माननीय सदस्यांचे समाधान झाले नाही तर उपप्रश्न विचारण्याची संधी त्यांना दिली गेली पाहिजे.

उपसभापती : मंत्रिमहोदयांनी उत्तर देण्यासाठी जास्तीचा वेळ घेतला तर काय करायचे?

श्री. प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय,माननीय सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला सविस्तर उत्तर देणे आवश्यक होते...

उपसभापती : ठीक आहे, मी आता फक्त एकच प्रश्न विचारण्यास अनुमती देत आहे.

श्री. अरुण गुजराथी : सभापती महोदय, महाराष्ट्रातील ठेवीदारांचे संरक्षण करणारा 1999 चा अधिनियम अंमलात आहे काय? असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणार काय? तसेच, सक्षम पतपेढयांमध्ये विलीनीकरण करुन पतपेढयांमधील ठेवीदारांची संपूर्ण रक्कम देण्याचा विचार करणार काय? प्रशासक नेमू नये याकरिता काही पतपेढया कोर्टामध्ये गेल्या आहेत. त्याबाबत शासन काय कारवाई करणार आहे?

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, ज्या पतपेढया कोर्टामध्ये गेल्या आहेत त्यासंबंधी शासनाचे स्थायी आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्याबाबत त्यांच्या बाजूने उभे रहाण्याचा किंवा पाठपुरावा करण्याचे काम हे शासन करील. शेवटी हायकोर्टामध्ये जो निर्णय होईल तो आपल्यावर बंधनकारक राहील. यामध्ये विलीनीकरणाचा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा असून विलीनीकरणासाठी सहकार खात्याच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मी मघाशी सांगितल्याप्रमाणे यामध्ये बऱ्याचशा संस्था एन.पी.ए. वाढल्यामुळे व विनातारण कर्ज दिल्यामुळे तोटयात गेल्या आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन कोणतीही सक्षम संस्था विलीनीकरणासाठी पुढे येत नाही. विलीनीकरण करण्यासाठी एखादी संस्था किंवा बँक पुढे येण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे.

---- (यानंतर सौ. रणदिवे)

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : पेण (जि.रायगड) नजिक बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्यास ग्रामस्थांचा असलेला विरोध

मु. शी. : पेण (जि.रायगड) नजिक बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्यास ग्रामस्थांचा असलेला विरोध यासंबंधी सर्वश्री अनिल परब, किरण पावसकर, परशुराम उपरकर,डॉ.दीपक सावंत,डॉ.नीलम गोऱ्हे,सर्वश्री दिवाकर रावते, जयंत प्र.पाटील,कपिल पाटील वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

ॲड.अनिल परब (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय महसूल मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"पेण (जि.रायगड) नजीक बाळगंगा नदीवर प्रस्तावित धरण बांधण्यास वरसई व गागोदे यासह १३ गावातील ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असणे, उक्त धरणामुळे आसपासची गावे, हजारो एकर जमिन पाण्याखाली जाणार असल्याने ग्रामस्थांचा विरोध असणे, दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०१० रोजी वा त्या दरम्यान धरणाच्या पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीचे मोजमाप करण्याचा ग्रामस्थांचा विरोध असताना देखील प्रंचड पोलिस बंदोबस्त करण्यात येणे, त्यामुळे त्या परिसरातील सुमारे ३ हजार ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलन करुन विरोध करणे, मात्र शासनाने पोलिस बळाचा वापर करुन आंदोलनकर्त्यांना प्रतिबंध करुन जमिनीची मोजणी पूर्ण करणे, शासनाच्या या धोरणामुळे त्या परिसरातील नागरिकांमध्ये पसरलेली संतापाची भावना व पोलिसांच्या दडपशाहीमुळे निर्माण झालेले भितीचे वातावरण याकडे शासनाचे होत असलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, सबब उक्त प्रकरणी सखोल चौकशी करुन संबंधित जमिन मालक व ग्रामस्थ यांना विश्वासात घेऊन धरण बांधण्याबाबत उचित निर्णय घेण्याची नितांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कार्यवाही, उपाययोजना व शासनाची प्रतिक्रिया."

श्री.प्रकाश सोळंके (महसूल राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

. . . .2 पी-2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

. . . .2 पी-3

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

ॲड.अनिल परब : सभापती महोदय, बाळगंगा नदीवर धरण बांधण्याकरता जमीन संपादन करण्यासाठी लोक गेले, तेव्हा त्याला ग्रामस्थांनी बऱ्याच मोठया प्रमाणात विरोध केला. माझा स्पेसिफीक प्रश्न असा आहे की, या कामासाठी ग्रामस्थांचा विरोध आहे.म्हणून जी काही कार्यवाही करावयाची आहे ती ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन केली जाईल का ? यामध्ये आदिवासींच्या जमिनी आहेत हे खरे आहे काय ? तसे असेल तर आदिवासींच्या जमिनीला हात लावणार नाही काय ? याबाबत माननीय मंत्री महोदयांनी खुलासा करावा.

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, याठिकाणी जलसिंचन प्रकल्पासाठी भूसंपादन करावयाचे होते. यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे, त्यांच्या काही मागण्या आहेत. या मागण्यांच्या संदर्भात सुध्दा स्वत: मदत व पुनर्वसन मंत्री महोदयांकडे दि.08-02-2010 रोजी बैठक झ ाालेली आहे. त्या बैठकीच्या वेळेस काही लोकप्रतिनिधींना देखील बोलविण्यात आले होते. तसेच जे पुनर्वसन क्षेत्र आहेत, तेथे जे कार्यकर्ते काम करतात त्यांनाही बैठकीसाठी बोलविण्यात आले होते, अशा प्रकारे 40-45 जणांच्या सोबत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये साधारणत: प्रामुख्याने त्या लोकांच्या ज्या अडचणी आहेत, त्यामध्ये 18 नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्याबाबतीत त्यांचे समाधान करण्यात आलेले आहे. त्यांना जमिनीचा दर वाढवून हवा आहे आणि तो प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे आपण जर आजची परिस्थिती पाहिली तर ग्रामस्थांनी भूसंपादनाच्या बाबतीत सहकार्य दाखविलेले आहे. यामध्ये कोणतीही अडचण राहिलेली नाही हे मला यानिमित्ताने सभागृहाला सांगावयाचे आहे.

श्री.परशुराम उपरकर : सभापती महोदय, आपल्या कायद्यानुसार आधी पुनर्वसन आणि मग धरण बांधावयाचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे काय ?

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, शासनाने ही भूमिका मान्य केलेली आहे.

श्री.परशुराम उपरकर : सभापती महोदय, शासन याठिकाणी तसे करणार आहे काय ?

श्री.प्रकाश सोळंके : सभापती महोदय, होय. अगोदर पुनर्वसनाचे कार्य करावयाचे आणि मग धरणाच्या कामाला सुरुवात करावयाची हे धोरण शासनाने जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे शासनाची ही भूमिका रहाणारच आहे.

. . . .2 पी-4

पृ. शी. : जव्हार (जि.ठाणे) येथील आदिवासी मुलींचा होणारा

लैंगिक छळ

मु. शी. : जव्हार (जि.ठाणे) येथील आदिवासी मुलींचा होणारा लैंगिक छळ यासंबंधी सर्वश्री.जयप्रकाश छाजेड,उल्हास पवार,जैनुद्दीन जव्हेरी, मोहन जोशी,सय्यद ज़मा,अशोक उर्फ भाई जगताप,डॉ.नीलम गोऱ्हे,डॉ.दीपक सावंत,ॲड. अनिल परब,सर्वश्री.परशुराम उपरकर,किरण पावसकर, दिवाकर रावते,संजय केळकर,विनोद तावडे,रामनाथ मोते वि.प.स.यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री.जयप्रकाश छाजेड (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय गृहमंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"जव्हार (जि.ठाणे) येथील 18 ते 25 वर्षे वयोगटातील 12 आदिवासी मुलींच्या अश्लील चित्रफिती तयार करुन बाजारात विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2010 रोजी वा त्या सुमारास निदर्शनास येणे,सदर प्रकार हा गत दोन वर्षापासून सुरु असून या प्रकरणात काही प्रतिष्ठित व्यक्तींचा सहभाग असणे, त्यामुळे सदर प्रकरण दडपण्याचे मोठया प्रमाणात प्रयत्न होणे, परिणामी जव्हार तालुक्यातील आदिवासी जनतेमध्ये पसरलेले भितीचे व चिंतेचे वातावरण, लैंगिक छळ करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होण्याच्या मागणीसाठी जव्हार, वाडा, तलासरी,मोखाडा, पालघर, डहाणू आणि विक्रमगड या तालुक्यांमधून 10 हजारांहून अधिक आदिवासींनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर दिनांक 16 फेब्रुवारी 2010 रोजी मोर्चा काढून या प्रकरणी नि:पक्षपातीपणे चौकशी करण्याची केलेली मागणी, यावर शासनाने केलेली वा करावयाची कार्यवाही."

श्री.रमेश बागवे (गृह राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

. . . .2 पी-5

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

. . . .2 पी-6

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.जयप्रकाश छाजेड : सभापती महोदय, ठाणे जिल्ह्यातील जव्हारमध्ये आदिवासी महिलांचे लैंगिक चित्रण करुन त्याच्या ब्ल्यु-फिल्म्स् तयार करणे आणि त्या वितरित करणे असे गंभीर प्रकार घडलेले आहेत. यासंदर्भात जनक्षोभ झाला, हजारो लोक रस्त्यावर आले आणि त्यांनी मोर्चा काढला.

या लक्षवेधीकडे अतिशय गांभीर्याने पहाणे गरजेचे आहे. आपण सावित्रीबाई फुले यांचे नाव घेतो आणि महिलांच्या ब्ल्यु फिल्म्स् मार्केटमध्ये बिझनेस सारख्या वितरीत होतात ही गोष्ट अतिशय गंभीर आहे.याबाबतीत सरकारने दिलेले उत्तर थातूरमातुर आहे. सरकारने निवेदनामध्ये म्हटलेले आहे की, संबंधित लॉजचा परवाना रद्द केला, संगणकाचा परवाना रद्द केला वगैरे. मुद्दा असा आहे की, यासंबंधात ज्या टोळ्या काम करीत आहेत, त्यांना आळा घालण्यासाठी शासन नक्की काय करणार आहे ? हा महत्वाचा मुद्दा आहे.म्हणून माझा पॉईंटेड प्रश्न आहे की, या सर्व प्रकाराकडे लाईट मूडमध्ये बघता कामा नये. कारण आजच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील चौथ्या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सुध्दा हाच मुद्दा आहे. तेव्हा राज्यभरामध्ये या टोळ्या काम करीत आहेत असे दिसते. म्हणून सरकार याला जरब बसविण्यासाठी एखादा कडक कायदा करणार आहे काय ? हा माझा पहिला प्रश्न आहे. त्यानंतर शेवटचा एक प्रश्न विचारण्यासाठी मला परवानगी देण्यात यावी.

श्री.रमेश बागवे : सभापती महोदय, जव्हार (जि.ठाणे) याठिकाणी एका पिडीत महिलेच्या संदर्भात आताच सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले की, महिलांच्या लैंगिक चित्रफिती काढून त्या विकण्याचा व्यवसाय करतात. मी आपल्या माध्यमातून सांगतो की, जी पिडीत महिला आहे, ती जव्हार येथील कुटीर रुग्णालयामध्ये स्वयंपाकीण म्हणून काम करीत असे. या गुन्ह्याच्या संबंधात पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक केलेली आहे. या पाच आरोपीपैकी जो एक नंबरचा आरोपी आहे, त्याची आणि या पिडित महिलेची ओळख झाली.

यानंतर कु.थोरात . . . .

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. रमेश बागवे....

त्यांचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. त्यानंतर त्यांचे शारीरिक संबंध आले. एप्रिल,2005 पासून नोव्हेंबर,2008 पर्यंत त्यांचे वारंवार शारीरिक संबंध येते होतो. जव्हार येथील राजमहल हॉटेलमध्ये आरोपी आरोपी क्रमांक 1 ने शारीरिक संबंध प्रस्तापित केला असताना त्याने संबंधित पीडित महिलेचे मोबाईलद्वारे चित्रीकरण केले. त्यानंतर त्याने तो मोबाईल दुरुस्ती करण्यासाठी त्याच्या मित्राकडे गेला. तो मोबाईल दुरुस्त न झाल्यामुळे त्याचा मित्र जाकिर आणि आरोपी क्रमांक 1 त्याठिकाणी असलेले दुकानदार श्री.गिरीष चंदवाणी यांच्याकडे गेले आणि त्या चंदवाणी यांनी तो मोबाईल दुरुस्त करतो म्हणून सदर क्लीप त्याच्या लॅपटॉपवर संचित करुन त्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली. ज्यावेळी ती चित्रफित विक्रीस सुरुवात झाली त्यावेळी त्या पीडित महिलेने त्या चंदवाणीस विक्री करु नकोस अशा तऱ्हेची विनंती केली. आरोपी गिरीष चंदवाणी यानी तिला सांगितले की, तुला ती क्लीप देतो तू शिरमाळ या ठिकाणी ये त्याप्रमाणे ती पीडित महिला त्याठिकाणी गेली असता त्याठिक्‍़ाणी एका खोलीत चंदवाणी आणि त्याचा नोकर या दोघांनी तिच्यावर जबरी संभोग केला. हे ठिकाण जव्हारपासून जवळपास तीन कि.मी. अंतरावर आहे. या पाचही आरोपीला या गुन्हयामध्ये अटक करण्यात आली आणि भा.द.वि.कलम प्रमाणे 376, 392,393,417/34 तसेच या कलमा व्यतिरिक्त ती पीडित महिला आदिवासी समाजाची होती. म्हणून ॲट्रॉसिटी ॲक्ट देखील लावलेला आहे. ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अनुषंगाने 3/1/10,3/1/11 व 3/1/12 या व्यतिरिक्त या गुन्हयामध्ये मोबाईलचा वापर केला म्हणून माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या अनुषंगाने 66(ई), 67 आणि 67(अ) अशा प्रकारची कलमे त्यांच्यावर लावण्यात आली आहेत. तसेच महिलेचे बिभत्स प्रदर्शन केले म्हणून कलम तीन व चार अनुषंगाने त्यांच्यावर केस केली आणि या पाचही लोकाना सुमारे सात दिवस, सहा दिवस व दोन दिवस अशा तऱ्हेची पोलीस कस्टडी देऊन त्यांच्यावर केस केलेली आहे. सन्माननीय सदस्यांनी या ठिकाणी सांगितले की, आरोपीच्या विरुध्द कारवाई केली जात नाही. पण या गुन्हयातील आरोपीच्या विरुध्द वेगवेगळया प्रकारची गुन्हे नोंदवण्यात आलेली आहेत. या गुन्हयामध्ये असलेल्या आरोपीचे मोबाईल दुरुस्तीचे दुकान होते, संगणक सेंटर होते, ते दुकान बंद करण्यात आले. हॉटेल राजमहलचा परवाना रद्द करण्यात आला. तसेच हॉटेल व लॉजिंगचे चेकिंग करुन समाधान लॉजचा परवाना देखील रद्द

...2.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. रमेश बागवे....

करण्यात आला. एक आरोपी जॅकी शेख नावाचा होता त्याचे अनधिकृत दुकान होते ते दुकान नगरपालिकेने तोडून नष्ट केलेले आहे. अशा तऱ्हेने या आरोपींवर अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली आहे तसेच या पीडित महिलेला शासनाच्या वतीने पंचवीस हजार रुपयाची मदत देण्यात आलेली आहे. सभापती महोदय, अशा गुन्हयांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या गुन्हयाची बारकाईने चौकशी व्हावी यासाठी हा गुन्हा सी.आय.डी.कडे दि. 30 मार्च, 2010 रोजी वर्ग करण्यात आलेला आहे.

श्री. किरण पावसकर : सभापती महोदय, या गुन्हयाच्या संदर्भात काय कारवाई करण्यात आलेली आहे याबाबतची विस्तृत माहिती माननीय मंत्रिमहोदयांनी दिलेली आहे. पण जवळ जवळ दीड ते दोन वर्षे अगोदर पासून हा प्रकार चालू होता. एका आदिवासी महिलेने धाडस केले आणि शासनाकडे तक्रार केली पण या प्रकरणामध्ये आज पर्यंत जवळ जवळ 16 ते 17 महिला बळी पडलेल्या आहेत. दोन अडीच वर्षापासून त्याठिकाणी हे वासनाकांड चालू होते तेव्हा जव्हार पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यावर शासनाने काही कारवाई केलेली आहे काय? याठिकाणी चालू असलेला हा प्रकार त्यांनी आगोदर निदर्शनास आणून दिला होता काय? सभापती महोदय, या गुन्हयातील चार ते पाच आरोपी माननीय मंत्रिमहोदयांनी याठिकाणी सांगितलेले आहेत. त्यांची दुकाने बंद करण्यात आलेली आहेत पण एवढयाने ही कारवाई पूर्ण होणार नाही. या संदर्भात ठोस कारवाई करण्यासाठी आणि भविष्यामध्ये अशा प्रकारचे गुन्हे होणार नाहीत या दृष्टिकोनातून शासन काय कारवाई करणार आहे?

यानंतर श्री. बरवड...

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. आर. आर. पाटील : सभापती महोदय, ही सगळी केस बघितल्यानंतर आणि पोलिसांनी केलेले काम पाहिल्यानंतर त्या इन्स्पेक्टरला खरे तर बक्षीस द्यावयास पाहिजे. कोणी तक्रार करण्यास येत नसताना त्या संबंधित बाधित स्त्रिला धीर देऊन त्यांनी तक्रारीची नोंद करुन घेतली. सगळ्या आरोपींना पकडलेले आहे. सन्माननीय सदस्य अशा प्रकारच्या 18-19 घटना सांगत आहेत. पण आतापर्यंतच्या तपासामध्ये फक्त तीन घटना आढळून आलेल्या आहेत. त्यात दोन्ही मुलींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांची लग्ने झालेली आहेत. आम्हाला सगळा विसर पडला आहे, आम्हाला आता कोठलाही गुन्हा नोंदवावयाचा नाही अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. जोपर्यंत कोणी तक्रार करीत नाही तोपर्यंत पोलिसांना स्वत:हून चौकशी करण्यामध्ये अनेक वेळा अडचणी येतात. आता तक्रारकर्त्यांचीच अशी इच्छा आहे की, आमच्या तक्रारी पुढे चालवू नयेत, झाली ती बदनामी भरपूर झाली, आता आमची आणखी बदनामी करु नये. सभापती महोदय, हा एक विश्वासघाताचा प्रकार आहे आणि पुढे त्याचा व्यापारी भूमिकेतून गैरफायदा घेतलेला आहे. आज यांसदर्भातील आपले जे कायदे आहेत त्यात भरपूर शिक्षा आहेत. ॲट्रॉसिटी वगैरे सगळी कलमे पोलिसांनी लावलेली आहे. पण अशा स्वरुपाची घटना गोंदिया जिल्ह्यामध्येही घडली, ठाणे जिल्ह्यामध्ये सुध्दा घडली आणि अशा घटना वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून यासंदर्भात काही कडक कायदा करता येईल काय याचाही आम्ही अभ्यास करु आणि लवकरच तशा स्वरुपाचा कायदाही करण्याचा प्रयत्न करु.

...2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ MMP/ SBT/

पृ. शी. : बोरकन्हार (ता.आमगाव,जि.गोंदिया) येथील महिलेची अश्लील चित्रफीत तयार करण्याचा घडलेला प्रकार

मु. शी. : बोरकन्हार (ता.आमगाव,जि.गोंदिया) येथील महिलेची अश्लील चित्रफीत तयार करण्याचा घडलेला प्रकार यासंबंधी सर्वश्री केशवराव मानकर, पांडुरंग फुंडकर, जगदीश गुप्ता, संजय केळकर, वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री. केशवराव मानकर (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय गृह मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"बोरकन्हार (ता.आमगांव, जि.गोंदिया) येथील एका महिलेची अश्लिल चित्रफीत तयार करणे, सदर चित्रफित येथील सरपंचाने काही लोकांना दाखविणे, त्यामुळे संबंधित महिलेची मानसिक स्थिती बिघडणे, याप्रकरणी संबंधित महिला व चित्रफीतीत असलेली व्यक्ती यांनी आमगांव पोलीस स्टेशनला दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१० रोजी तक्रार करणे, परंतु पोलिसांनी फक्त महिलेचीच तक्रार नोंदविणे, तसेच सदर चित्रफीत आपलीच असल्याचे संबंधित महिला आणि व्यक्तीने मान्य करणे, सदर महिलेने केलेल्या तक्रारीवरुन संरपचासह आठ ते दहा लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेणे, परंतु चित्रफीत तयार करणाऱ्या टोळीस पोलिसांनी अद्याप अटक न करणे, यावरुन पोलीस प्रशासनाची दिरंगाई व टाळाटाळ स्पष्ट होणे, आमगांव तालुक्यात चित्रफीत तयार करण्याची तिसरी घटना असणे, त्यामुळे पोलीस प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा लक्षात घेता शासनाने सदर प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता व यावर शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना."

श्री. रमेश बागवे (गृह राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

...3 ...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. केशवराव मानकर : सभापती महोदय, तिसरी आणि चौथी लक्षवेधी सूचना एकसारखीच आहे. पण या लक्षवेधी सूचनेमध्ये थोडासा फरक असा आहे की, ही घटना फिर्यादी महिला व आरोपी यांच्या वैयक्तिक संबंधातून घडलेली आहे. मला माननीय गृहमंत्री श्री. आर. आर. पाटील यांना विनंती करावयाची आहे. ही जी महिला आहे ती अंगणवाडी सेविका आहे. ती आणि तेथील स्थानिक डॉक्टर यांचे आपसात प्रेम होते. त्यांची जेव्हा बदनामी झाली तेव्हा ही महिला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त झाली. तेव्हा गावातील लोकांनी आणि घरच्या लोकांनी तिला समजावले की, जे तुझी बदनामी करीत आहेत त्यांच्या विरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार कर. हे दोघेही पोलिसांमध्ये तक्रार करण्यासाठी गेले. फिर्यादीची तक्रार पोलिसांनी कशी घेतली ही बाब तपासण्याचा प्रश्न आहे. खरे म्हणजे दोघेही आमची बदनामी करण्याचा प्रकार चालू आहे अशी तक्रार करावयास गेले पण त्या ठिकाणी जो तक्रार दाखल करावयास गेला त्याला आरोपी क्रमांक 1 केलेले आहे आणि ज्याच्या विरुध्द तक्रार केली त्याला साक्षीदार केलेले आहे. म्हणजे चोर सोडून सन्याशाला फाशी असा हा प्रकार आहे. माझा पहिला प्रश्न असा आहे की, ज्याच्या विरुध्द तक्रार आहे त्याच्यावर कारवाई होणार काय ? दुसरा प्रश्न असा की, चौकशीसाठी श्री. रहांगडाले, सरपंच आणि शितल फोटो स्टुडियोचे मालक उपेंद्र कटरे यांना पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले काय ? ज्यांनी ही चित्रफित काढली त्याच्यावर आपण कोणत्या प्रकारचा गुन्हा दाखल केला ? या लक्षवेधीमध्ये मी माझ्या तालुक्यातील तीन प्रसंगाच्या संदर्भात उल्लेख केलेला आहे. माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे की, लक्षवेधी सूचना क्रमांक 3 च्या संदर्भात उत्तरामध्ये शासनाने असे म्हटले आहे की, त्यांचा लॉजिंग बोर्डीगचा परवाना रद्द केलेला आहे. पण या लक्षवेधी सूचनेमधील जे सी.डी. प्रकरण झाले आहे ते गोंदियाच्या लॉजमध्ये झालेले आहे. पण त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तिसऱ्या लक्षवेधी सूचनेला न्याय देत असताना लॉजिंग बोर्डीगचा परवाना रद्द केला त्याप्रमाणे या लक्षवेधी सूचनेतील गुन्हा ज्या ठिकाणी घडला त्या लॉजिंग बोडींगचे मालक तसेच फोटोग्राफर, त्यांचे कॅमेरे, त्यांचे संगणक हे सर्व जप्त करुन याची पूर्ण चोकशी करुन या लक्षवेधी सूचनेला आपण न्याय देणार काय ?

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

RDB/ MMP/ SBT/

श्री. रमेश बागवे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी असा प्रश्न विचारला की, श्री. उपेंद्र कटरे यांना अटक केली का ? मी सांगू इच्छितो की, यामध्ये श्री. खुमण पसरराम कटरे आणि उपेंद्र मिसरीमल कटरे असे दोन आरोपी आहेत या दोघांनाही कलम 292 आणि 37 प्रमाणे त्यांच्यावर केस करुन अटक करण्यात आली आहे. हा गुन्हा लॉजमध्ये घडलेला नाही. ही पिडित महिला अंगणवाडी सेविका होती आणि अंगणवाडीसेविका असल्याकारणाने खुमण कटरे नावाचा जो आरोपी आहे तो हत्तीरोग, मलेरिया, पोलिओचे कार्यक्रम राबवित होता त्या कार्यक्रमामध्ये संबंधित पिडित महिला सहभागी होत असे. त्यावेळी त्यांची ओळख झाली आणि त्या ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झाले. सदर गुन्हा लॉजमध्ये घडलेला नसून धर्मशाळेमध्ये घडलेला आहे. त्या ठिकाणची ही धर्मशाळा 1931 पासून आहे.

यानंतर श्री. खंदारे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.रमेश बागवे.....

आणि या धर्मशाळेमध्ये या दोघांनी जाऊन क्लीप काढली, त्यासाठी दोघांची खुषी होती. परंतु त्यांनी ती उपेंद्र कटरे यांना ती दाखविली आणि त्यामुळे या दोघांना या गुन्हयात अटक केलेली आहे.

श्री.केशवराव मानकर : सभापती महोदय, रहांगडाळे याच्यावर गुन्हा दाखल केला होता त्याला का सोडण्यात आले ? या दोघांनी त्याच्याविरुध्द तक्रार केली आहे की, चित्रफीत दाखवून समाजात आमची बदनामी केली जात आहे. त्या रहांगडाळेविरुद गुन्हा दाखल केलेला असताना त्याला साक्षीदार का केले आहे, त्याच्या पाठीमागे कोणती भूमिका आहे, त्या पोलीस स्टेशनमध्ये असे कोणते लक्ष्मी दर्शन घडले आहे ? त्याचे उत्तर आम्हाला पाहिजे.

श्री.रमेश बागवे : खूमण कटरे ही कार्यक्रम राबविणारी व्यक्ती होती. त्या व्यक्तीचे व पिडीत महिलेचे संबंध होते. त्या दोघांचे शारीरिक संबंध असताना त्यांनी ती क्लीप काढली आणि ती क्लीप गावातील लोकांना दाखविली, ती क्लीप सरपंचांनी पाहिली. सरपंचाने ती क्लीप त्या महिलेच्या दिराला दाखविली आहे. त्यामुळे तिचा दीर व पिडीत महिला तक्रार करण्यास गेली त्यावेळी त्या फिर्यादीची तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल केलेला आहे.

डॉ.नीलम गो-हे : सभापती महोदय, या छायाचित्रांचा व्यापार होतो. आणि व्यापारासाठी या महिलेची अशा पध्दतीची छायाचित्रे काढली गेली. दुर्दैवाने एका नव्हे तर प्रत्येक ठिकाणी असे घडते की, त्या मुलीबरोबर प्रेमसंबंध तयार करावयाचे आणि त्या अश्लील सी.डी.विकायच्या हा दलालांचा एक धंदा झालेला आहे. यामध्ये त्यांच्या वैयक्तिक प्रेमसंबंधाचा नाही. बाजारी गोष्टींसाठी अश्लील छायाचित्रांचा उपयोग केलेला असल्यामुळे संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे. हा एक संघटित गुन्हेगारीचा भाग आहे. संघटित गुन्हेगारीमध्ये शस्त्र, अंमली पदार्थ आणि अश्लील छायाचित्र आणि अश्लील सी.डी.यांचाही समावेश होतो. त्यामुळे संघटित गुन्हेगारी कायद्यान्वये या लोकांना मोक्का लावला जाईल का ?

श्री.रमेश बागवे : सभापती महोदय, आताच सन्माननीय गृहमंत्री यांनी मला असे सांगितले की, अशाप्रकारच्या गंभीर गुन्हयाला जरब बसविण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करता येतील काय ही बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

2....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : दुर्धर आरोग्य अभियानांतर्गत पुणे जिल्हयातील पिडीत विद्यार्थ्यांवर कमी संख्येने शस्त्रक्रिया करण्यात येणे

मु. शी. : दुर्धर आरोग्य अभियानांतर्गत पुणे जिल्हयातील पिडीत विद्यार्थ्यांवर कमी संख्येने शस्त्रक्रिया करण्यात येणे यासंबंधी सर्वश्री मोहन जोशी, जयप्रकाश छाजेड,वि. प. स. यांनी दिलेली लक्षवेधी सूचना.

श्री.मोहन जोशी (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी नियम 101 अन्वये पुढील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आपल्या अनुमतीने सन्माननीय सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो आणि त्याबाबत त्यांनी निवेदन करावे, अशी विनंती करतो.

"राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या दुर्धर आरोग्य अभियानातून निधी मिळून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या 2 वर्षापासून पुणे जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना शस्त्रक्रियेपासून वंचित ठेवले असल्याचे माहे जानेवारी, 2010 मध्ये वा त्यासुमारास निदर्शनास येणे, या योजनेअंतर्गत इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करुन दुर्धर आजाराने पिडीताचा शोध घेऊन त्यांच्या शस्त्रक्रिया करण्यात येणे, तथापि पुण्यात 2 वर्षाच्या कालावधीत फक्त 9 शस्त्रक्रिया करण्यात येणे, जनसामान्यांच्या सार्वजनिक हिताच्या योजनांकडे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे गरीब रुग्ण विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नसणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये व सर्वसामान्य जनतेत पसरलेला तीव्र असंतोष व संतापाची भावना, याबाबत राज्य शासनाने केलेली वा करावयाची कार्यवाही व उपाययोजना आणि याबाबत शासनाची प्रतिक्रिया "

प्रा.फौजिया खान (शालेय शिक्षण राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सूचनेसंबंधीच्या निवेदनाच्या प्रती माननीय सदस्यांना आधीच वितरित केल्या असल्यामुळे मी ते निवेदन आपल्या अनुमतीने सभागृहाच्या पटलावर ठेवतो.

उपसभापती : निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आले आहे.

निवेदन

(प्रेस : येथे सोबतचे निवेदन छापावे)

3....

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.मोहन जोशी : या राज्यामध्ये दारिद्रय रेषेखालील गरीब पालकांना आपल्या पाल्याच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी चांगले काम करता येत नाही, आपल्या मुलाचा इलाज करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात. अशा विद्यार्थ्यांना गंभीर आजार असेल मग हृदयरोग असेल कर्करोग असेल अशा भयानक रोगावर उपचार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळतो. शासनाकडून मागील दोन वर्षाच्या संदर्भात उत्तर आलेले आहे. त्यानुसार आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या 3 वर्षात केवळ 101 केसेस उघडकीस आलेल्या आहेत. यामध्ये हृदयरोग, मूत्रपिंडाचा आजार, कर्करोग असे भयंकर आजार असल्याचे आढळलेले आहे. असे असताना पुणे जिल्हयात गेल्या 3 वर्षात फक्त 33 केसेस केलेल्या आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून केंद्राकडून पैसा येतो. तरी देखील आरोग्य खात्यामार्फत गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर किती दिवसामध्ये परवानगी देण्यात येते. ही परवानगी लवकरात लवकर न दिल्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचा आजार बळावतो आणि त्यात काही विद्यार्थी दगावतात. त्याला जबाबदार कोण आहे ? म्हणून संबंधितांकडून अर्ज प्राप्त होताच ही परवानगी विनाविलंब दिली पाहिजे व या विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचविले पाहिजे अशी मी विनंती करतो. जीवनदायी आरोग्य योजनेचा निधी कमी पडतो म्हणून दरवर्षी अंदाजपत्रकात तरतूद केली जाते. त्याप्रमाणे ती करुन महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी काही योजना आहे काय, ज्या योजनेमुळे या विद्यार्थ्यांचा जो 3-3 वर्षे अनुशेष राहिलेला आहे तो भरुन काढता येईल आणि त्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. असा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल काय किंवा शासनाच्या विचाराधीन अशी योजना आहे काय ?

यानंतर श्री.शिगम....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

MSS/ SBT/ MMP/ KTG/ पूर्वी श्री. खंदारे 15:30

प्रा. फौजिया खान : सभापती महोदय, आरोग्य कार्यक्रमानुसार राज्यातील पहिली ते दहावी पर्यन्तच्या सर्व शालेय विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी होत असते. या आरोग्य तपासणीसाठी केन्द्र शासनाचे पैसे येतात. ही तपासणी मागील वर्षापर्यन्त राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत होत होती. या वर्षापासून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी जीवनदायी योजना अंमलात आणलेली आहे. शस्त्रक्रियेसाठी पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पैसे दिले जातात, विद्यार्थ्यांवर मोफत शस्त्रक्रिया केली जाते. सन 2008-09मध्ये शस्त्रक्रियेसाठी पात्र असे 68 विद्यार्थी आढळले. त्यातील 26 विद्यार्थ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. 2008-09मध्ये 32 विद्यार्थ्यांकडून अर्ज प्राप्त झालेले नसल्यामुळे त्यांच्यावरील उपचार थांबलेले आहेत. विद्यार्थ्यांकडून अर्ज आल्या शिवाय पुढील कार्यवाही होऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत त्यांनी सिंपल डॉक्युमेंट जोडले पाहिजेत.

श्री. दिवाकर रावते :सिंपल डॉक्युमेंट म्हणजे काय ?

श्रीमती फौजिया खान : सिंपल डॉक्युमेंट म्हणजे डोमिसाईल सर्टिफिकेट इत्यादी. डोमिसाईल सर्टिफिकेट प्राप्त होत नसल्यामुळे शस्त्रक्रिया थांबलेल्या आहेत. आरोग्य विभागामुळे त्या थांबलेल्या नाहीत. येणा-या आर्थिक वर्षपासून जीवनदायी योजनेमध्ये आमुलाग्र बदल करण्यात येऊन नवीन राजीव गांधी आरोग्यश्री योजना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. आंध्रप्रदेश राज्याने राबविलेल्या योजनेच्या धर्तीवर ही योजना प्रस्तावित आहे. मंत्रिमंडळाने या योजनेला तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. यासंदर्भात माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमलेली आहे. इन्शुरन्स कंपनीकडून ही योजना अमलात येणार आहे. उत्पन्नाची मर्यादा ठरवून कुटुंबाला हेल्थ कार्ड देण्यात येणार आहे. ही पेपरलेस, कॅशलेस योजना होणार आहे. हे हेल्थ कार्ड घेऊन रुग्णालयातून शस्त्रक्रिया करुन घेता येईल. या योजनेंतर्गत आजारांची आणि रुग्णालयाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे.

श्री. राजन तेली : आम्ही जेव्हा पंचायती राज समितीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शाळांची तपासणी करतो त्यावेळी दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेले विद्यार्थी फार मोठ्या संख्येने आढळू येतात. तेव्हा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामधून शालेय आरोग्य तपासणीच्या वेळी दुर्धर आजाराने ग्रस्त असलेले जे जे विद्यार्थी आढळून येतात त्यांची एकत्रितपणे शस्त्रक्रिया करण्यात येईल काय ?

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

प्रा. फौजिया खान : आता शासना तर्फे राजीव गांधी आरोग्यश्री योजना राबविण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत सन्माननीय सदस्यांनी केलेल्या सूचनेचा जरुर विचार करण्यात येईल.

.....नंतर श्री. भोगले...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

<u>विशेष उल्लेख</u>

पृ. शी. : हिंगोली जिल्हयातील संत श्री नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थळ व पुरातन मंदिरास ऐतिहासिक वास्तुचा दर्जा देणे

मु. शी. : हिंगोली जिल्हयातील संत श्री नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थळ व पुरातन मंदिरास ऐतिहासिक वास्तुचा दर्जा देणे याबाबत श्री.चरणसिंग सप्रा,वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : माननीय सदस्य श्री.चरणसिंग सप्रा यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री.चरणसिंग सप्रा (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडतो.

महाराष्ट्रातील थोर संत श्री नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान हिंगोली जिल्हयातील नरसी नामदेव येथे असून याठिकाणी देशातून व राज्यातून मोठया प्रमाणात भाविक येत असतात. परंतु तेथे भाविकांसाठी मुलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे भाविकांना त्रास होत आहे. तेथे निसर्गरम्य परिसर असून त्याठिकाणी पुरातन मंदिर आहे. या पुरातन मंदिराचा विकासही झालेला नाही. श्री क्षेत्र संत नामदेव महाराजांच्या जन्मस्थळास व पुरातन मंदिरास ऐतिहासिक वास्तू म्हणून घोषित करावे आणि संत नामदेव महाराजांचे स्मारक उभे करणे, तेथील पुरातन मंदिराचा विकास करणे व तेथे येणाऱ्या भाविकांना मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या सार्वजनिक दृष्टया महत्वाच्या बाबीकडे मी या विशेष उल्लेखाद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छितो.

..2.

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : राज्यातील 35 हजार गावांमध्ये ग्रंथालयाची स्थापना न होणे

मु. शी. : राज्यातील 35 हजार गावांमध्ये ग्रंथालयाची स्थापना न होणे याबाबत ॲड.उषा दराडे, वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : माननीय सदस्या ॲड.उषा दराडे यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

ॲड.उषा दराडे (विधानसभेने निवडलेल्या) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडते.

राज्यात गाव तेथे ग्रंथालय या धोरणानुसार 15 हजार गावात ग्रंथालये स्थापन करण्यात येणे, अद्याप 35 हजार गावात ग्रंथालये उभारण्यात न येणे, ग्रंथालय संघटनेच्या वर्षानुवर्षे मागण्या प्रलंबित असणे, राज्यातील ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना अद्याप सेवाशर्ती लागू न केल्यामुळे वेतनश्रेणी न मिळणे, गाव तिथे ग्रंथालय यासाठी ग्रूप ग्रामपंचायतीची अट अडचणीची ठरणे, ग्रंथालयाच्या वर्गवारीनुसार अनुदानात वाढ न होणे, प्रत्येक जिल्हयात ग्रंथालय स्थापनेसाठी दरवर्षी अपुरा निधी प्रत्येक जिल्हयाच्या नियोजन विभागाकडून वितरीत होणे, या बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी होणारा विलंब, पर्यायाने ग्रंथालय कर्मचारी वर्गात पसरलेला असंतोष व निराशेचे वातावरण व त्याबाबत शासनाने उपाययोजना करावी याकडे मी या विशेष उल्लेखाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधू इच्छिते.

..3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : कोळसा या खनिज पदार्थाच्या साठवणुकीमुळे भूगर्भातील पाणी साठयावर होत असलेला दुष्परिणाम

मु. शी. : कोळसा या खनिज पदार्थाच्या साठवणुकीमुळे भूगर्भातील पाणी साठयावर होत असलेला दुष्परिणाम याबाबत श्री.संजय केळकर, वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : माननीय सदस्य श्री.संजय केळकर यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री.संजय केळकर (कोकण विभाग पदवीधर) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडतो.

कोळसा या खनिजामुळे सामान्य जतनेच्या आरोग्यावर परिणाम होतात, त्याच्या साठवणुकीमुळे पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होऊन भूगर्भातील पाणी दूषित होते, या बाबी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्या दि.9.2.2010 च्या पत्रान्वये मान्य केलेल्या आहेत व त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिल्याचे कळविले आहे. कोळशापासून प्रदूषण होते हे सनातन सत्य असताना शासनाने रत्नागिरी जिल्हयातील सपाट गोळप परिसरातील फिनोलेक्सच्या औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेस मंजुरी दिलेली आहे. सदरची बाब ग्रामस्थांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी असून भविष्यात त्या भागातील पाणीसाठे व बागायतीवर विपरित परिणाम करणारी आहे. परिसरातील जनतेच्या मागणीनुसार फेर जनसुनावणी घेतल्याशिवाय फिनोलेक्सच्या वीज प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येऊ नये. सदर विषय अतिमहत्वाचा व सार्वजनिक हिताचा असल्याने तो मी आज सभागृहात विशेष उल्लेखाद्वारे उपस्थित करीत आहे.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील अडचणी दूर करणे

मु. शी. : मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील अडचणी दूर करणे याबाबत श्री.मोहन जोशी,वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : मा□□□य सदस्य श्री.मोहन जोशी यां□ विशेष उल्ले□ासंबंधीची सूच□ दिली आहे. त्यां□ ती मांडावी.

श्री.मोहन जोशी (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्ले□ासंबंधीची सूच□ मांडतो.

प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या मेट्रो प्रकल्पातील सुमारे 2356 कोटी रुपये खर्चाचा आणि 11.4 कि.मी. लांबीचा वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर हा अतिशय महत्वाचा उड्डाणपूल आहे. नियोजित वेळेनुसार डिसेंबर 2010 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची तारीख असून 50 ते 55 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. परंतु या मार्गातील वर्सोवा-अंधेरी ह्या मार्गाचे आराखडे मंजुरीसाठी रेल्वेकडे पाठविण्यात आले आहेत. परंतु वेळोवेळी शंकानिरसन करुनही रेल्वेने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. रेल्वेची मंजुरी, त्यानंतर मिळणारे मेगा ब्लॉक व ठरवून दिलेल्या कालावधीतच करावे लागणारे काम यामुळे उड्डाणपुलाच्या कामात व्यत्यय येत आहे. राज्य शासनाने मेट्रो रेल्वेसाठी येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने करावयाची कार्यवाही याबाबत या सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या मुद्याबाबत मी विशेष उल्लेखाद्वारे शासनाचे लक्ष वेधू इच्छितो.

..5..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सुपीक जमीन खनिज प्रकल्पासाठी संपादित करण्याचा प्रयत्न सुरु असणे

मु. शी. : सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सुपीक जमीन खनिज प्रकल्पासाठी संपादित करण्याचा प्रयत्न सुरु असणे याबाबत ॲड.गुरुनाथ कुळकर्णी,वि.प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : माननीय सदस्य ॲड.गुरुनाथ कुळकर्णी यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

ॲड.गुरुनाथ कुळकर्णी (नामनियुक्त) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडतो.

सभापती महोदय, सिंधुदुर्ग जिल्हयात, विशेषत: राज्याचे औद्योगिक धोरण निश्चित करण्यात आले त्यावेळी कोणताही मोठा उद्योग किंवा निसर्गाला हानीकारक ठरेल असे उद्योग त्या जिल्हयामध्ये येऊ नयेत आणि पर्यटन, मासेमारी व फलोत्पादन या प्रमुख उद्योगांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग त्याठिकाणी यावेत अशी भूमिका घेण्यात आली होती. दुर्दैवाने आज त्या जिल्हयामध्ये खाणीमुळे निसर्गाचा ऱ्हास होत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हयातील दोडामार्ग, सावंतवाडी तालुक्यात खनिज प्रकल्पांना ग्रामस्थांचा होत असलेला विरोध, त्यातच आता डोंगरपाल व गाळेल येथे खनिज प्रकल्प उभारण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय, या गावात फळबागा मोठया प्रमाणात असणे...

(नंतर 2व्ही.1...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी .....

ही सुपीक जमीन खनिज प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार असल्यामुळे तेथील ग्रामस्थांत पसरलेले चिंतेचे वातावरण, यासाठी डोंगरपाल येथे 12 एप्रिल, 2010 व गाळेल येथे 20 एप्रिल, 2010 रोजी खनिज प्रकल्पाबाबतची जनसुनावणी घेण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय, सुपीक व बागायती जमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात येणार असल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांवर ओढवणारी उपासमारीची परिस्थिती याविरुध्द तेथील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा घेतलेला निर्णय, यावर शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची भूमिका अशी मी विशेष उल्लेखाची सूचना देत आहे.

...2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : महाड (जि. रायगड) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची झालेली दुरवस्था

मु. शी. : महाड (जि. रायगड) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची झालेली दुरवस्था याबाबत श्री. किरण पावसकर, वि. प. स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : माननीय सदस्य श्री. किरण पावसकर यांनी विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना दिली आहे. त्यांनी ती मांडावी.

श्री. किरण पावसकर (विधानसभेने निवडलेले) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्लेखासंबंधीची सूचना मांडतो.

महाड (जि. रायगड) येथील शिवाजी चौकात 20 कोटी रुपये खर्च करुन उभारण्यात आलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाची देखभालीअभावी दयनीय अवस्था झालेली आहे. काही काळाने हे स्मारक केवळ बाहेरुनच पाहून समाधान मानण्याची वेळ येण्याची शक्यता, या बहुउद्देशीय राष्ट्रीय स्मारकामध्ये वाचनालय, ग्रंथालय, म्युझियम, अभ्यासिका, दोन छोटी सभागृहे, तरणतलाव, काही कार्यालयांसाठी जागा देण्यात आलेल्या असणे, तसेच सुरबा नाना टिपणीस सभागृह/नाट्यगृह हे एकमेव दालन सध्या वापरामध्ये असून त्या नाट्यगृहाची अवस्था देखील दिवसेदिवस बिकट होत चालली असताना त्याकडे शासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाची जी हेळसांड होत आहे त्याकडे शासनाने लक्ष घालण्यासाठी मी विशेष उल्लेखाची सूचना देत आहे.

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : ठाणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेवा मदतनीसांना नोव्हेंबर, 2009 पासून मानधन न मिळणे

मु. शी. : ठाणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेवा मदतनीसांना नोव्हेंबर, 2009 पासून मानधन न मिळणे याबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे, वि. प.स. यांनी दिलेली विशेष उल्लेखाची सूचना.

उपसभापती : मा□□य सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यां□ विशेष उल्ले□ासंबंधीची सूच□ दिली आहे. त्यां□ ती मांडावी.

डॉ. नीलम गोऱ्हे (विधानसभेने निवडलेल्या) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने पुढील विशेष उल्ले□ासंबंधीची सूच□ मांडते.

ठाणे जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका मदतनीसांना नोव्हेंबर, 2009 पासून मानधन तर मिळालेच नाही परंतु त्यांना देण्यात येणारे टीएडीएची रक्कम देखील सन 2005 ची देण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे एप्रिल, 2008 पासूनच्या वाढीव मानधनाची थकबाकीही अद्याप बाकी आहे. या सर्व रकमेचा निधी जिल्हा परिषदेकडे येऊन देण्यास टाळाटाळ व विलंब करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका मदतनीसांवर राज्य शासनाने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत मध्यम व गंभीर कुपोषित बालकांचे एकात्मिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी टाकण्यात येणे, त्या कामासाठी त्यांना 10 तास काम करावे लागणार आहे. खरे पाहता त्यांचा चार तासाचा कालावधी असताना जास्त वेळ काम करावे लागणार असल्यामुळे त्यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी ठाणे जिल्हा परिषद कार्यालयावर थाळीनाद मोर्चा काढला असणे, याप्रकरणी शासनाने लक्ष वेधण्यासाठी मी विशेष उल्लेखाची सूचना देत आहे.

....4....

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

पृ. शी. : मुंबई प्राथमिक शिक्षण विधेयक.

L. A. BILL NO. LXVIII OF 2009

(A BILL FURTHER TO AMEND THE BOMBAY PRIMARY EDUCATION ACT, 1947.)

प्रा. फौजिया खान (शालेय शिक्षण राज्यमंत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे सन 2009 चे वि. स. वि. क्रमांक 68-मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, 1947 यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक मांडते.

उपसभापती : विधेयक मांडण्यात आले आहे.

यानंतर श्री. जुन्नरे ....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

प्रा. फौजिया खान :सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमती ने सन 2009 चे वि.स.वि. क्रमांक 68 - मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम,1947 यात आणखी सुधारणा विधेयक, 2009 विचारात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडते.

सभापती महोदय, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा यामध्ये 1947 पासून शिक्षण मंडळ होते. त्या शिक्षणमंडळात बदल आणणारे हे छोटेस विधेयक आहे. अगोदर शिक्षण मंडळातील सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता कमी होती व त्यामध्ये अजून चांगल्या बाबींचा समोवश व्हावा यासाठी हे विधेयक येथे आणलेले आहे. टोटल शाळा मंडळातील सदस्यांची संख्या पूर्वी 12 ते 16 एवढी होती ती संख्या या विधेयकामध्ये तशीच राहणार आहे. कलम 4 (1) हे सुध्दा तसेच राहणार आहे. कलम 4(2) अनुसार शासन द्वारा नामनिर्देषित किमान 2 आणि कमाल 3 असे सदस्य अगोदर होते. परंतु आता यामध्ये शासनाच्या सदस्यांची संख्या 5 राहणार आहे. कलम 4(4) अनुसार 5 सदस्यांमधून 1 शासकीय अधिकारी राहतील आणि बाकीचे जे 4 सदस्य राहतील त्यामध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या संदस्यांची संख्या 1 राहणार आहे, 1 ओबीसी असणार असून 1 सदस्य अल्पसंख्याक समाजाचा तसेच एक सर्वसाधारण समाजाचा सदस्य राहणार आहे. या शिक्षण मंडळावरील सदस्यांची शैक्षणिक अर्हता पूर्वी 10 वी पर्यंत होती परंतु आता कमीतकमी पदवीपर्यंत शैक्षणिक अर्हता राहणार आहे. नगरपरिषदा कडून जे सदस्य नियुक्त होणार आहेत त्या सदस्यांची संख्या 7 असून यामध्ये 1 अनुसूचित जाती व 1 सदस्य अनुसूचित जमातीची राहणार आहेत. जर अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचे सदस्य मिळाले नाहीत तर दोन्ही पैकी हे सदस्य राहणार आहेत.

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. आमच्याकडे विधेयक मराठी सुध्दा आहे. बॉम्बे-मुंबई हा वेगळा विषय आहे. या विधेयकाच्या संदर्भात बॉम्बेचे मुंबई हा सुध्दा वेगळा विषय आहे. परंतु गुरुवार दिनांक 30 ऑक्टोबर,1980 रोजी आदेश निघाले त्यावेळेस बॉम्बेचे मुंबई झालेले नव्हते. त्यावेळेला जे जे कायदे बॉम्बे नावाने होते ते ते महाराष्ट्राचे कायदे म्हणून करण्यात आले. परंतु आता महाराष्ट्र राज्याचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असतांना जी मुले शिक्षण घेणार आहेत त्यांना या महाराष्ट्राची, मुंबईची आणि या मातीची आता ओळख होणार आहे. त्या शिक्षणाचे विधेयक अजूनपर्यंत Further to amend the Bombay

...2...

SGJ/ KTG/ SBT/ 15:45

श्री. दिवाकर रावते.....

Primary Education Act, 1947 आलेले नाही. स्टँप ॲक्ट हा 1958 चा होता. परंतु हा ॲक्ट 1947 चा आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर या महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर महाराष्ट्रा करिता जे जे कायदे होते ते बदलले गेले. परंतु हा कायदा का बदलला गेला नाही ? असा माझा सवाल आहे. काल मी आपणास विनंती केली होती की, आपल्या दालनात एक तातडीची बैठक बोलवा परंतु त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. या ठिकाणी हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी कायदा बदलविण्यात येईल असेही सांगण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या कायद्यात आपण कोणत्या तारखेला बदल करणार आहात त्याची तारीख आम्हाला समजली पाहिजे आहे. कायद्यात बदल होतांना राज्याचे मुख्य सचिव, तसेच जेवढे जेवढे विभाग आहेत त्या विभागाच्या मुख्य सचिवांना बोलवावे लागणार आहे. या कायद्याच्या वरचे पान एकच असेल परंतु कायद्याची थप्पी मोठी असणार आहे. 50 वर्षात आपण का बदल केला नाही हे सुध्दा महाराष्ट्राच्या चव्हाटयावर येणार आहे. पुढच्या अधिवेशनापर्यंत बदल करण्याची आमची इच्छा नाही. हे अधिवेशन संपण्याच्या आत आपल्याला कायद्यात बदल करावयाचा आहे. यामध्ये आपल्याला आता चालढकल करता येणार नाही. मी आपल्याला सांगितले होते की, या कायद्याच्या संदर्भात आपल्या दालनात एक तातडीची बैठक घ्या. या बैठकीसाठी राज्याचे मुख्य सचिव, विधी मंडळाचे प्रधान सचिव तसेच सर्व विभागाच्या प्रधान सचिवांना उपस्थित राहावे लागणार आहे. या कायद्यात कोणत्या तारखेला बदल केला जाणार आहे त्याची तारीख आम्हाला समजली पाहिजे तसेच या सभागृहालाही ते समजले पाहिजे. या या तारखेला कायदे बदलल्याचे विधेयक येईल आणि हे विधेयक चर्चा न करता एक मताने मंजूर करु असे सांगितले पाहिजे. नाही तर हे असेच चालू राहणार आहे.

यानंतर श्री. भारवि....

असुधारित प्रत / प्रसिध्दीसाठी नाही

उप सभापती : माननीय मुख्यमंत्री, आपण स्वत:, मुख्य सचिव यांची एक बैठक माननीय सभापती महोदयांच्या दालनात ह्या मंगळवारी बोलवावी. या बैठकीनंतर आपल्याला निर्णय घेता येईल. ज्यावेळी माननीय मंत्री श्री.नारायण राणे यांनी सभागृहाला अवगत केले होते, त्यावेळी ही बैठक घेण्याचे सभागृहाला पीठासीन अधिकारी यांनी अवगत केले होते. हा प्रश्न एकदा तडीस लागू द्यावा. ह्या मंगळवारी किंवा बुधवारी माननीय सभापती महोदय यांच्या दालनात बैठक बोलावून सदर प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्याकरिता घेण्यात येईल.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, माननीय महसूल मंत्री श्री.नारायण राणे यांनी आम्ही बदल करीत आहोत. तथापि, विधेयक विधानसभेने संमत केले असल्यामुळे ते पुन्हा खाली पाठविणे योग्य होणार नाही, असे सांगून सभागृहाची अनुमती घेतली आहे. त्यामुळे चुकीचा कायदा येथे करीत असताना माननीय शिक्षण मंत्री यांनी देखील सभागृहाची अनुमती घेतली पाहिजे.

उप सभापती : यासंबंधी आपण मंगळवारी किंवा बुधवारी बैठक घेऊ या.

प्रा. फौजिया खान : सभापती महोदय, मी सभागृहाची अनुमती मागते. हे विधेयक आता आपण विधानसभेकडे पाठवू शकत नाही. पुढच्या अधिवेशनामध्ये या विधेयकाच्या शीर्षामध्ये "महाराष्ट्र" असा बदल करण्यात येईल.

सभापती महोदय, नगरपालिकांकडून नियुक्त होणाऱ्या सदस्यांमधून कलम 4 (6) मध्ये तरतूद अशी आहे की, एक अनुसूचित जाती आणि एक अनुसूचित जमातीचा सदस्य असणार आहे. तो जर उपलब्ध नसेल तर मग अन्य जातीचा घेऊ शकेल. मेंबर्सची शिक्षण अर्हता एच.एस.सी.पर्यंत राहणार आहे. नगरपालिकेकडून सदस्य निवडून जाणार आहेत. त्यापैकी किमान 3 सदस्य हे पदवीपर्यंत शिकलेले असावेत. असे हे विधेयक आहे.

प्रश्न प्रस्तुत झाला.

...2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.रामनाथ मोते (कोकण विभाग शिक्षक) : अध्यक्ष महोदय, मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम 1947 यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक क्रमांक 68 आणले आहे. त्यावर माझे मनोगत व्यक्त करण्यासाठी मी उभा आहे.

हे विधेयक वाचल्यानंतर शासनाने सुधारणा करण्याचे निश्चित केले आहे हे दिसून येते. यात दोन सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. नगरपालिका, महानगरपालिकांची शिक्षण मंडळे आहेत. या शिक्षण मंडळातील शासन नियुक्त सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचे आणि सदस्य म्हणून होण्यासाठी जी अर्हता निश्चित केली होती त्यात वाढ करण्याचे, सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शासनाला अशा प्रकारची सुधारणा का करावी लागली ?

यानंतर श्री.सरफरे...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

DGS/ SBT/ KTG/ 15:55

श्री. रामनाथ मोते..

नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांच्या शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांची गुणवत्ता वाढावी, त्या शाळांमध्ये शिकणारी मुले ही श्रीमंतांची नाहीत. सर्वसामान्य गोरगरीब, झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांची आहेत. हे सर्व लोक फार मोठया प्रमाणात असलेली खाजगी शाळांची फी भरु शकत नाहीत. अशी गोरगरीबांची मुले या शाळांमध्ये शिकत आहेत. आणि म्हणून त्यांना सुध्दा खाजगी शाळांसारखे चांगले दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा, त्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा मिळण्याचा हक्क आहे. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने सर्वांना चांगले दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी, सर्वप्रकारच्या सुविधा पुरविण्याची व त्यांची गुणवत्ता वाढविण्याची जबाबदारी शिक्षण मंडळाची आहे. परंतु या शिक्षण मंडळाचे जे पदाधिकारी आहेत, संचालक आहेत किंवा जे सदस्य आहेत त्यांची अर्हता विचारात घेतली तर चौथी उत्तीर्ण झालेली माणसे या शिक्षण मंडळाचे सदस्य होत होते. असा प्रकार ठाणे महानगरपालिकेमध्ये घडला. तेथील शिक्षण मंडळामध्ये 13 पैकी 9 सदस्य हे दहावी परीक्षा सुध्दा उत्तीर्ण झाले नव्हते. असे प्रकार होत असल्यामुळे यासंदर्भात खूप चर्चा झाली. शासनाकडे हे प्रकरण आल्यानंतर शासनाने त्याला स्थगिती दिली होती. आणि त्यानंतर आता या विधेयकाच्या माध्यमातून त्यांच्या अर्हतेमध्ये सुधारणा केली आहे. या विधेयकामध्ये दोन गोष्टी केल्या आहेत. एक म्हणजे त्यांनी ग्रॅज्युएट असणे सक्तीचे केले, बंधनकारक केले. तो सदस्य पदवीधारक असला पाहिजे. तसेच, काही प्रमाणात ज्यांच्योकरिता एस.एस.सी.डी.एड. ही अर्हता निश्चित केली होती. अशा सदस्यांसाठी आता ट्रेंड ग्रॅज्युएट असावेत, म्हणजे प्रशिक्षित पदवीधर असावेत ही अर्हता निश्चित केली आहे. यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, संबंधित व्यक्ती ही बॅचरल आफ एज्युकेशन असली पाहिजे. म्हणजे त्याची कन्सेप्ट नक्की काय आहे? हे स्पष्ट झाले पाहिजे. मी यासाठी विचारतो की, बॅचरल ऑफ एज्युकेशन झालेले पाहिजेत म्हणजे त्यांच्याकडे शिक्षण क्षेत्रातील पदवी असली पाहिजे. परंतु जे बी.पी.एड. किंवा बी.एड. (फिजिकल) उत्तीर्ण झालेले सुध्दा शिक्षण शास्त्रातील पदविकाधारक शिक्षक आहेत. म्हणजे शिक्षण शास्त्रातील पदवीधारक याचा अर्थ बॅचरल ऑफ एज्युकेशनमध्ये जर ते बी.पी.एड. झालेले असतील त्यांना आपण समकक्ष धरणार काय? बी.एड. (फिजिकल) झालेल्या शिक्षकांना समकक्ष धरणार काय? सभापती महोदय, या संदर्भात सांगावयाचे झाले तर काल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचा निकाल लागला. अनेक

YY 2/-

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. रामनाथ मोते...

शिक्षकांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केले होते, त्यावेळी त्यांची अर्हता निश्चित केली होती. त्यामध्ये ते ट्रेड ग्रॅज्युएट असले पाहिजेत असे म्हटले होते. आज अनेक शिक्षक हे बी.पी.एड. आणि बी.एड. (फिजिकल) आहेत, त्यांनी सुध्दा अर्ज केले होते. शासन निर्णयाप्रमाणे बी.एड. झालेले शिक्षक हे बी.पी.एड. समकक्ष ठरु शकतात. आणि बी.एड. (फिजिकल) झालेले शिक्षकसुध्दा समकक्ष ठरु शकतात. असा शासन निर्णय असतांना महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाच्या परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना अपात्र ठरविले गेले. आणि म्हणून त्यानंतर वाद होऊ शकतो तो होऊ नये म्हणून ही कन्सेप्ट क्लिअर होण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये बी.एड. याचा अर्थ बी.पी.एड. झालेले आणि बी.एड. (फिजिकल) झालेले सुध्दा चालतील काय ? यासंबधी खुलासा होणे आवश्यक आहे.

सभापती महोदय, शासन नियुक्त सदस्यांची असलेली दोनची संख्या वाढवून ती 5 करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एक शासकीय अधिकारी व 4 सदस्य हे शासनाकडून नियुक्त केले जातील. आतापर्यंत जसे होत आले आहे, तसे यानंतरही होत रहाणार आहे. आणि म्हणून या 4 सदस्यांची गुणवत्ता विचारात न घेता कोणत्या तरी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या ओळखीची व्यक्ती असेल...

उपसभापती : राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडे गुणवत्ता नसते काय?

श्री. रामनाथ मोते : सभापती महोदय, गुणवत्ता असते. परंतु सर्व नियम बाजूला ठेवून अशाप्रकारे कुणाच्या तरी एन्फ्लुअेंसमुळे हे शासकीय सदस्य त्याठिकाण्री येतात. तसेच, या शासकीय सदस्यांसाठी आपण आरक्षण ठेवले आहे, ही आनंदाची बाब आहे त्याचे मी समर्थन करतो. परंतु त्याचबरोबर मला याठिकाणी खेदाने असे सांगावेसे वाटते की,आपण एस.सी.एस.टी. साठी आरक्षण ठेवतांना महिलांसाठी कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण ठेवले नाही. 4 पैकी 2 सदस्य हे कोणत्याही पक्षाचे असले तरी, किंवा आपल्याला ज्याची नियुक्ती करावयाची असेल त्याची करा.

(यानंतर सौ. रणदिवे)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.रामनाथ मोते . . . .

पण या चार सदस्यांपैकी 2 सदस्य मग ते एस.सी.तील किंवा एस.टी.तील कोणताही सदस्य घ्यावा.

उपसभापती : 50 टक्क्यावर आणा.

श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदय, होय. आता शासनाने 33 टक्के आरक्षण दिलेले आहे.

उपसभापती : पण तेवढी ॲव्हीलीबिलीटी नाही.

श्री.रामनाथ मोते : सभापती महोदय, शिक्षण क्षेत्रामध्ये आहे. त्यामुळे महिलांना सुध्दा प्राधान्य देण्याची गरज आहे.मी यासाठी सांगू इच्छितो की, अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या आहेत. उल्हासनगर महापालिकेच्या शिक्षण मंडळावर अशा व्यक्तींची नेमणूक झाली आहे की, त्यांनी 25 वर्षे सुध्दा पूर्ण केलेली नव्हती. शासनाकडून नियुक्ती झाल्यानंतर मग शासनाला त्याबाबतीत माघार घ्यावी लागली. तेव्हा याबाबतीत ज्या काही फॉरमॅलिटीज् आहेत, जे काही टेक्नीकल मुद्दे आहेत जे शासनाने मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायद्यामध्ये ठरवून दिलेले आहे त्या सगळया गोष्टींची पडताळणी होण्याची आवश्यकता आहे. या शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून केवळ त्या शिक्षण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक शाळेच्या नियंत्रण केले जाते असे नाही. पण आता प्राथमिक शाळेपेक्षा खाजगी शाळा फार मोठया प्रमाणात आहेत. उल्हासनगर महापालिकेच्या ठिकाणी 115 खाजगी शाळा आहे आणि 30 शाळा महापालिकेच्या आहेत. म्हणून या खाजगी शाळांचे जे संस्था चालक आहेत, त्यांचे प्रतिनिधी सुध्दा शासन नियुक्त सदस्यांमध्ये घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनुदानाच्या बाबतीत सुध्दा प्रत्येक शिक्षण मंडळाच्या बाबतीत भेदभाव केला जात आहे. मालेगाव येथे 80 टक्के अनुदान देते. भिवंडीमध्ये अल्पसंख्यांकांची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. गोरगरीब, अल्पसंख्यांकांची मुले या शाळेमध्ये शिकतात. आपण मालेगावचा निकष भिवंडीला लागू करणार आहात काय ? तसेच त्या शिक्षण मंडळांना सुध्दा 80 टक्के अनुदान देणार आहात काय? असा माझा प्रश्न आहे. सभापती महोदय, सर्वात महत्वाची अडचण अशी आहे की, नगरपालिका शिक्षण मंडळांना दिले जाणारे जे अनुदान आहे. ते कधीही वेळेवर दिले जात नाही आणि त्यामुळे या शिक्षण मंडळातील शिक्षकांचे कधीही वेळेवर पगार होत नाही. म्हणून मी या विधेयकाच्या माध्यमातून विनंती करतो की, शिक्षण मंडळाचे वेतन अनुदान लवकरात लवकर मिळण्याची आवश्यकता आहे . धन्यवाद.

. . . .2 झेड-2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

उपसभापती : आता सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी आपले भाषण थोडक्यात करावे.

श्री.कपिल पाटील (मुंबई विभाग शिक्षक) : सभापती महोदय,मी थोडक्यात बोलणार आहे. पण विधयेकावर बोलण्यासाठी वेळेचे बंधन नसते याची फक्त जाणीव करुन देतो.

काही सन्माननीय सदस्य (खाली बसून) : फक्त भावना मांडाव्यात.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, भावना नाही, पण मी थोडक्यात बोलेन.त्यामुळे यावर बंधन घालता येणार नाही असे मी नम्रपणे सांगतो.

उपसभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील, मी तुम्हाला नम्रपणे सांगतो की, तुम्हाला जेवढे बोलावयाचे आहे, तेवढे बोलावे.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, माननीय शिक्षण राज्यमंत्री श्रीमती फौजिया खान यांनी याठिकाणी सन 2009 चे वि.स.वि.क्रमांक 68 चर्चेसाठी मांडलेले आहे, त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. मी शिक्षकांचे प्रतिनिधीत्व करतो. पण आताच आदरणीय शिक्षक आमदार श्री.रामनाथ मोतेसर यांनी दोन सूचना केलेल्या आहेत, त्या संदर्भात एक सूचना वगळता माझी मतभिन्नता व्यक्त करणे आवश्यक आहे आणि ती या विधेयकाच्या बाबतीत आहे, त्याला माझा विरोध आहे म्हणून मी उभा आहे.

सभापती महोदय, याठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण असले पाहिजे, परंतु आपण त्याची तरतूद केलेली नाही. किमान पुढच्या वेळेस तरी करावी. एका बाजूला 1/3 सदस्यांना लोकसभेमध्ये स्थान देण्याच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय होतो आणि तुम्ही जेव्हा सुधारणा विधेयक घेऊन येता, तेव्हा एक महिला राज्यमंत्री असताना त्या ही बाब विसरतात याचा मला खेद होत आहे.

एक सन्माननीय सदस्य (खाली बसून) : शिक्षण क्षेत्रात महिला राज आहे.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, महिलांचे राज्य अजिबात नाही. कारण महिलांचे शिक्षणाच्या बाबतीतील गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे. ते एवढे कमी आहे की, डॉ.दीपक सावंत साहेबांनी सांगितले म्हणून सांगतो की, एस.एस.सी.पर्यंत 47 मुली शिक्षण सोडून जातात आणि ज्या 15 मुले पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी पुढे जातात. त्यामध्ये फक्त 3-4 मुली पुढील शिक्षण घेऊ शकतात. इतक्या मोठया प्रमाणात महिलांची गळती असताना, तुम्ही यामध्ये स्त्रियांना स्थान देऊ नये याचे अधिक वैष्यम्य वाटते.नगरपालिकेचे जे सदस्य शिक्षण मंडळावर निवडून द्यावयाचे आहेत.

यानंतर कु.थोरात . . . .

अप्रकाशित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

SMT/ MMP/ KGS/ प्रथम सौ. रणदिवे... 16:05

श्री. कपिल पाटील...

त्यांची पात्रता एकदम मॅट्रिकोत्तर केलेली आहे त्याला माझा विरोध आहे. शासकीय प्रतिनिधी जे नेमण्यात येणार आहेत ते पदव्यूत्तर नेमा तो शासनाचा अधिकार आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. मोते यांनी याठिकाणी उल्लेख केला की, शासन ज्यांना नेमत होते त्यांची कोणतीही पात्रता पहात नव्हते फक्त राजकीय पक्षांनी नेमले आहेत काय? एवढेच पहात होते. उल्हानगरला गेल्या वेळेला कोणतेही शिक्षण नसलेली वयात न बसणारी लहान मुले पाठविली. 18 वर्षापेक्षा लहान मुलगा पाठविला असेल तर तो सदस्य कसा काय होईल? म्हणून तो आदेशही मागे घ्यावा लागला इतकी लाजीरवाणी घटना घडलेली आहे. पण मुद्दा असा आहे की, नगरपालिकेतील सदस्य आपले प्रतिनिधी तेथे पाठविणार आहेत त्यांना शासनाने शिक्षणाची अट घालणे याला माझा विरोध आहे. ती अट अजिबात असता काम नये. कारण या राज्याचे नेतृत्व एका चौथी पास असलेल्या माणसाने केले होते आणि अत्यंत सक्षमपणे केले होते.पदव्यूत्तर शिक्षण घेतले म्हणजे राज्य चांगले चालविता येते असे मानण्याचे कारण नाही. पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलेले लोक काय दिवे लावतात हे आपण भ्रष्टाचाराच्या कथा ऐकल्यानंतर पहातो. ज्याचे किमान लोक शिक्षण झालेले आहे पण इयत्ता सातवी नंतर शाळेचे तोंड पाहिलेले नाही अशी माणसे अत्यंत चांगले निर्णय घेत असताना आपण पाहिलेले आहे. सभापती महोदय, आपण त्याचे साक्षीदार आहात.

उपसभापती : मी साक्षीदाराच नाही तर आपल्या मताशी सहमत आहे.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, माननीय मंत्रिमहोदयांना हे मागे घेण्यास आपण सांगावे. आज संध्याकाळी माननीय पंतप्रधान देशाला उद्देशून भाषण करणार आहेत.(अडथळा) माननीय पंतप्रधानांचे भाषण झालेले आहे किंवा माननीय पंतप्रधानांनी जो हक्क प्रदान केलेला आहे तो हक्क आज मिळणार आहे. सभपती महोदय, कालपर्यंत घटनेने 14 वर्षापर्यंतच्य मुलांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण दिले गेले पाहिजे अशा प्रकारचे बंधन होते. याची अंमलबजावणी ना राज्य सरकारने कधी केली ना केंद्र शासनाने कधी केली. येथून पुढे शासनाने ती जबाबदारी घेतलेली आहे ती पण इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतलेली आहे त्यामुळे फार मोठी शेखी मिरवण्याचे कारण नाही. तरी देखील सभापती महोदय, मी त्याचे कौतुक करतो कारण कालपर्यंत तेही होत नव्हते. यामध्ये इयत्ता आठवीपर्यंतची अट असती तर मी ती मान्य केली असती. कारण आजपासून शासन याला सुरुवात करीत आहे त्यामुळे यापुढे या शासनाला बोलण्याचा अधिकार

...2.

श्री. कपिल पाटील....

आहे. पण ज्या दिवशी तुम्ही शिक्षणाचा अधिकार इयत्ता दहावी, बारावी पर्यंत किमान शिक्षण होईल त्या दिवशी शासन हे बोलू शकेल. कारण महात्मा गांधीनी "नई तालीममध्ये"सांगितले होते. पण गांधीजींचे नाव घेणारे ते विसरलेले आहेत कारण ते दुसऱ्या गांधीजींचे नाव घेत आहेत. पूर्व विद्यापीठीय शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे आणि त्याची जाबाबदारी राज्य आणि केंद्र शासनाने घेतली पाहिजे असा महात्मा गांधींनी आग्रह धरला होता. हंटर कमिशनपुढे महात्मा फुलेंनी हा अग्रह धरला होता की, मॅट्रीकपर्यंतचे शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत द्या. प्राथमिक शिक्षण द्या. हे दोन्ही आग्रह आपण विसरलो. आपण गांधींजीचे नाव घेता त्यांनी "नई तालिममध्ये" सांगितले होते तेही आपण विसरुन गेलात. पूर्व विद्यापीठीय शिक्षण म्हणजे इयत्ता बारावी पर्यंतचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे ती शासनाने पाळलेली नाही. धड प्राथमिक शिक्षण दिले नाही. आज स्वातंत्र्यांच्या 50 वर्षानंतर 60 वर्षानंतर ज्यावेळेला काही करायला उभे आहोत त्यावेळेला या देशाचे माननीय पंतप्रधान फक्त इयत्ता आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाची हमी देत आहेत ही सगळयात दुःखाची आणि खेदाची बाब आहे. एका बाजूला मी त्याचेही स्वागत करतो पण ते मुळात अत्यंत अपुरे आहे. जे गांधीजींनी स्वप्न पाहिले जे महात्मा फुलेंनी स्वप्न पाहिले, जे महर्षी कर्वेनी स्वप्न पाहिले ज्यासाठी सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख झटल्या तेथपर्यंत सुध्दा आपण स्वातंत्र्यांच्या 60 वर्षानंतर पोहचलेलो नाही आणि आता मात्र कमी शिकलेले लोक देशाची वाट लावतात, शिक्षणाची वाट लावत आहेत अशा पध्दतीचा गृह हे शासन करुन घेत आहे, याचे मला जास्त दुःख वाटते. सभापती महोदय, आपण आज फोटो पाहिला असेल. शिक्षणमंडळाचे लोक कसे नाचत होते. ते चांगले शिकलेले लोक आहेत. लावणीवर नाचतात याबद्दल माझा काही आक्षेप नाही पण ते नाचत होते आणि नाचत असलेला फोटो आपण पाहिलेला आहे. (अडथळा) बहुतेक सर्वच वर्तमानपत्रात तो छापून आलेला आहे बहुतेक प्रहार या वर्तमानपत्रामध्ये छापून आलेला आहे. सभापती महोदय, लावणीवर नाचल्यानेही काही बिघडत नाही पण मोठे मोठे शिकलेले लोक सुध्दा भानगडी करतात. शासनाने येथे लगेच शिक्षणाची अट घातलेली आहे म्हणून माझा याला कडवट विरोध आहे. कृपाकरुन आपण यासंबंधीची अट मागे घ्यावी. मला यासंदर्भात दुरुस्ती देता आली नाही, ही माझी चूक आहे परंतु आपण ती मागे घ्यावी. कारण मी दुरुस्ती सुचविली तरी शासन ती

..3..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

SMT/ MMP/ KGS/ 16:05

श्री. कपील पाटील...

स्वीकारणार नाही म्हणून मी या शासनालाच विनंती करतो की, इयत्ता मॅट्रिकपर्यंतची अट काढण्यात यावी. ती अट घालण्याचा अधिकार या शासनाला तेव्हाच मिळेल ज्यावेळेला मॅट्रिकपर्यंतच्या शिक्षणाची व्यवस्था हे शासन या राज्यामध्ये करेल आणि या राज्यामध्ये ती व्यवस्था केलेली नाही कारण विनाअनुदानित शाळा अजूनही चालू आहेत "कायम" हा शब्द काढल्याची नागपूरच्या अधिवेशनात या शासनाने फक्त घोषणा केलेली आहे. पण प्रत्याक्षात अनुदान दिलेले नाही. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना फी देण्यात येत नाही. म्हणजे येथील जो गोरगरीब वर्ग आहे, जो आदिवासी आहे, दलित आहे, पददलित आहे. मागासवर्गीय आहे त्याला शिक्षणाची कोणतीच व्यवस्था करण्यात येत नाही आणि येथे मॅट्रिक शिकलेला माणूस आला पाहिजे असे सांगत असाल तर तो कसा येईल.? शिक्षण मंडळामध्ये गरीबातील गरीब माणूस तेथे पोहचला पाहिजे तर तो सांगने. सभापती महोदय, बिहारमध्ये एक दगड फोडणारी स्त्री खासदार झाली त्यानंतर तेथील अनेक प्रश्न मार्गी लागले. कारण न शिकलेला माणूस जेव्हा तेथे जाईल तेव्हा तो आपल्या पिढीसाठी जास्त कष्ट घेतो.

यानंतर श्री. बरवड...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. कपिल पाटील .....

त्यामुळे आपण जी अट घालत आहात ती अत्यंत लोकशाहीविरोधी आहे. कारण या देशामध्ये लोकशाहीच्या मार्गाने ज्यांना कारभार चालवावयाचा आहे त्या कारभार चालविणाऱ्याच्या बाबतीत कोणतीही अट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ठेवलेली नाही. आपणास ती अट घालण्यास हरकत नाही पण जेव्हा आपण त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था कराल तेव्हाच आपणाला ती अट घालता येईल. जोवर आपण ती व्यवस्था करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला कोणत्याही पध्दतीची अट घालता येणार नाही. कारण या देशातील गरिबातील गरीब माणसाला, न शिकलेल्या माणसाला सुध्दा मताचा एक अधिकार आहे आणि टाटा-बिर्लाला सुध्दा मताचा एक अधिकार आहे. माननीय मंत्रिमहोदया प्रा. फौजिया खान यांना सुध्दा मताचा एक अधिकार आहे आणि कपिल पाटील यांना सुध्दा मताचा एक अधिकार आहे. दोघांच्या मतांमध्ये शिक्षणाची पात्रता काय आहे यावरुन काहीही फरक केलेला नाही. जर ही गोष्ट खरी असेल तर मग आपण अशा पध्दतीची अट आणून त्या गरीब वर्गाची थट्टा का मांडता ? एका बाजूला शिक्षण देत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला या राज्याच्या शिक्षणाचे वाटोळे केलेले आहे. जो अर्थसंकल्प मांडला त्यासंदर्भात आमचे मित्र अर्थमंत्री श्री. सुनील तटकरे यांनी जोरदार भाषण करुन उत्तर दिले. राज्याचे 6 लाख 92 हजार कोटी रुपयांचे जे स्थूल उत्पन्न आहे त्यामध्ये शिक्षणासाठी फक्त 3.1 टक्के तरतूद केलेली आहे. या देशाचे पहिले शिक्षण मंत्री श्री. मौलाना आझाद यांनी असे सांगितले होते की, राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 6 टक्के तरतूद शिक्षणासाठी असली पाहिजे. आपण 4-5 टक्के सुध्दा तरतूद करीत नाही. आपण 4-5 टक्के तरतूद केली तरी या राज्यातील शिक्षणाचे प्रश्न मिटतील. तेही आपण करीत नाही. मला माहीत आहे की, माननीय मंत्रिमहोदया प्रा. फौजिया खान या श्री. मौलाना आझाद यांच्या अनुयाची आहेत आणि त्यांच्या विचाराने चालणाऱ्या आहेत. त्यांच्या विचाराने चालत असताना आपण शिक्षणासाठी तरतूद करीत नाही. काही सन्माननीय सदस्य असे विचारत आहेत की, या विधेयकाला माझे समर्थन आहे काय ? माझे विधेयकाला समर्थन नाही. माझा विधेयकाला विरोध आहे. मी विरोध करण्यासाठी उभा आहे. माझे समर्थन असते तर हात वर करुन खाली बसलो असतो. विरोध करण्यासाठी बोलावे लागते. माननीय मंत्रिमहोदयांनी या ठिकाणी अतिशय

...2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. कपिल पाटील ....

चुकीचा पायंडा पाडलेला आहे असे मला वाटते. म्हणून माझी शासनाला विनंती आहे. एका बाजूला आपण तरतूद करणार नाही, शिक्षणाची सोय करणार नाही, ती सोय नाकारणार, विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी मोकळ्या राहतील, समान राहतील या पध्दतीची कोणतीही व्यवस्था करणार नाही आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र आपण इतके शिक्षण प्राप्त केले असेल तरच शिक्षण मंडळामध्ये येता येईल अशी अट घालत आहात. माझे असे म्हणणे आहे की, गरिबातील गरीब, अशिक्षित माणूस ज्या दिवशी त्या ठिकाणी येईल त्या दिवशी तो माझ्या पोरांसाठी चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे यादृष्टीने निर्णय घेईल. कारण मोठी माणसे कधीही गरिबांकडे बघत नाहीत. ज्या वर्गातून आपण आणि आम्ही सर्वजण येतो त्या वर्गातील माणसे गरिगांकडे कधीही बघत नाही हा माझा आजवरचा अनुभव आहे आणि त्या वर्गाच्या हातामध्ये जर आपण जर ही सूत्रे देऊ पाहात असाल तर त्याला माझा कडवट विरोध आहे. कृपाकरुन श्रीमंतांच्या हातात, धनिकांच्या हातात, उच्चभ्रूंच्या हातात, उच्चशिक्षितांच्या हातात या राज्याच्या स्थानिक स्वराज्याचे शिक्षण आपण देऊ नका अशी माझी कळकळीची विनंती आहे.

डॉ. दीपक सावंत : सभापती महोदय, माझा हरकतीचा मुद्दा आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील बोलताना असे म्हणाले की, उच्चशिक्षितांच्या हातामध्ये शिक्षण देऊ नका. ते कामकाजातून काढून टाकावे.

श्री. कपिल पाटील : मी तथाकथित असे म्हणालो.

डॉ. दीपक सावंत : आपण तथाकथित म्हणाला नाही. आपण उच्चशिक्षित असा शब्द वापरलेला आहे.

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, अशी मी दुरुस्ती करतो. केवळ उच्चशिक्षितांच्या हातात असे मला म्हणावयाचे आहे. मी सन्माननीय सदस्य डॉ. दीपक सावंत यांना सांगू इच्छितो की, आपण डॉक्टर झालात पण अजून खेड्यापाड्यात डॉक्टर्स नाहीत. त्याला शासन जबाबदार आहे. त्यामुळे आपण शासनाला कृपा करुन मदत करु नका. आपण जव्हार मोखाडा येथे गरीब आदिवासींसाठी जाता हे मला माहीत आहे. म्हणून कृपाकरुन आपण शासनाला मदत करु नका.

..3...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. कपिल पाटील .....

कारण आपण बहुजन वर्गातून आला आहात. सभापती महोदय, मी आठवण करुन देतो की, हंटर कमिशनपुढे महात्मा फुले यांनी जेव्हा निवेदन केले त्यावेळी त्यांनी दोन मागण्या केल्या होत्या. सक्तीच्या मोफत शिक्षणाच्या बरोबरीने बहुजन वर्गातून शिक्षक निर्माण झाला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मागणीला अर्थ होता. जोपर्यंत बहुजन वर्गातील शिक्षक मिळणार नाही तोपर्यंत बहुजन वर्गाचे शिक्षण होणार नाही. आज त्यांच्यापर्यंत जे शिक्षण पोहोचले आहे ते बहुजन वर्गातील शिक्षक उभे राहिल्यामुळे पोहोचले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी जर अशी अट घातली असती की वरचाच माणूस येऊ द्या तर कधीही त्यांच्यापर्यंत शिक्षण पोहोचले नसते. म्हणून उफराटी तरतूद आपण करु पाहात आहात. ही तरतूद कै. वसंतदादा पाटील यांचा अपमान करणारी आहे. ज्यांनी या महाराष्ट्राला खूप काही दिले, अत्यंत कुशाग्र बुध्दिमत्ता असलेले, मोठ्या प्रकांडपंडिताला हरवू शकणारे अशा ताकदीचे ते नेते होते. मी कॅ. वसंतदादा पाटील यांचे एकच उदाहरण देतो. ते एकदा दादरला भाषण करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी तुरुंगातील अनुभव सांगतले. आपल्यातील अनेकजणांनी मार्क्सचा कॅपिटल ग्रंथ वाचला नसेल पण त्यांनी कॅपिटल ग्रंथ पूर्ण वाचलेला होता, त्याचे पारायण केले होते. इतकी विद्वान मंडळी होती

यानंतर श्री. खंदारे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.कपिल पाटील....

केवळ तुमचे लौकिक शिक्षण किंवा त्या अर्थाचे शिक्षण त्यांच्याकडे नाही म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री व्हायला नाकारले असते तर पाटाच्या पाण्याच्या योजना आल्या नसत्या, ग्रामीण विकासाच्या योजना महाराष्ट्रात राबविल्या गेल्या नसत्या. कारण अनेक उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित तथाकथित अनेक मुख्यमंत्री होऊन गेले. त्यांनी काय दिवे लावले ते आपण पाहतो. अनेक राज्यांबाबत आपण बोलतो. पण या राज्याला एक वेगळी परंपरा आहे. या राज्यातील प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी गरीबांचा विचार केलेला आहे. या विधेयकातील एका तरतुदीला माझा विरोध आहे. या तरतुदीच्या संदर्भात सन्माननीय सदस्य श्री.रामनाथ मोते, सन्माननीय सदस्य डॉ.दीपक सावंत यांच्या भावना वेगळया आहेत. त्या भावना मला समजतात. पण अशा पध्दतीने गरीबांचा हक्क काढून घेणार असाल, त्याच्या तोंडचा घास काढून घेणार असाल, ज्याला तो अधिकार कधीही दिलेला नाही. तो अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार या सभागृहालाही नाही. कारण जनता सार्वभौम आहे, त्या जनतेचे आपण प्रतिनिधीत्व करीत असतो. म्हणून मी जबाबदारीने सांगतो की, या सभागृहालाही तो अधिकार नाही. जोवर त्यांना तो अधिकार देत नाही तोवर त्यांच्यावर अटी घालण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. शासन नियुक्त सदस्य मी मान्य करतो, परंतु निवडून देण्याच्या संदर्भात किमान हा बदल शासनाला करावा लागेल. एवढे बोलून मी या विधेयकाला विरोध करतो आणि थांबतो, धन्यवाद.

प्रश्न मतास टाकून संमत झाला.

उपसभापती : विधेयक विचारात घेण्यात आले आहे. आता विधेयक खंडश: विचारात घेण्यात येईल.

खंड 2 विधेयकाचे भाग झाले.

खंड 1, संपूर्ण शीर्षक व हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले.

प्रा.फौजिया खान : सभापती महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2009 चे वि.स.वि.क्रमांक 68 संमत करण्यात यावे, असा प्रस्ताव मांडते.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, या विधेयकाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेला सन्माननीय मंत्रिमहोदयांनी उत्तर दिले पाहिजे.

2...

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

उपसभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांच्या प्रश्नांना मंत्री महोदयांनी उत्तर द्यावे.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, अशा पध्दतीने कामकाज चालणार नाही.

उपसभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांना मी सांगू इच्छितो की, मी ज्याठिकाणी पॉज घ्यावयाचा असतो त्याठिकाणी पॉज घेतो. त्यावेळी ज्या सन्माननीय सदस्यांना बोलावयाचे असते ते बोलू शकतात. मंत्री महोदयांनी त्यांचे सायटेशन वाचल्यानंतर मी थांबलो होतो. त्यानंतर मी पुढे गेल्यावर आपण बोलला आहात. तरी मी आपल्या विनंतीला मान देतो. मंत्री महोदयांनी सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे. मी पॉज घेतला होता. मी प्रत्येकाला असे सांगू शकत नाही की, तुम्ही उठावे आणि तुम्हाला काय बोलावयाचे आहे ते बोलावे. असे करता येत नाही.

प्रा.फौजिया खान : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी दोन मुद्यांचा उल्लेख केला आहे. महिला सदस्यांचा समावेश व्हावा ही त्यांची सूचना शासनाला मान्य आहे. त्यांची दुसरी सूचना अशी होती की, नगरपालिकेकडून निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी शिक्षणाची अट घालू नये. मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छिते की, शिक्षणासोबतच राईट टू एज्यूकेशन हा कायदा शासनाने पास केला आहे. त्याचबरोबर दर्जेदार शिक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातूनही आपण विचार केला पाहिजे. सध्या निवडणुकीसाठी जे उमेदवार पात्र आहेत त्यात पदवीधर सुध्दा आहेत. पदवीधारक उमेदवार सध्या उपलब्ध होत आहेत. पूर्वी पदवीधर उमेदवार गावोगावी उपलब्ध होत नव्हते.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, माझा तो मुद्दा नाही. शासनाने त्यांना आतापर्यंत सार्वत्रिक अधिकार दिलेला आहे काय, आठवीपर्यंत अधिकार आता दिलेला आहे. तेव्हा आठवीपर्यंत अट टाकावी. जो अधिकार दिला आहे तेथपर्यंत शासनाला अट टाकता येईल.

प्रा.फौजिया खान : सभापती महोदय, मला सांगावयाचे आहे की, शासनाने कोणालाही वंचित ठेवलेले नाही. जेव्हा आपण दर्जेदार शिक्षणाकडे जातो...

3....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यासाठी निवडणुका होतात. या निवडणुकांसाठी काही मतदार संघ राखीव असतात. काही वेळेला त्या मतदार संघासाठी आपल्याला उमेदवार सुध्दा मिळत नाहीत. काही वेळा तर सही सुध्दा न येणा-या उमेदवारांना उभे करावे लागते. एकदा का तो उमेदवार निवडून आला तर त्याला हक्क प्राप्त होतो. शिक्षणाच्या अटीमुळे त्याला त्या हक्कापासून वंचित करु नका. असा हा विषय आहे. त्यानंतर तो उमेदवार शिकला तर आनंद आहे.

यानंतर श्री.शिगम.....

अस्धारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(श्री. दिवाकर रावते...

त्याला मिळालेला हक्क अशा पध्दतीने जात असेल तर ते योग्य नाही. हे राखीव मतदारसंघ आणि त्यामध्ये ही अशी परिस्थिती. दलित, पददलित आणि सगळया बाबतीत मागासलेले आहेत त्यांना लोकशाहीमध्ये जी संधी मिळालेली आहे, त्यांना जे हक्क प्राप्त झालेले आहेत, त्या हक्कापासून त्यांना तुम्ही वंचित करु शकणार नाही.

प्रा. फौजिया खान : सभापती महोदय, हे शिक्षण मंडळ आहे. शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि शाळांचे व्यवस्थापन बघण्याचे त्यांचे काम आहे. यामध्ये आपण जर शैक्षणिक अर्हतेची अट ठेवली तर त्याबाबतीत काय हरकत आहे ?

श्री. कपिल पाटील : ज्या जनतेकडून आम्ही निवडून येतो त्यांचा अपमान करण्याचा अधिकार तुम्हास नाही.

डॉ. दीपक सावंत : जे शिक्षित असतील त्यांना पहिल्यांदा प्राधान्य दिले जाईल आणि जे शिक्षित नसतील त्यांना त्यानंतर प्राधान्य दिले जाईल असा पर्याय ठेवण्यात येणार आहे काय ?

(दोन्ही बाजूचे काही सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.)

श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील यांनी जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला तो त्यांच्या दृष्टीने बरोबर असेल. कालानुरुप शैक्षणिक पात्रता वाढत गेली. उदा.पूर्वी शिक्षक हे मॅट्रीक झालेले होते. आता शिक्षक पदासाठी डी.एड. आणि बी.एड.झ ालेल्या उमेदवारांना घेतले जाते. जस जशी आवश्यकता वाटत गेली त्याप्रमाणे परिवर्तन करण्यात आले. आता 60 वर्षानंतर शिक्षण मंडळावर येणारा सदस्य हा पदवीधर असायला पाहिजे असा नियम केला तर त्यामध्ये चुकीचे काय आहे ?

श्री. दिवाकर रावते : सन्माननीय सदस्य श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी यांनी जो मुद्दा मांडाला त्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. सन्माननीय सदस्य श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी यांचे मी स्वागत करतो. ते रोखठोक आणि स्पष्ट वक्ते आहेत, त्यांना समाजाची जाण आणि भान आहे. सभापती महोदय, हा अशिक्षित पणा काढायला किती वर्षे लागली ? स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे झाली. आज पुण्यामध्ये सर्वांकरिता अनिवार्य शिक्षण या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होते. 60 वर्षानंतर या सरकारला

..2..

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(श्री. दिवाकर रावते....)

जाणीव झाली, मी अक्कल आली असे म्हणणार नाही. 60 वर्षे या देशामध्ये राज्यकर्ते राज्य करीत आहेत. ज्यांनी 5 पिढ्याचे आयुष्य बरबाद केले ते आता भविष्यात शिक्षण पाहिजे अशा प्रकारचे उद्घाटन पुण्यात येऊन करीत आहेत. मी माननीय पंतप्रधान आणि श्री. कपिल सिब्बल यांचे स्वागत करावे असे म्हणतोय. श्री. कपिल सिब्बल यांनी एवढया उशिरा हा प्रस्ताव आणला त्याबद्दल त्याचे स्वागत करु शकत नाही आणि प्रस्ताव भावी पिढीकरिता आहे म्हणून त्याचा धिक्कारही करता येत नाही. पण ही लांच्छनास्पद गोष्ट आहे. मधली काही वर्षे सोडली तर या देशामध्ये तुम्ही सतत राज्य करीत आहात. या देशात वनामध्ये राहणा-या, जंगलामध्ये राहाणा-या, डोंगरकपा-यात राहाणा-या आणि ज्यांना शिकायला शाळा मिळत नाही अशा लोकांना शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त होत नव्हता. तो अधिकार देण्यासाठी तुम्हाला 60 वर्षे लागली. या 60 वर्षाचे हे पाप या काँग्रेस सरकारचे आहे. जो शिकलेला असेल तोच या मंडळावर येईल असा कायदा आपण करीत असाल तर मग निवडणुक लढविण्यासंबंधीच्या कायद्यामध्ये देखील दुरुस्ती करावी. किमान एवढे शिक्षण असल्या शिवाय निवडणुक लढविता येणार नाही असा कायदा करावा. परंतु अशा प्रकारचा कायदा नाही, कोठेही अशी तरतूद नाही. यादेशाच्या कोणत्याही नागरिकाला अवाक्षरही येत नसले तरी मुक्या, बहि-या आणि आंधळयाला सुध्दा निवडणूक लढविता येते. ज्यांना वाचता येत नव्हते, सही करता येत नव्हते असे लोक या विधिमंडळाचे सदस्य झाले. मी कशावर सही करतोय हे कळत नव्हते असे लोक सदस्य झाले. तेव्हा अशा प्रकारे लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून येणा-या सदस्याला जे अधिकार आहेत ते अधिकार हिरावून घेणे योग्य नाही. मी अत्यंत खेदाने हे नमूद करतो की, या देशामध्ये प्रत्येकाला घटनेने शिक्षणाचा अधिकार दिलेला आहे. तो अधिकार द्यायला ज्या सरकारला 60 वर्षे लागली, त्या बद्दल चिंता व्यक्त करतो आणि हे धोरण न राबविणा-या सरकारचा जाहीररित्या निषेध करतो.

...नंतर श्री. भोगले....

असुधारित प्रत/प्रसिध्दीसाठी नाही

ॲड.गुरुनाथ कुळकर्णी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी सांगितले की, राईट टू एज्यूकेशन म्हणजे शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार दिलेला आहे तो डायरेक्टिव्ह ऑफ प्रिन्सिपल्समध्ये आहे. फक्त घटनेने तो देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

डॉ.दीपक सावंत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकर रावते यांनी जे सांगितले त्यापुढे जाऊन मी सांगू इच्छितो की, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार पदवीधर असावा असा दंडक नाही. अशिक्षित असला तरी चालतो. मग तुम्हाला याठिकाणी पदवीधर कशाला हवा आहे?

उपसभापती : सभागृहाची बैठक दुपारी 4.40 पर्यंत स्थगित करण्यात येत आहे.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 4.26 ते 4.40 पर्यंत स्थगित झाली.)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(स्थगिती नंतर)

(सभापतीस्थानी माननीय उपसभापती)

श्री. कपिल पाटील : सभापती महोदय, मघाशी ज्यावेळेस मी उत्तराचा आग्रह धरीत होतो त्यावेळी माननीय मंत्री महोदय श्रीमती फौजिया खान यांनी जे उद्गार काढले ते आक्षेपार्ह होते. हा प्रश्न शिक्षणाचा आहे असे उद्गार त्यांनी काढावे याचे जास्त वैषम्य वाटते हे मला आपल्या निदर्शनास आणून द्यावयाचे आहे. त्यामुळे हा केवळ सभागृहातील सदस्यांचाच अपमान नाही तर राज्यातील कोट्वधी अशिक्षीत जनतेचाही अपमान आहे. त्यानंतर आमचे ज्येष्ठ घटना तज्ज्ञ असलेले सन्माननीय सदस्य श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी त्यांनी असा आग्रह धरावा हे त्याहून जास्त दु:खदायक आहे. घटना समितीमध्ये याबद्दल.....अडथळा.....मी आपल्याकडे मार्गदर्शन मागत नाही तर आपण जे मार्गदर्शन केले त्याबद्दल बोलतो. आपण जो आक्षेप नोंदविला तोही आक्षेप यासाठीच आहे की, घटना समितीने सुध्दा शिक्षणाचा अधिकार कोणाला द्यायचा यावरुन वाद झाला होता. तो अधिकार शिक्षीतांना द्यायचा असे एका मोठ्या वर्गाचे मत होते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरु तसेच डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचे मत असे होते की सर्वांना समान अधिकार राहील तसेच अंगठे बहाद्दराला सुध्दा तो तसाच समान राहील. या सभागृहात आपण राजकीय समितीसंबंधीचा निर्णय घेत आहोत. नोकरीसंबंधीचे निर्णय घेत नाही की कोणाला इंजिनिअर करावे वगैरे, हा निर्णय घेत नाही हाच माझा आक्षेप आहे. अशा प्रकारे जेथे राजकीय निर्णय प्रक्रिया ठरते तो निर्णय घेण्यासाठी आपण येथे शिक्षणाची अट घालत, जे शिक्षण आपण आजपर्यंत दिलेलेच नाही. म्हणून अशी व्यवस्था आपण जोपर्यंत निर्माण करीत नाही तोवर अशी अट घालण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. तुम्ही सर्वांना समान हक्क द्या, त्यानंतर अशी अट घाला आणि जोपर्यंत समान शिक्षण द्यालय तोपर्यंत अशी अट घालण्याचा अधिकार आपल्याला आहे. आज रोजी फक्त आठवीपर्यंत शिक्षणाचा अधिकार आहे, जो कायद्यानेच दिलेला आहे. तसेच सन्माननीय सदस्य श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी यांनी डायरेक्टीव्हजमध्ये पूर्वीपासूनच तसा अधिकार दिलेला होता असे सांगितले. त्यासंसबंधी स्पेसिफिकली केंद्राने राज्यावर आठवीपर्यंतच्या शिक्षणाच्या संदर्भातली 55+45 ची जबाबदारी टाकलेली आहे ती जबाबदारी तुम्ही आज घेतलेली आहे. आणि येथून पुढे तुम्हाला फक्त आठवीपर्यंतच बंधन घालता येईल आणि असे आठवीपर्यंत

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. कपिल पाटील.....

शिक्षण मिळाल्यानंतर आणखी 8 वर्षापर्यंत थांबावे लागेल. पुन्हा शिक्षणाचा प्रश्न ....तुम्हाला बोलता कसे येईल, येथे कसे राहता येईल असे प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजेच ज्यांना राजकीय निर्णय घेण्याची विवेक क्षमता आहे, ज्यांचे लोकशिक्षण झालेले आहे अशा सर्वांचा आपण अपमान करीत आहात. हा अपमान केवळ आमचाच नव्हे तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आणि भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा, ज्यांनी आम्हाला हा अधिकार दिलेला आहे त्या सर्वांचाच हा अपमान आहे. याबाबत माझा आक्षेप नोंदवून घ्यावा व तोपर्यंत तुर्तास हे विधेयक थांबवावे आणि त्यात बदल करुन पुन्हा ते मांडण्यात यावे....

यानंतर श्री. जुन्नरे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्रीमती फौजिया खान : सभापती महोदय, आम्ही कोणाचा अपमान करतो आहे असे म्हणणे बरोबर नाही त्यामुळे सन्माननीय सदस्य श्री. कपिल पाटील यांनी उच्चारलेले शब्द कामकाजातून काढून टाकावे अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. हा प्रश्न नागरी भागाचा आहे. त्यांनी शिक्षण घेतले नसले तरी आज लाखो लोक शिक्षीत आहे. शिक्षीत लोक उपलब्ध नाही अशी आता परिस्थिती राहिलेली नाही. आपल्याला पॉझीटीव्ह पाऊल उचलावयाचे आहे, आपण एक क्रांतिकारी कायदा आपण आणीत आहोत. ज्याला दोन मुले असतील त्यांनाच आता निवडणुकीमध्ये उभे राहता येणार आहे.निवडणुकीमध्ये आपल्याला उभे राहावयाचे आहे म्हणून लोक आता फॅमिली प्लॅनिंग करु लागले आहेत. If we want change we have to go ahead. मी आपल्याला डार्वीनचे एक वाक्य वाचून दाखवते ते असे आहे की, "It is not the strongest in the society that survives the one most responsive to change" आपण जेंचला रिस्पॉन्सीव्ह असले पाहिजे. हा पॉझीटीव्ह चेंज आहे. पॉझीटीव्ह चेंजमुळे आपला शैक्षणिक दर्जा वाढणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करावे अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करते.

(विरोधी पक्षाचे काही सन्माननीय सदस्य उभे राहून बोलण्याचा प्रयत्न करीत असतात.)

श्री.. गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय, या ठिकाणी जे विधेयक आलेले आहे ते घटनेनुसारच आलेले आहे.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, घटनेची पायमल्ली करुन आपल्याला विधेयक मंजूर करता येणार नाही. त्यामुळे मी आपणास विनंती करतो की, शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी या शासनाची आहे. घटनेने भारतीयांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. आपल्याला जर घटनेची पायमल्ली करावयाची होती तर आपण पदवीधर मतदारसंघामध्ये जो माणूस उभा राहतो त्यासंदर्भात आपण का विधेयक आणले नाही ? पदवीधर मतदार संघातून उभा राहणारा व्यक्ती पदवीधर असला पाहिजे यासाठी आपण का विधेयक आणले नाही? आता कुणाला निवडणूक लढवायची असेल तर त्याला दोन मुले असली पाहिजे असे आपण या ठिकाणी उदाहरण दिले आहे परंतु हा आता कायदाच झालेला आहे. आता शिक्षणाच्या बाबतीत हे विधेयक आणून ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत शिक्षण मंडळ करण्यात येणार आहे. निवडून आलेला सदस्य जर आठवी पर्यंत शिकलेला असेल तर तो आपण तयार केलेल्या कायद्यामुळे

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

श्री. पांडुरंग फुंडकर.....

मुकणार आहे. आपल्याला जर अट टाकावयाची असेल तर ती अट आपण आठवी पर्यंत करावी आणि हे विधेयक मंजूर करावे. परंतु मॅट्रीक आणि बारावी पर्यंतची अट या ठिकाणी आपल्याला टाकता येणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक आपण येथेच थांबवावे असे आमचे म्हणणे आहे. या विधेयकामध्ये जर दुरुस्ती करुन जर विधेयक आणावयाचे असेल तर ते आपण आणू शकता.

श्री. गुरुनाथ कुलकर्णी : सभापती महोदय, या ठिकाणी सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते श्री. पांडुरंग फुंडकर यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे प्रश्न उपस्थित केलेला आहे. परंतु अशा प्रकारचे हे विधेयक संमत करु नये असे घटनेत कोठेही म्हटलेले नाही.

यानंतर श्री.भारवि.....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

BGO/ KGS/ MMP/ जुन्नरे... 16:50

श्री.गुरूनाथ कुलकर्णी ....

विरोधी पक्षाला देखील देशावर राज्य करण्याची संधी मिळाली होती. तेव्हा आपण क्रांतिकारी निर्णय का घेतला नाही ? विनाकारण आपण कुठल्या वादामध्ये पडत आहोत. सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांनी जो मुद्दा येथे उपस्थित केला आहे,त्यांच्यापरिने तो ठीक आहे. तथापि, येथे घटनात्मक मुद्दा उपस्थित करता येत नाही.

श्रीमती फौजिया खान : सभापती महोदय, सदस्यांची नियुक्ती होत आहे. त्यामुळे असंविधानिक काही नाही.

श्री.जयंत प्र. पाटील : सभापती महोदय, मंत्रिमहोदयांना माहिती नाही की, सन्माननीय गृह मंत्री श्री.आर.आर.पाटील ज्या शाळेमध्ये शिकले त्या शाळेची आज काय स्थिती आहे. आज 3500 शाळा पगार आणि पेन्शन देऊ शकत नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये तरतूद केली म्हणून श्री.बागवे साहेब आपण येथे आलात. म्हणून आपण मंत्री झालात. 100 वर्षे आपण आम्हाला पुढे नेणार आहात काय ? हा खरा प्रश्न आहे. मी माननीय मंत्रिमहोदयांची माफी मागून बोलतो की, यावर आपल्याला अजून अभ्यास करावा लागेल. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये मूलभूत हक्क मागितला त्यावेळी काय झाले ? त्यावेळी विरोध करण्यात आला. जो कायदा आपण 60 वर्षानंतर करायला निघाला आहात तो आला आहे. या राज्यामध्ये अभियांत्रिक कॉलेज कोणी काढले ? मंत्रिमहोदय, आपण माझे ऐकून घ्यावे. आपण चळवळीमधून आलेल्या नाहीत. आम्ही चळवळीतून आलेले कार्यकर्ते आहोत. या राज्यात अभियांत्रिकी आणि मेडिकल कॉलेजेस वसंतदादा पाटील यांनी काढली. तो माणूस फक्त चौथी की सातवी शिकला होता. .....(अडथळा)...... मी जर काही चुकीचे बोलत असेन तर आपण हरकत घ्यावी.

उप सभापती : हे सभागृह आहे की, शाळा आहे.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, मी नम्रपणे सांगतो की, हे सर्व चुकीचे होत आहे. शिक्षणाची अट निवडणुकीमध्ये नाही. सुरूवातीलाच माझा बिलाला आक्षेप होता की, शासन नियुक्त प्रतिनिधी एवढ्या प्रमाणात पाठविण्याची आवश्यकता नाही. हा अधिकार नगरपालिकेलाच असला पाहिजे, असे माझे म्हणणे आहे. मंत्रिमहोदय, समर्थन करून ज्या पद्धतीने बोलत आहेत, ते काही

......2

असुधारित प्रत/प्रसिद्धीसाठी नाही

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती)

श्री.जयंत प्र.पाटील.....

बरोबर नाही. त्यामुळे हे विधेयक परत पाठविण्यात यावे. यासंबंधी एकमुखाने कामकाज सल्लागार समितीमध्ये चर्चा व्हावी. त्यानंतरच हे बिल यावे अशी मी विनंती करतो.

श्री.अरूण गुजराथी : सभापती महोदय, एज्युकेशन क्वालिफिकेशन असावे किंवा नसावे ही वेगळी बाब आहे. सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील येथे असा मुद्दा मांडला की, येथे घटनाबाह्य विधेयक मांडण्यात आले आहे. तेव्हा हे बिल घटनाबाह्य आहे किंवा घटनेनुसार आहे यासंबंधीचा निर्णय आपण द्यावा.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, विधि खात्याच्या सचिवांचे चुकले असेल तर ते कोर्टामध्ये सिद्ध होईल.

श्री.अरूण गुजराथी : सभापती महोदय, मी सन्माननीय सदस्यांना आपल्या मार्फत सांगू इच्छितो की, येथे निर्णय हा पीठासीन अधिकाऱ्यांनाच घ्यायचा असतो. माननीय सभापतींनी निर्णय दिल्यानंतर त्यावर आपल्याला भाष्य करता येत नाही. माननीय सभापतींचा निर्णय अंतिम असतो.

श्री.दिवाकर रावते : सभापती महोदय, असे जर असेल तर आपण ॲडव्होकेट जनरलचे मत मागवून घ्यावे.

सभापती : ॲडव्होकेट जनरल यांचे सातत्याने वरचेवर मत मागविणे योग्य आहे असे मला वाटत नाही. आता सभागृहात जो मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे, त्यावर माझ्या दालनात चर्चा करण्यासाठी मी सभागृहाची बैठक दहा मिनिटांकरिता स्थगित करीत आहे.

(सभागृहाची बैठक दुपारी 4.54 ते 5.04 पर्यंत स्थगित झाली.)

यानंतर श्री.सरफरे .....

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(सभापतीस्थानी तालिका सभापती ॲड. अनिल परब)

तालिका सभापती : सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात येत आहे.

(सभागृहाची बैठक 5 वाजून 04 मिनिटांनी, 10 मिनिटांकरिता स्थगित करण्यात आली.)

(5.04. ते 5.14 पर्यंत सभागृह स्थगित)

(यानंतर सौ. रणदिवे)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(स्थगितीनंतर)

सभापतीस्थानी -माननीय सभापती

सभापती : याठिकाणी सन्माननीय सदस्य श्री.अरुण गुजराथी यांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे. त्या मुद्याच्या अनुषंगाने खरे म्हटले तर विधानसभेमध्ये जेव्हा हे बिल इन्ट्रोड्युस झाले, चर्चेसाठी आले, त्यावेळेला या मुद्याचा परामर्श घेणे आवश्यक होते. तसेच ज्यावेळी विधान परिषदेमध्ये हे बिल इन्ट्रोडक्शनसाठी आले, त्यावेळी सुध्दा अशा पध्दतीने अल्ट्रा व्हायरस आहे की नाही या अनुषंगाने भाष्य झाले असते तर बरे झाले असते. सन्माननीय सदस्य श्री.अरुण गुजराथी यांनी मला याबाबत सांगितले. याबाबतीत रुलींग देत असताना एकंदर या सभागृहातील दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांच्या भावना बघितल्या तर मला असे वाटते की, मी माझे रुलींग आज न देता सोमवारी देईन. या बिलावरील उर्वरित चर्चा आहे, ती आपण सोमवारी करु या.

श्री.विक्रम काळे : सभापती महोदय, बिलावर चर्चा करावयाची आहे.

सभापती : मी या बिलावरील चर्चा सोमवारी ठेवत आहे आणि या बिलातील व्हायरसच्या दृष्टीने किंवा सन्माननीय सदस्य श्री.अरुण गुजराथी यांनी जो मुद्दा मांडला आहे, त्याबाबतचा निर्णय मी सोमवारी देतो.

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, आपण निर्णय देण्यापूवी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे मला सांगावयाचे आहे.

सभापती : याठिकाणी हा मुद्दा निर्णयासाठी आल्यानंतर त्या अनुषंगाने मी 10-15 मिनिटांसाठी सभागृह तहकूब करुन या विषयाच्या अनुषंगाने कायदेशीर माहिती घेतली. पण मला अद्याप त्याबाबत पूर्ण माहिती मिळालेली नसल्यामुळे मी माझा निर्णय सोमवारपर्यंत तहकूब ठेवलेला आहे.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, उद्यापासून तीन दिवस सुटी आहे.आता नियम 260 अन्वयेच्या प्रस्तावावरील चर्चा पुढे सुरु होणार आहे. सन्माननीय सदस्यांना आपापल्या गावी जावयाचे आहे. त्यामुळे ही चर्चा सोमवारी घेण्यात यावी..

काही सन्माननीय सदस्य : सभापती महोदय, हा विषय सोमवारी घ्यावा आणि माननीय मंत्री महोदयांचे उत्तर देखील सोमवारी ठेवावे.

श्री.जयंत प्र.पाटील : सभापती महोदय, आता 5.30 वाजलेले आहेत.

. . . .3जे-2

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

(काही सन्माननीय सदस्य एकदम बोलतात.)

सभापती : माननीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटीलसाहेब, काय करावयाचे ?

(काही सन्माननीय सदस्य एकदम बोलतात.)

डॉ.दीपक सावंत : सभापती महोदय, गृह विभागाशी संबंधित चर्चेच्या संदर्भात माननीय मंत्री श्री.आर.आर.पाटीलसाहेब यांनी उत्तराचे भाषण करावे.

सभापती : मी याबाबत आज सकाळी निर्णय दिला आहे. पण माझे मत असे होते की,आजच्या कामकाज पत्रिकेवरील अनु.क्र.8 वर दाखविण्यात आलेली गडचिरोली जिल्हयातील नक्षलवाद्यांच्या कारवायांच्या संबंधातील जी चर्चा आहे, त्याबाबत एक तास चर्चा करु आणि जर माननीय मंत्री महोदयांचे उत्तर पूर्ण झाले तर ती चर्चा सुध्दा आज पूर्ण होऊ शकते.

श्री.पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, आता 5.30 वाजत आहेत आणि सन्माननीय सदस्यांना गावी जाण्यासाठी गाड्या पकडावयाच्या आहेत.

काही सन्माननीय सदस्य : सभापती महोदय, सोमवारी सकाळी चर्चा घ्यावी.

सभापती : जर आपण सोमवारी सकाळी चर्चा घेतली तर सन्माननीय सदस्य श्री.कपिल पाटील यांचा प्रस्ताव . . . .

श्री.कपिल पाटील : सभापती महोदय, तो मंगळवारी घेऊ.

सभापती : "राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या" संदर्भातील जी चर्चा आहे, ती अपूर्ण आहे. त्या व्यतिरिक्त आज "गडचिरोली जिल्हयातील नक्षलवाद्यांच्या कारवायांच्या अनुषंगाने" चर्चा होणार होती. म्हणून सकाळी माननीय गृह मंत्री श्री.आर.आर.पाटीलसाहेब, सन्माननीय विरोधी पक्षनेते श्री.पांडुरंग फुंडकरसाहेब, सन्माननीय सदस्य श्री.दिवाकरजी रावते यांच्याबरोबर चर्चा करुन असा निर्णय घेतला होता की, माननीय गृहमंत्री श्री.आर.आर.पाटीलसाहेब यांचे उत्तर पूर्ण झाल्यानंतर आजच्या कामकाज पत्रिकेवर अनु.क्र.आठ वर दाखविण्यात आलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांच्या कारवायांच्या अनुषंगाने जी चर्चा आहे, ती देखील पूर्ण करु.

यानंतर कु.थोरात . . . .

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही

सभापती .....

या दोन्ही चर्चेला एकत्रित उत्तर देण्यात येईल असा आपला निर्णय झालेला होता. परंतु मधल्या चर्चेच्या अनुषंगाने एक ते दीड तास जास्त गेला. त्यामुळे या चर्चा पुढे ढकलावयाच्या म्हटले तरी पुन्हा सोमवारी या चर्चा घेता येणार नाहीत. त्यामुळे ज्यावेळेला वेळ मिळेल त्यावेळेला त्या घेण्यात येतील..

श्री. दिवाकर रावते : सभापती महोदय, ही चर्चा आता आठ वाजेपर्यंत चालू ठेवण्यास आमची हरकत नाही. परंतु बऱ्याच सन्माननीय सदस्यांना संध्याकाळच्या गाडीने आपापल्या गावी जावयाचे असल्यामुळे ही चर्चा सोमवारी घेण्यात यावी.

श्री. आर.आर.पाटील : सभापती महोदय, सोमवारी 68 क्रमांच्या विधेयकावर चर्चा घेण्यात यावी व नियम 260 अन्वयेच्या प्रस्तावावरील चर्चा मंगळवारी घेण्यात यावी.

श्री. पांडुरंग फुंडकर : सभापती महोदय, नियम 260 अन्वयेच्या चर्चा मंगळवारी घेण्यात याव्यात.

सभापती : ठीक आहे.

सभागृहापुढील कामकाज संपलेले आहे. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होऊन सोमवार,दिनांक 5 एप्रिल, 2010 रोजी सकाळी 11.30 वाजता पुन: भरेल. सकाळी 11.30 ते 1.00 वाजेपर्यंत विशेष बैठक होईल आणि त्यानंतर दुपारी 1 वाजून 15 मिनिटांनी सभागृहाची नियमित बैठक भरेल.

(सभागृहाची बैठक सायंकाळी 5 वाजून 21 मिनिटांनी सोमवार, दिनांक 5 एप्रिल, 2010 रोजीच्या सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत स्थगित झाली.)

असुधारित प्रत / प्रसिद्धीसाठी नाही